



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 54]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 28, 2015/फाल्गुन 9, 1936

No. 54]

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 28, 2015/PHALGUNA 9, 1936

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बजट अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2015

फा. सं. 2 (2)/2015-बी (डी).—निम्नलिखित सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

बजट 2015-2016

वित्त मंत्री अरुण जेटली का भाषण

28 फरवरी, 2015

अध्यक्ष महोदया,

- मैं वर्ष 2015-16 का बजट प्रस्तुत करता हूँ।
- मैं यह बजट एक ऐसे आर्थिक माहौल में प्रस्तुत कर रहा हूँ जो अभी हाल ही में बीते दिनों के आर्थिक माहौल की तुलना में अधिक सकारात्मक है। जबकि विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाएं गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही हैं, वहीं भारत एक बार फिर से विकास के पथ पर तीव्र गति से अग्रसर हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैश्विक आर्थिक विकास के संबंध में अपना पहले किया गया पूर्वानुमान 0.3% कम कर दिया है। विश्व व्यापार संगठन ने, विश्व व्यापार विकास का अपना पूर्वानुमान 5.3% से घटाकर 4% कर दिया

है। तथापि भारत के संबंध में पहले लगाया पूर्वानुमान या तो बढ़ा दिया गया है या उसमें कोई कमी किए बिना, उसे पूर्व के स्तर पर ही रखा गया है। अध्यक्ष महोदया, हमने आर्थिक विकास की प्रक्रिया में राज्यों को भी समान भागीदार के रूप में सम्मिलित किया है। राज्यों को आर्थिक रूप से इतना अधिक सशक्त बनाया गया है जितना पहले कभी नहीं बनाया गया था। मुझे विश्वास है कि केंद्र अथवा राज्य सरकारों में से किसी के भी द्वारा किए गए व्यय का प्रत्येक रुपया देश में रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास का पथ प्रशस्त करके, लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में योगदान करेगा।

3. पिछले नौ महीनों के दौरान, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए सरकार ने अर्थव्यवस्था के विकास की गति में तेजी लाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण उपाय किए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता फिर से लौटी है। दुनिया के देश मानने लगे हैं कि यह समय भारत के लिए प्रगति के पथ पर उड़ान भरने का समय है।

कुछ तो फूल खिलाए हमने, और कुछ फूल खिलाने हैं,
मुश्किल यह है बाग में अब तक, काँटे कई पुराने हैं।

4. हालांकि केंद्रीय बजट अनिवार्य रूप से लोक वित्त का लेखा विवरण है, किंतु पारंपरिक रूप से यह भारत की आर्थिक नीति की दिशा और गति की रूपरेखा बताने का एक विशेष अवसर प्रदान करता है। अतः मेरे प्रस्तावों में विकास की गति को तीव्रतर बनाने, निवेश में वृद्धि करने, निवेश में और विकास प्रक्रिया के फायदे को देश के आम आदमी, महिला, युवा और बच्चों तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इनके जीवन-स्तर में सुधार किया

जाना है। यह वह पथ है जिस पर हम पूरे इरादे से और बिना रुके चलते रहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने भी अक्सर कहा है कि हमारी सरकार चौबीसों घंटे और पूरे वर्ष काम करने वाली सरकार है।

5. महोदया, मैं देश में हमारी सरकार द्वारा कामगाज शुरू किए जाने के बाद से, भारतीय अर्थव्यवस्था में आए बदलावों का जिक्र करना चाहता हूँ। नवंबर 2012 में सीपीआई मुद्रास्फीति 11.2 प्रतिशत थी, 2013-14 की पहली तिमाही तक चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4.6 प्रतिशत पर पहुँच गया था तथा मार्च, 2014 तक सामान्य विदेशी निवेश अंतर्वाह 15 बिलियन अमरीकी डालर था। हमें एक ऐसी भावना विरासत में मिली जो मैं कहना चाहता हूँ कि दुर्भाग्य और निराशा से ओत-प्रोत थी तथा निवेशक समुदाय का हम पर भरोसा प्रायः खत्म हो गया था।

6. तब से, हमने एक लंबी दूरा तय की है। नवीनतम सीपीआई मुद्रास्फीति दर 5.1 प्रतिशत तथा थोक मूल्य मुद्रास्फीति ऋणात्मक स्तर पर है; इस वर्ष चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 1.3 प्रतिशत से कम रहने की संभावना है; नई श्रृंखला के आधार पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 7.4 प्रतिशत हो जाने की उम्मीद है जिससे भारत विश्व में सर्वाधिक तेजी से विकसित हो रही विशाल अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। अप्रैल, 2014 के बाद से देश में लगभग 55 बिलियन अमरीकी डालर का विदेशी निवेश अंतर्वाह हुआ है जिससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 340 बिलियन अमरीकी डालर के रिकार्ड स्तर पर पहुँच गया है। रुपया विश्व के प्रमुख देशों की मुद्राओं की तुलना में पहले से 6.4 प्रतिशत अधिक मजबूत हुआ है। हमारा पूंजी बाजार विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों में दूसरा सबसे अच्छा निष्पादन करने वाला बाजार था। संक्षेप में, अध्यक्ष महोदया, हमारी अर्थव्यवस्था में नाटकीय ढंग से आमूल-चूल बदलाव आया है। हमने अपने वृहत-आर्थिक स्थायित्व को फिर से प्राप्त किया है तथा स्थायी तौर पर गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और दो अंकों में संपोषणीय आर्थिक विकास संबंधी परिस्थितियाँ उत्पन्न की हैं। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेशक हमारी ओर नए हित और आशा के साथ देख रहे हैं।

7. अध्यक्ष महोदया, इन चुनौतियों के प्रति विशेष रूप से जागृत होने के साथ ही ये चुनौतियाँ हमें आशावादी बने रहने के लिए भी प्रेरित करती हैं। सभी प्रतिकूल परिस्थितियों के मौजूद होने के बावजूद, मेरा मानना है कि ऐसी स्थिति इस कारण उत्पन्न हुई कि हमने उसे उत्पन्न होने दिया। भारत की जनता ने शीघ्र बदलाव, तीव्र विकास और उच्चतम स्तर की पारदर्शिता को स्थापित करने के लिए हमें सत्ता सौंपी है। जनता चाहती थी कि देश से घोटाला, स्कैंडल और भ्रष्टाचार का राज समाप्त हो। वह ऐसी सरकार चाहती थी जिस पर वह विश्वास कर सके। हम उस विश्वास पर खरे उतरे हैं।

8. हमारे कार्य मूल अथवा वृहत्-आर्थिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं हैं। इनका प्रसार सामाजिक, सांस्कृतिक और

प्रशासनिक क्षेत्रों में भी है। प्राकृतिक संसाधनों के आबंटन; वित्तीय समावेशन; आम अदमी के स्वास्थ्य और स्वच्छता; बालिकाओं और उनकी शिक्षा; युवाओं के लिए रोजगार; उन्नत और अप्रतिकूल कर प्रशासन; प्रसुविधाओं की प्रभावी सुपदर्शी; निवेश और रोजगार सृजन; श्रमिकों के कल्याण; कृषि उत्पादकता और कृषि आय बढ़ाने; विद्युत; डिजिटल कनेक्टिविटी; हमारे युवाओं का कौशल विकास करने; सरकार में प्रभावी और बेहतर कार्य संस्कृति; व्यवसाय करने को सुगम बनाने; उत्तर-पूर्वी राज्यों को मुख्यधारा में लाने और हमारे राष्ट्रीय गर्व और संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए कार्य किए गए हैं। मैं, इनका ब्यौरा इस भाषण के अनुबंध में दे रहा हूँ।

9. अध्यक्ष महोदया, हमारे द्वारा किए गए कार्यों में से मैं, तीन उपलब्धियों के बारे में बताना चाहूँगा। ये हमारी सरकार की विशेषता और दृढ़ विश्वास को दर्शाती हैं। पहली उपलब्धि जन धन योजना की सफलता है। वित्तीय समावेशन के बारे में दशकों से बातें की जा रही हैं। किसने सोचा होगा कि 100 दिनों की अल्प-अवधि में, 12.5 करोड़ से अधिक परिवार वित्तीय मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे? दूसरी उपलब्धि कोयला नीलामियाँ रहीं। पहले राज्यों को केवल रायल्टी के लाभ मिलते थे। अब, हमारी पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया से कोयला वाले राज्यों को कई लाख या करोड़ों रुपए प्राप्त होंगे। ये राज्य इनका उपयोग लंबे समय से प्रतीक्षित सामुदायिक आस्तियों के सृजन और अपने लोगों के कल्याण के लिए कर सकते हैं।

10. तीसरी उपलब्धि 'स्वच्छ भारत' है। भारत का पुनरुद्धार करने के लिए इस अभियान को आंदोलन में बदलने में हम कामयाब रहे हैं। उदाहरण के लिए, मैं, 2014-15 में निर्मित 50 लाख शौचालयों की बात करता हूँ और मैं, इस महान सदन के सदस्यों को आश्चर्य भी करता हूँ कि हम छह करोड़ शौचालयों का निर्माण-कार्य करने के लक्ष्य को, वास्तव में, प्राप्त कर लेंगे। महोदया, स्वच्छ भारत केवल स्वास्थ्य और स्वच्छता का कार्यक्रम नहीं है बल्कि दूरदर्शिता से देखा जाए तो यह एक निवारक स्वास्थ्य देखभाल और जागरूकता निर्माण कार्यक्रम है।

11. हमने अब आर्थिक परिस्थितियों को अत्यधिक बेहतर बनाने के लिए दो सुधार कार्यक्रमों को प्रारंभ किया है। ये वस्तु एवं सेवा कर और प्रसुविधाओं के प्रत्यक्ष अंतरण के क्रियान्वयन के लिए आर्थिक समीक्षा में वर्णित त्रिसूत्री योजनाएं, जन धन, आधार और मोबाइल - हैं। 1 अप्रैल, 2016 तक वस्तु एवं सेवा कर से अत्याधुनिक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली आएगी। ये त्रिसूत्री सुविधाएं हमें क्षतिरहित, सुलक्षित और नकदी रहित तरीके से प्रसुविधाओं का अंतरण कर सकेंगी।

12. अध्यक्ष महोदया, मेरी सरकार की मुख्य उपलब्धि, महंगाई पर काबू पाना रही है। मेरे विचार से, महंगाई में यह कमी संरचनात्मक परिवर्तन को परिलक्षित करती है। हमें आशा है कि आगे चलकर, इस वर्ष की समाप्ति पर उपभोक्ता मूल्य

सूचकांक मुद्रास्फीति लगभग 5 प्रतिशत रहेगी। इससे मौद्रिक नीति को और सहज बनाया जा सकेगा।

13. यह सुनिश्चित करने के लिए कि मुद्रास्फीति पर हमारी जीत संस्थानिक है। हमने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मौद्रिक नीति रूपरेखा करार किया है। मैंने, 2014-15 के बजट भाषण में इसका वादा किया था। इस रूपरेखा में मुद्रास्फीति को 6% से नीचे रखने के लक्ष्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। मौद्रिक नीति समिति का गठन करने के लिए, हम, इस वर्ष, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव लाएंगे।

14. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने, हाल ही में, सकल घरेलू उत्पाद के लिए नई श्रृंखला जारी की है। इस नई श्रृंखला में पुरानी श्रृंखला की तुलना में कई बदलाव किये गए हैं। नई श्रृंखला के आधार पर, 2014-15 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की अनुमानित विकास दर 7.4 % है। वर्ष 2015-16 में, विकास दर 8 से 8.5% के बीच रहने की उम्मीद है। दो अंकीय विकास दर हासिल करने का लक्ष्य बहुत जल्दी पूरा होता दिखाई दे रहा है।

15. मैं, अब, हमारे सामने जो कार्य हैं उनका जिक्र करता हूँ। अब से पूर्व, सात दशकों में, हमने सामाजिक और आर्थिक सूचकों के संबंध में प्रतिशतताओं और शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या के अनुसार कार्य किए हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कहीं भी वृद्धिशील परिवर्तन होने नहीं जा रहे हैं। हमें बड़े परिवर्तन के बारे में विचार करना होगा।

16. वर्ष 2022 में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय सरकार के मार्गदर्शन और राज्य सरकारों के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री द्वारा उल्लिखित 'टीम इंडिया' के विजन में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (i) भारत में प्रत्येक परिवार के लिए घर हो। 2022 तक 'सबके लिए घर' के लिए टीम इंडिया को शहरी क्षेत्रों में 2 करोड़ घरों और ग्रामीण क्षेत्रों में 4 करोड़ घरों का निर्माण करने की आवश्यकता होगी।
- (ii) देश के प्रत्येक घर में 24 घंटे बिजली आपूर्ति, स्वच्छ पेयजल, शौचालय जैसी मूल सुविधाएं होनी चाहिए और वह सड़क से जुड़ा हो।
- (iii) प्रत्येक परिवार से कम से कम एक सदस्य की आजीविका के साधनों और रोजगार अथवा आर्थिक अवसर तक पहुँच होनी चाहिए ताकि वह अपना और अपने परिवार का जीवन स्तर सुधार सके।
- (iv) गरीबी में पर्याप्त कमी लायी जाए। हमारी सभी स्कीमें गरीबों पर केन्द्रित होनी चाहिए। गरीबी उन्मूलन के इस कार्य के लिए हममें से प्रत्येक को स्वयं प्रतिबद्धता दिखानी होगी।

- (v) देश में शेष 20,000 गांवों का 2020 तक विद्युतीकरण किया जाए। इसमें ऑफ-ग्रिड सौर विद्युत उत्पादन शामिल है।
- (vi) सड़क मार्ग से न जुड़ी 1,78,000 बस्तियों में से प्रत्येक को बारहमासी सड़कों से जोड़ना। इसके लिए वर्तमान में निर्माणाधीन 1,00,000 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण-कार्य पूरा करने और अन्य 1,00,000 किलोमीटर की सड़क की मंजूरी और निर्माण की आवश्यकता होगी।
- (vii) अच्छी सेहत जीवन-स्तर सुधारने और व्यक्ति की उत्पादकता दोनों तथा अपने परिवार की सहायता करने की उसकी सामर्थ्य के लिए आवश्यक है। प्रत्येक गांव और शहर में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना पूर्णतः आवश्यक है।
- (viii) अपने युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए उन्हें शिक्षित करना और कौशल संपन्न बनाना एक ऐसी वेदी है जिसके सामने हम सबको नतमस्तक होना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक बच्चे के लिए 5 किमी. के भीतर एक सीनियर सेकेन्डरी स्कूल हो, हमें 80,000 माध्यमिक विद्यालयों का उन्नयन करने तथा अन्य 75,000 जूनियर/मिडल स्तर तक के विद्यालयों का स्तर बढ़ाकर सीनियर माध्यमिक स्तर तक करने की आवश्यकता है। साथ ही, हमें यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षा में गुणवत्ता तथा शिक्षण परिणामों की दृष्टि से सुधार हो।
- (ix) ग्रामीण क्षेत्रों के कल्याण के लिए कृषि उत्पादकता में वृद्धि और कृषि उपजों के लिए वाजिब दाम प्राप्त होना आवश्यक है। हमें सिंचित क्षेत्रों को बढ़ाने, मौजूदा सिंचाई प्रणालियों की क्षमता में सुधार लाने तथा मूल्य वर्धन और कृषि से होने वाली आय में वृद्धि करने तथा कृषि-उत्पादों के लिए उचित कीमतें सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।
- (x) संचार की दृष्टि से, गांवों और शहरों के बीच भेद हमें अब स्वीकार्य नहीं है। हमें भेदभाव के बगैर सभी गांवों में संचार व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- (xi) हमारी दो-तिहाई आबादी 35 वर्ष से कम उम्र वालों की है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे युवाओं को उचित रोजगार प्राप्त हो, हमें, भारत को दुनिया का विनिर्माण केन्द्र बनाने के उद्देश्य को लेकर चलना होगा। स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया कार्यक्रम इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए गए हैं।
- (xii) हमें भारत में उद्यमशीलता की भावना को भी प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना है तथा नए उद्योग को शुरु

करने में सहायता करनी है। इस प्रकार, हमारे युवा रोजगार तलाशने वालों के स्थान पर रोजगार देने वाले बन जाएंगे।

- (xiii) हमारे देश के पूर्वी एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र कई मोर्चों पर विकास में पिछड़ रहे हैं। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वे भी देश के शेष भागों के समतुल्य हों।

17. भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ तक, हमारी स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव करीब पहुँच चुका होगा। हमें उपर्युक्त सभी लक्ष्य प्राप्त करने हैं ताकि भारत एक समृद्ध राष्ट्र के साथ-साथ एक परोपकारी विश्व शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना सके। अपने स्वतंत्रता सेनानियों को यह हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

महत्वपूर्ण भावी चुनौतियाँ

18. अध्यक्ष महोदया, यह मैं पहले ही बता चुका हूँ कि चुनौतियों को लेकर मैं भी चिन्तित हूँ। मेरे विचार से पांच मुख्य चुनौतियाँ हैं। कृषि संबंधी आय दबावग्रस्त है। हमारी दूसरी चिन्ता है अवसंरचना में निवेश बढ़ाना। सरकारी-निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से अवसंरचना में निवेश की स्थिति अभी भी खराब है, निवेश को उत्प्रेरित करने के लिए, सरकारी क्षेत्र को कदम उठाने की आवश्यकता है।

19. हमारी तीसरी प्रमुख चुनौती यह है कि नए सकल घरेलू उत्पाद आंकड़ों के अनुसार, विनिर्माण, सकल घरेलू उत्पाद के 18% से गिरकर 17% रह गया है; और विनिर्माण निर्यात, सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 10% पर स्थिर रहा है। इस प्रकार, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य रोजगार के सृजन द्वारा इस चुनौती से निपटना है।

20. चौथी चुनौती यह है कि हमें, सरकारी निवेश के लिए बढ़ती मांगों के बावजूद, राजकोषीय अनुशासन की आवश्यकता को ध्यान में रखने की जरूरत है। सरकारी संघवाद की सच्ची भावना को ध्यान में रखते हुए, हमने करों के विभाज्य कोष (पूल) का 42% हिस्सा राज्यों को अंतरित करना स्वीकार कर लिया है। स्थानीय निकायों को दिया जाने वाला अनुदान या राजस्व घाटा इन अनुदानों में शामिल नहीं है, जो इसके अतिरिक्त हैं। जैसाकि महान सदन के सदस्यों को पता ही है कि यह एक अप्रत्याशित वृद्धि है। इससे राज्यों को अधिक संसाधन मिलने से वे सशक्त हो जाएंगे। राज्यों को 2014-15 के संशोधित अनुमानों के अनुसार ₹3.38 लाख करोड़ के अंतरण की तुलना में, 2015-16 में यह अंतरण ₹5.24 लाख करोड़ होगा। अनुदानों और आयोजनागत राशि के अंतरण के रूप में ₹3.04 लाख करोड़ रूपए की अतिरिक्त राशि अंतरित की जाएगी। इस प्रकार, राज्यों को कुल अंतरण केंद्र के निवल कर राजस्व का लगभग 62% हो जाएगा।

21. केन्द्र के लिए घटती परिणामी राजकोषीय गुंजाइश के बावजूद, सरकार ने सड़कों सहित कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य,

मनरेगा, ग्रामीण अवसंरचना जैसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को सहायता जारी रखने का निश्चय किया है। गरीबों और उपेक्षित लोगों के उद्देश्य से बनाए-गए कार्यक्रम जारी रहेंगे।

22. अपनी राजकोषीय स्थिति में न केवल गिरावट आयी है अपितु यह प्रायः खत्म सी हो गयी है। मुझे राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखने की पांचवी चुनौती का मुकाबला करना है। इस वर्ष 11.5 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि सांकेतिक अर्थ में लगभग 2 प्रतिशत कम थी जिसके कारण मुद्रास्फीति की दर कम होना है। परिणामतः, कर में उछाल भी काफी कम रहा। महोदया, इसके बावजूद, मैंने अपना वचन पूरा किया है, और हम विरासत में प्राप्त सकल घरेलू उत्पाद के 4.1 प्रतिशत के राजकोषीय घाटा के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। अध्यक्ष महोदया, मुझे गरीबी में कमी लाने और उसे दूर करने के लिए इन चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता है।

राजकोषीय रूपरेखा

23. अध्यक्ष महोदया, मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूँ कि मेरी सरकार, सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत के मध्यावधिक लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास के प्रति कृत संकल्प है। किंतु इस प्रयास में सरकारी निवेश में वृद्धि करने की आवश्यकता पर विचार करना होगा। सं.अ. से अधिक कुल अतिरिक्त सरकारी निवेश ₹1.25 लाख करोड़ निर्धारित किया गया है, जिसमें से ₹70,000 करोड़ बजटीय परिव्यय से पूंजीगत व्यय होगा। हमें अत्यधिक घट गई राजकोषीय गुंजाइश, वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने से उत्पन्न होने वाली अनिश्चितताओं; और 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के कारण पड़ने वाले संभावित बोझ पर भी विचार करना होगा। मेरे विचार में, राजकोषीय समेकन हेतु चक्रीय तौर पर पूर्व निर्धारित समय सारणी की जल्दबाजी अथवा इस पर बल देना विकास के पक्ष में नहीं होगा। अर्थव्यवस्था सुधारों के साथ, राजकोषीय समेकन की गति में तेजी लाने का दबाव कम हो गया है। इन परिस्थितियों में, मैं 3% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पहले से परिकल्पित दो वर्षों के बजाय 3 वर्षों में पूरा करूंगा। इस प्रकार, अगले तीन वर्षों के लिए मेरे लक्ष्य हैं: 2015-16 के लिए 3.9 प्रतिशत; 2016-17 के लिए 3.5 प्रतिशत; और 2017-18 के लिए 3.0 प्रतिशत। अतिरिक्त राजकोषीय गुंजाइश में अवसंरचना में निवेश के वित्तपोषण हेतु प्रयोग में लायी जाएगी।

24. तदनुसार, मैं, एफआरबीएम अधिनियम के प्रति वित्त विधेयक में संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूँ।

25. अध्यक्ष महोदया, मैं एक आशावादी टिप्पणी के साथ राजकोषीय रूपरेखा पर विचार-विमर्श को विराम देना चाहता हूँ। जबकि संरचनात्मक परिवर्तन हुआ है, किन्तु रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन और संरचना निर्माण की समग्र स्थिति निर्बाध रही है; वस्तुतः यह स्थिति इस वर्ष और प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष में जारी रहेगी क्योंकि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के कर राजस्व में इजाफा होगा। लोक वित्त के इस राष्ट्रीय

परिप्रेक्ष्य से, न केवल राजकोषीय समेकन की गाड़ी पटरी पर है अपितु इससे समग्र रूप में सरकारों के कुल सरकारी व्यय में सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होने की उम्मीद की जा सकती है।

26. अध्यक्ष महोदया, आप देखेंगी कि बजट में विनिवेश संबंधी आंकड़े अत्यधिक स्पष्टता के साथ प्रदर्शित किए गए हैं। इसमें घाटा उठाने वाली इकाइयों में विनिवेश और कुछ स्ट्रेटेजिक विनिवेश, दोनों ही शामिल होंगे।

सु-शासन

27. अध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार भारतीय के रूप में अपने संकल्प में एक न्यायप्रिय तथा अनुकंपा से परिपूर्ण देश के रूप में अपने पूर्व के उत्कर्ष को प्राप्त करने के लिए कृत संकल्प है। विगत में अच्छे इरादों के साथ प्रारंभ की गई स्कीमें प्रायः अपने लक्ष्य पूरे नहीं कर सकी हैं, कमियों के जाल में उलझ गई हैं और इन पर अक्षमता का ठप्पा लग गया है। यही स्थिति सब्सिडियों की भी है। सब्सिडियों की जरूरत गरीबों और वंचितों के लिए होती है। हमें सब्सिडी सुपुर्दगी की सुलक्षित प्रणाली की आवश्यकता है। हमें सब्सिडी क्षतियों को कम करने की आवश्यकता है न कि सब्सिडियों को ही समाप्त करने की। हम, इस दृष्टिकोण पर आधारित सब्सिडियों को युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध हैं।

28. हम उस पथ पर चल पड़े हैं। अधिकतर छात्रवृत्ति स्कीमों में शुरू किए गए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लाभार्थियों की मौजूदा संख्या 1 करोड़ से बढ़ाकर 10.3 करोड़ करने के लिए इसका और विस्तार किया जाएगा। इसी प्रकार, 11.5 करोड़ एलपीजी उपभोक्ताओं को ₹6,335 करोड़ का प्रत्यक्ष अंतरण किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सदन के सदस्यों जैसे शीर्ष कर वर्ग वाले धनी व्यक्ति और जो वास्तव में गरीब व्यक्तियों के कल्याण के प्रति वस्तुतः चिंतित हैं, स्वेच्छा से अपनी एलपीजी सब्सिडी छोड़ देंगे।

कृषि

29. हमारे किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता गहरी है। हमने कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण दो बड़े कारकों अर्थात् मृदा और पानी के समाधान के लिए पहले ही प्रमुख उपाय किए हैं। सतत आधार पर मृदा उर्वरता में सुधार लाने के लिए, महत्वाकांक्षी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम शुरू की गई है। मृदा स्वास्थ्य सुधारने के लिए, मैं कृषि मंत्रालय की परंपरागत कृषि विकास योजना के वित्तपोषण और पूर्ण सहायता का भी प्रस्ताव करता हूं। प्रधान मंत्री ग्राम सिंचाई योजना प्रति बूंद अधिक फसल की व्यवस्था करने के लिए प्रत्येक किसान के खेत में सिंचाई करने और जल घर दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से बनायी गयी है। मैं, सूक्ष्म सिंचाई, जलसंभर विकास और प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना की सहायता हेतु ₹ 5,300 करोड़ आवंटित कर रहा हूं। मैं राज्यों से आग्रह करता

हूं कि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में भरपूर सहयोग दें।

30. छोटे और सीमांत किसानों पर विशेष ध्यान देते हुए, प्रभावी और निर्बाध कृषि ऋण की सहायता से कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए। मैं, 2015-16 में नाबार्ड में स्थापित ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष की निधियों में ₹25,000 करोड़, दीर्घावधिक ग्रामीण ऋण कोष में ₹15,000 करोड़, अल्पावधिक सहकारी ग्रामीण ऋण पुनर्वित्त निधि हेतु ₹45,000 करोड़ और अल्पावधिक आरआरबी पुनर्वित्त निधि के लिए ₹15,000 करोड़ आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं।

31. कृषि ऋण हमारे मेहनतकश किसानों के प्रयासों को सहारा देते हैं। इसलिए मैंने 2015-16 के दौरान ₹8.5 लाख करोड़ के ऋण का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि बैंक यह लक्ष्य पार कर लेंगे।

32. हमारी सरकार मनरेगा के जरिए रोजगार में मदद करने के प्रति वचनबद्ध है। हम सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी गरीब रोजगार के बगैर न रह जाए। हम मनरेगा के अंतर्गत कार्यों की गुणवत्ता और प्रभावशीलता में सुधार लाने पर ध्यान देंगे। मैंने इस कार्यक्रम के लिए ₹34,699 करोड़ का आरंभिक आवंटन किया है।

33. हालांकि, किसान अब स्थानीय व्यापारी के शिकंजे में नहीं हैं परन्तु उसके उत्पाद को अभी भी सर्वोत्तम राष्ट्रीय कीमत नहीं मिलती है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि हम राष्ट्रीय कृषि बाजार सृजित करें जिससे मूल्य वृद्धियों को कम करने के अनुषंगी लाभ होंगे। मैं, इस वर्ष एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार के सृजन हेतु नीति में राज्यों के साथ कार्य करने का इच्छुक हूं।

अनिधिबद्ध का निधियन

34. अध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि विकास से समावेशी विकास होगा। जबकि बड़े कारपोरेट और कारोबारी कंपनियों को भूमिका निभानी है। इसे अधिकतम रोजगार सृजन में लगे अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा संपूरित करना होगा। लगभग 5.77 करोड़ छोटे व्यवसाय वाली यूनिटें हैं और अधिकतर व्यक्ति स्वामित्व की हैं तथा छोटे विनिर्माण, व्यापार अथवा सेवा व्यवसाय चलाते हैं और इनमें 62% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के स्वामित्व में हैं। ये पिरामिड के सबसे निचले पायदान पर हैं। ये मेहनतकश उद्यमी असंभव तो नहीं, पर मुश्किल से ऋण की औपचारिक प्रणालियों तक पहुंच पाते हैं। मैं, इसलिए, 20,000 करोड़ की निधि और 3,000 करोड़ की गारंटी निधि से सूक्ष्म यूनिट विकास पुनर्वित्त एजेंसी (मुद्रा) बैंक सृजित करने का प्रस्ताव करता हूं। मुद्रा बैंक सभी सूक्ष्म वित्त संस्थाओं, जो ऐसी छोटी कारोबार इकाइयों को उधार देने के व्यवसाय में लगी हैं जो प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के जरिए संचालित और पुनर्वित्तपोषण करेगा। उधार देने में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के उद्योगों को

प्राथमिकता दी जाएगी। ये उपाय युवा, शिक्षित अथवा कुशल श्रमिकों का भरोसा बढ़ाएंगे जो पहली पीढ़ी के उद्यमों बनने की इच्छा रखने में समर्थ होंगे; विद्यमान छोटे व्यवसायी भी अपने कार्यकलापों का विस्तार करने में समर्थ होंगे। जिस प्रकार हम बिना बैंक वालों को बैंक वाला बना रहे हैं उसी तरह हम अनिधिबद्ध को निबद्ध कर रहे हैं।

35. दीर्घकालिक प्राप्य संग्रहण चक्रों के कारण किसी सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम की कार्यशील पूंजी जरूरत का महत्वपूर्ण भाग उत्पन्न होता है। हम ट्रेड डिस्काउंटिंग सिस्टम (ट्रेड्स) की स्थापना करने की प्रक्रिया में हैं जो बहुविध फाइनेंसर्स के जरिए कारपोरेट और अन्य क्रेताओं से सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों के व्यापार प्राप्यों के वित्तपोषण सुसाध्य बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म होगा। यह महत्वपूर्ण रूप से इस उद्यम क्षेत्र में नकदी में सुधार लाएगा।

36. रेशम औद्योगिक कंपनी अधिनियम तथा औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण ब्यूरो ये लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहे हैं। हम वित्त वर्ष 2015-16 में विस्तृत दिवालियापन कोर्ड लाएंगे। जो वैश्विक मानक पूरे करेगा और आवश्यक न्याय क्षमता की व्यवस्था करेगा।

37. सरकार औपचारिक वित्तीय प्रणाली तक लोगों की पहुंच बढ़ाने के प्रति वचनबद्ध है। इस संदर्भ में, सरकार देश भर में फैले सभी गावों में मौजूद, 1,54,000 स्थानों पर विशाल डाक नेटवर्क का उपयोग करना चाहती है। मुझे आशा है कि डाक विभाग अपने उद्यम से भुगतान बैंक को सफल बनाएंगे ताकि यह प्रधान मंत्री जनधन योजना में और योगदान कर सके।

38. समुत्थान से संबंधित मामलों में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएमसी) की अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ विनियमन में समानता लाने के लिए, यह प्रस्ताव है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत 500 करोड़ रुपए और उससे अधिक की परिसंपत्ति आधार वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-एनडी को सरफेसी अधिनियम, 2002 के अनुसार "वित्तीय संस्था" के तौर पर अधिसूचनाओं हेतु विचार किया जा सकेगा।

जन धन से जन सुरक्षा तक

39. भारत की जनसंख्या का बड़ा भाग-स्वास्थ्य, दुर्घटना अथवा जीवन-किसी प्रकार के बीमा के बगैर ही है। दुःखद है कि जब हमारी युवा पीढ़ी बूढ़ी होगी उसके पास भी कोई पेंशन नहीं होगी। प्रधान मंत्री जन धन योजना की सफलता से प्रोत्साहित होकर, मैं सभी भारतीयों, विशेषकर गरीबों और वंचितों के लिए कार्यशील सामाजिक नेटवर्क सृजित करने के कार्य का प्रस्ताव करता हूं।

40. शीघ्र शुरु की जाने वाली प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना मात्र 12 रु. प्रति वर्ष के प्रीमियम पर ₹2 लाख के दुर्घटना मृत्यु जोखिम को कवर करेगी। इसी तरह, हम अटल पेंशन योजना की शुरु करेंगे यह अंशदान की अवधि पर निर्भर

रहते हुए एक निश्चित पेंशन उपलब्ध कराएगी। इस योजना में शामिल होने के लिए लोगों को प्रत्साहित करने हेतु, सरकार 31 दिसंबर 2015 से पहले खोले गए नए खातों में पांच वर्ष के लिए, 1000 रुपए प्रति वर्ष तक सीमित, लाभार्थियों के प्रीमियम के 50 प्रतिशत का अंशदान करेगी।

41. तीसरी सामाजिक सुरक्षा योजना जिसकी मैं घोषणा करना चाहता हूं। वह है - प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, यह ₹ 2 लाख नैसर्गिक मृत्यु और के दुर्घटना जोखिम को कवर करेगी। आयु समूह 18-50 के लिए इसका प्रीमियम ₹ 330 प्रतिवर्ष अथवा ₹ एक प्रतिदिन से कम होगा।

42. पीपीएफ में लगभग ₹ 3,000 करोड़ और ईपीएफ निधि में लगभग ₹ 6,000 करोड़ की बिना दावे की जमाराशियां पड़ी हैं। मैंने निधि में इन राशियों के विनियोजन हेतु वित्त विधेयक में अदावाकृत निक्षेप अधिनियम के अधिनियमन का प्रस्ताव किया है जिसका उपयोग इनके प्रीमियमों को सब्सिडी देने पर किया जाएगा। कमजोर वर्गों वृद्धावस्था पेंशनरों, बीपीएल कार्ड धारकों और छोटे और सीमान्त किसानों तथा अन्य को प्रीमियम पर सब्सिडी उपलब्ध कराने हेतु प्रावधान किया जाएगा। एक ब्यौरेवार स्कीम मार्च में शुरु की जाएगी।

43. इस बीच, देश में वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या को भी विशेष सम्मान दिए जाने की जरूरत है, जिनकी संख्या लगभग 10.5 करोड़ है और इनमें से एक करोड़ से ज्यादा 80 वर्ष से ऊपर वाले हैं। इनमें 70 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और इनकी बड़ी संख्या बीपीएल श्रेणी वालों की है। इनका काफी बड़ा प्रतिशत बड़ी उम्र से जुड़ी विकलांगताओं से भी पीड़ित है। हमारा ऐसा समाज है जो अपने बुजुर्गों का सम्मान करता है। इसलिए, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक सहायता यंत्र और सहायता जीवन साधन उपलब्ध कराने की नई स्कीम शुरु की जाए।

44. संक्षेप में ये सामाजिक सुरक्षा स्कीमें जन धन प्लेटफार्म का उपयोग करने में हमारी वचनबद्धता यह सुनिश्चित करने के लिए दर्शाती है कि किसी भारतीय नागरिक को बीमारी, दुर्घटना अथवा वृद्धावस्था में अभाव की चिन्ता न करनी पड़े। गरीबों, उपेक्षितों और वंचितों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील रहते हुए मेरी सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए चल रही कल्याण योजनाओं के प्रति भी वचनबद्ध है। मैं इन कार्यक्रमों हेतु निम्नानुसार आवंटन बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं :

अनु.जाति	₹30,851 करोड़
अनु.जनजाति	₹19,980 करोड़
महिला	₹79,258 करोड़

45 उन अल्पसंख्यक युवाओं को समर्थ बनाने के लिए इस वर्ष 'नई मंजिल' नामक एक एकीकृत शिक्षा और आजीविका स्कीम आरम्भ की जाएगी, जिसके पास औपचारिक स्कूल

स्थानांतरण प्रमाणपत्र नहीं होता जिससे वे कोई या बेहतर रोजगार प्राप्त कर पाते। इसके आलावा, पारसियों की दिखावटी सभ्यता और संस्कृति के लिए सरकार 2015-16 में 'दी एवरलास्टिंग प्ले' नामक एक प्रदर्शनी में मदद करेगी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए आबंटन संरक्षित किया जा रहा है। वर्ष 2015-16 के लिए ब.अ. में ₹ 3,738 करोड़ है।

अवसंरचना

46. अध्यक्ष महोदय, यह बात किसी से छिपी नहीं है कि विगत दशक में मुख्य चूक अवसंरचना के मोर्चे पर हुई हैं। हमारी अवसंरचना हमारी विकास महत्वकांक्षा के अनुरूप नहीं है। तत्काल सार्वजनिक निवेश बढ़ाए जाने की भारी आवश्यकता है। अतः मैंने रेलवे को सड़कों और सकल बजटीय सहायता दोनों पर परिव्यय क्रमशः ₹14,031 करोड़ और ₹10,050 करोड़ बढ़ा दिया है। सरकारी क्षेत्र की यूनिटों का पूंजी व्यय ₹ 3,17,889 करोड़ होना अनुमानित है, इसमें संशोधित अनुमान 2014-15 से लगभग ₹ 80,844 करोड़ की वृद्धि है। वस्तुतः अवसंरचना में सभी निवेश वर्ष 2015-16 में 2014-15 के मुकादबले सरकारी क्षेत्र के केन्द्रीय उद्यमों के केन्द्र की निधियों और संसाधनों से ₹ 7,000 करोड़ बढ़ जाएंगे।

47. दूसरा, मैं राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि स्थापित करना और इसमें ₹ 20,000 करोड़ का वार्षिक प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए धन प्राप्त करना चाहता हूँ। इससे यह ट्रस्ट बदले में ऋण जुटाने और भारतीय रेल वित्त निगम और एनएचबी जैसी अवसंरचना वित्त कंपनियों में इक्विटी के रूप में निवेश कर सकेगा। इसके बाद अवसंरचना वित्त कंपनियाँ इस अतिरिक्त इक्विटी को कई गुना बढ़ा सकती हैं। तीसरी, मैं, रेल, सड़क और सिंचाई क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए कर मुक्त अवसंरचना बांडों को जारी करने की भी अनुमति देना चाहता हूँ। चौथा, अवसंरचना विकास के सरकारी निजी भागीदारी मोड की समीक्षा करना एवं पुनरुज्जीवित करना है। इसमें शामिल प्रमुख मुद्दा है जोखिम को पुनर्संतुलित करना। अवसंरचना परियोजनाओं में, सरकार को निःसंदेह इसको पूर्ण रूपेण आत्मसात किए बगैर जोखिम के बड़े भाग को वहन करना होगा।

48. पांचवां, मैं नीति में अटल नवोन्मेष मिशन की भी स्थापना करना चाहता हूँ। अटल नवोन्मेष मिशन एक नवोन्मेष संवर्धन मंच होगा। इसमें शिक्षाविदों को शामिल किया जाएगा और भारत में नवोन्मेष, अनुसंधान और विकास की संस्कृति विकसित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अनुभवों को आकर्षित करेगा। यह मंच सरकारी और निजी क्षेत्रों में दोहराव के लिए श्रेष्ठ परंपराओं को भी बढ़ावा देगा। आरंभ में इस प्रयोजन के लिए ₹ 150 करोड़ की राशि निश्चित की जाएगी।

49. भारत के पास सुप्रतिष्ठित और विश्वस्तरीय आईटी उद्योग है। इसके पास लगभग 150 बिलियन अमरीकी

डालर का राजस्व, 100 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक का निर्यात होता है, सीधे लगभग 40 लाख लोगों को रोजगार देता है। अब हम इन्हें आरंभ करने में अधिक सूचि देख रहे हैं। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का प्रयोग, विचारों से मूल्यों का सृजन करना और उन्हें कार्यक्रमों एवं आरोह्य उद्यमों में बदलना तथा कारोबार हमारे युवा वर्ग को कार्य में लगाने और हमारे देश का समावेशी एवं स्थायी विकास करना हमारी कार्यनीति का मुख्य आधार है। वैश्विक पूंजी जुटाने की अधिक उदार प्रणाली, हमारे उत्कृष्टता केन्द्रों में उन्नत सुविधाएं, आधार पूंजी और विकास के लिए वित्तपोषण और कारोबार करने की सुगमता जैसी चिंताओं जिससे खरबों डालर के मूल्य का सृजन होगा, का निराकरण ट्रिलियन डालरों का सृजन करने के लिए किया जाएगा।

50. इस उद्देश्य के साथ सरकार सेतु (स्व-रोजगार और प्रतिभा का उपयोग) नामक तंत्र की स्थापना कर रही है। सेतु एक औद्योगिकीय-वित्तीय उद्भवन होगा और अन्य स्व-रोजगार के क्रियाकलापों, विशेषकर प्रौद्योगिकी प्रेरित क्षेत्रों में व्यवसाय चलाने के सभी पहलुओं की सहायता करने हेतु सहायता कार्यक्रम होगा। इस प्रयोजन के लिए, मैं नीति आयोग में आरंभिक रूप में ₹ 1000 करोड़ निर्धारित करता हूँ।

51. चूंकि लघु पत्तनों में सफलता दिखायी दी है, निजी क्षेत्र के लिए पत्तन आकर्षक निवेश संभावना बन सकते हैं। पत्तनों को निजी क्षेत्र में ऐसा निवेश जुटाने तथा उनके पास अप्रयुक्त पड़े भू-संसाधनों का उत्थान करने की आवश्यकता है। हमें ऐसा करने में समर्थ बनाने के लिए, निजी क्षेत्र के पत्तनों को कंपनी अधिनियम के तहत निगमित होने और कंपनियाँ बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

52. अध्यक्ष महोदय, घरेलू और विदेशी, दोनों तरह के निवेशकों से लगातार शिकायत आती रही है कि भारत में निवेश करने और परियोजना शुरू करने की हमारी प्रतिबद्धता अनेक प्रकार की अनुमति लेने में बीते हुए बहुत अधिक समय के द्वारा कमतर आंकी गई। ये अनुमतियाँ विभिन्न कानूनों/नीतियों के अधीन ली जाती हैं। क्या भारत निवेश के लिए गंतव्य बन सकता है, जो व्यवसाय खोलने के लिए सार्वजनिक रूप से बताए गए दिशा-निर्देशों और मानदण्डों के अनुसार अनुमति प्रदान करता है, जो विनियामक तंत्र के अत्यधीन होते हैं।

53. मैं, इस प्रयोजन के लिए संभावना की जांच करने और विधान का प्रारूप तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति नियुक्त करना चाहता हूँ, जहाँ कई पूर्वानुमतियों को पहले से ही मौजूद विनियामक तंत्र द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सके।

54. सरकार 5 नई अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं शुरू करने का भी प्रस्ताव रखती है, प्रत्येक की क्षमता 4000 मेगावाट की होगी और वे प्लग एण्ट प्ले मोड में होंगी। पारदर्शी नीलामी पद्धति के द्वारा परियोजना के कार्य पर

संविदा दिया जाने से पूर्व सभी तरह की मंजूरियां क्रियान्वित की जाएंगे। इसे ₹ 1 लाख करोड़ तक का निवेश खोलना चाहिए। इस प्रयास की सफलता के आधार पर, सरकार, सड़क, पत्तनों, रेल लाइनों, हवाई अड्डों आदि जैसी अन्य अवसंरचना परियोजनाओं में इस प्रकार की प्लग-एण्ड-प्ले परियोजनाओं पर भी विचार करेगी। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कुडनकुलम न्यूक्लीयर विद्युत केन्द्र की दूसरी यूनिट 2015-16 में चालू हो जाएगी।

55. अध्यक्ष महोदया, मैं वर्ष के दौरान कर उछाल से कुछ अतिरिक्त संसाधन जुटाने की आशा करता हूँ। यदि मैं सफल हुआ तो बजटीय आवंटन से मनरेगा के लिए ₹ 5000 करोड़ आवंटन बढ़ाने का प्रयास करूंगा, एकीकृत बाल विकास स्कीम के लिए ₹ 1500 करोड़, एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम के लिए ₹ 500 करोड़ और प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए ₹ 3000 करोड़ और एनआईआईएफ में ₹ 5000 करोड़ का आरंभिक अंतर्वाह के लिए प्रयास करूंगा।

वित्तीय बाजार

56. भारत में अवसंरचना सेक्टर में निवेश सहित निवेश प्रोत्साहित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक भारतीय बांड बाजार की गहनता है, जिसे हमें उसी स्तर पर लाना है जहां हमारा विश्व स्तरिय इक्विटी बाजार है। मैं, इस वर्ष लोक ऋण प्रबंधन एजेंसी की स्थापना करके, इस प्रक्रिया को शुरू करना चाहता हूँ। इससे भारत का विदेशी उधार और घरेलू ऋण दोनों एक ही छत के नीचे आ जाएंगे।

57. मैं वायदा बाजार आयोग को सेबी में विलय करने का भी प्रस्ताव करता हूँ ताकि वस्तु वायदा बाजारों का विनियमन मजबूत किया जा सके और अंधाधुंध संट्रेबाजी कम की जा सके। वित्त विधेयक, 2015 में, विधान को समर्थकारी बनाने, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

58. पूंजी लेखा नियंत्रण एक नीति है न कि विनियामक विषय। अतः, मैं वित्त विधेयक के जरिए फेमा की धारा-6 में संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूँ ताकि स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की जा सके कि इक्विटी की तरह ही पूंजी प्रवाहों पर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके सरकार द्वारा नियंत्रण रखा जाएगा।

59. समुचित रूप से कार्यशील पूंजी बाजार के लिए यथोचित उपभोक्ता संरक्षण की भी जरूरत है। अतः मैं क्षेत्रीय तटस्थ वित्तीय निपटान एजेंसी की स्थापना करने के लिए एक कार्य बल बनाने का भी प्रस्ताव करता हूँ। यह सभी वित्तीय सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध शिकायतों का समाधान करेगी। मुझे सदन को सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि वित्तीय डाटा प्रबंधन केन्द्र, वित्तीय क्षेत्र अपीलीय अधिकरण, समाधान

निगम और लोक ऋण प्रबंधन एजेंसी संबंधी कार्य बल को सौंपे गए कार्यों में संतोषजनक प्रगति हो रही है। हमने भारतीय वित्त संहिता के संबंध में अनेक सुझाव प्राप्त किए हैं। इस समय, इनकी समीक्षा न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण समिति द्वारा की जा रही है। मुझे विश्वास है कि देर-सबेर भारतीय वित्त संहिता को संसद में विचारार्थ पुरःस्थापित किया जाएगा।

60. अध्यक्ष महोदया, यह तो शुरुआत ही है। मेरी निगाह प्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू करने पर है, जो अंतरराष्ट्रीय रूप से दरों के संबंध में प्रतिस्पर्धी है, इसके लिए कोई छूट प्राप्त नहीं है, बचतों को प्रोत्साहित करना है और अंतरवर्तियों से कर की उगाही नहीं करता है। ऐसी प्रत्यक्ष कर प्रणाली वस्तु एवं सेवा कर के माध्यम से जिस आधुनिकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को लागू कर रहे हैं, उसके समरूप है और इससे अधिक पारदर्शिता आएगी तथा ज्यादा निवेश बढ़ेगा।

61. अध्यक्ष महोदया, कर्मचारी भविष्य निधि खातों के संबंध में और कर्मचारी राज्य बीमा के दावा-अनुपात को सभी भलीभांति जानते हैं। यहां उनका उल्लेख करना मात्र पुनरावृत्ति होगी। यह ध्यान देने योग्य है कि ये दोनों संस्थाएं सेवाप्रदाता कम और कल्याणपरक अधिक हैं। इसके अलावा, न्यून वेतन वाले कामगारों की वेतन कटौतियों का प्रतिशत बेहतर वेतन पाने वाले कामगारों की वेतन कटौतियों की तुलना में अधिक है।

62. कर्मचारी भविष्य निधि के संबंध में, कर्मचारी को दो विकल्प दिए जाने की आवश्यकता है। पहला, कर्मचारी स्वयं कर्मचारी भविष्य निधि या नई पेंशन स्कीम का विकल्प चुने। दूसरा, आरंभिक सीमा से कम मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान, नियोक्ता के अंशदान को घटाए या प्रभावित किए बिना, वैकल्पिक होना चाहिए। कर्मचारी राज्य बीमा के सम्बन्ध में, कर्मचारी को कर्मचारी राज्य बीमा या बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (इरडा) द्वारा मान्य कोई स्वास्थ्य बीमा उत्पाद चुनने का विकल्प होना चाहिए। सभी सम्बद्ध पक्षों से विचार-विमर्श के बाद, हम इस सम्बन्ध में कानून में संशोधन करना चाहते हैं।

स्वर्ण का मुद्रिकरण करना

63. भारत विश्व में स्वर्ण के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है तथा प्रतिवर्ष 800-1000 टन स्वर्ण का आयात करता है। यद्यपि, भारत में 20,000 टन से अधिक के स्वर्ण भण्डार का अनुमान है; लेकिन अधिकांशतः यह स्वर्ण न तो व्यापार में और न ही मुद्रिकरण में प्रयुक्त होता है। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

- i) स्वर्ण मुद्रिकरण स्कीम जारी की जाए, जो वर्तमान स्वर्ण जमा और स्वर्ण धातु ऋण स्कीमों दोनों का स्थान लेगी। नई स्कीम सोना जमा कराने वाले व्यक्ति को उसके धातु खाते में ब्याज अर्जन तथा

ज्वेलरों को उनके धातु खाते में ऋण प्राप्त करने की अनुमति देगी। बैंक/अन्य डीलर भी स्वर्ण का मुद्रिकरण कर सकेंगे।

- ii) वैकल्पिक वित्तीय आस्ति, सरकारी स्वर्ण बांड का स्वर्ण धातु की खरीद के विकल्प के रूप में भी विकास करना होगा। इन बांडों पर एक निश्चित ब्याज-दर होगी और बॉन्ड के धारक को बॉन्ड मोचन के समय स्वर्ण के अंकित मूल्य के संदर्भ में नकद प्रतिदेय होंगे।
- iii) भारतीय स्वर्ण सिक्का बनाने का काम शुरू करना, जिसके पटल पर अशोक चक्र बना होगा। इस प्रकार के भारतीय स्वर्ण सिक्कों से देश के बाहर बनाए गए सिक्कों की मांग में कमी आएगी और देश में उपलब्ध स्वर्ण के पुनर्चक्रण में मदद मिलेगी।

64. काले धन के प्रवाह को रोकने का एक उपाय नकद होने वाले लेन-देनों को हतोत्साहित करना है। अब, अधिकतर भारतीयों के पास रुपये डेबिट कार्ड है या यह लिया जा सकता है। अतः मैं, जल्द ही कई उपाय आरम्भ करने का प्रस्ताव करता हूँ। इनसे क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड लेन-देन को प्रोत्साहित और नकद लेन-देनों को हतोत्साहित किया जाएगा।

निवेश

65. सेबी द्वारा वैकल्पिक निवेश निधि विनियमन अधिसूचित किए गए हैं। ऐसी वैकल्पिक निवेश निधियां घरेलू निवेशों को सुसाध्य बनाने के लिए अन्य साधन प्रदान करेंगी। सभी स्रोतों से निवेशों को बढ़ाने की जरूरत के मद्देनजर, मैं, वैकल्पिक निवेश निधियों में विदेशी निवेशों की अनुमति देने का भी प्रस्ताव करता हूँ।

66. विदेशी निवेश जुटाने के लिए, भारतीय कम्पनियों हेतु प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने हेतु, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विभिन्न प्रकार के विदेशी निवेशों, खासकर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशों और विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों के बीच के विभेद को दूर किया जाए और उनके स्थान पर समिश्र उच्चतम सीमाएं लायी जाएं। जो क्षेत्र पहले से ही 100 प्रतिशत स्वचलित मार्ग के अंतर्गत आते हैं, प्रभावित नहीं होंगे।

67. भारत सरकार की 'एक्ट ईस्ट' नीति दक्षिण-पूर्वी एशिया में सघन आर्थिक और कार्यनीतिक सम्बन्धों को बढ़ाने की दिशा में किया गया प्रयास है। इस क्षेत्र में भारतीय निजी सेक्टर से निवेश को उत्प्रेरित करने के लिए, परियोजना विकास कंपनी सीएमएलवी देशों अर्थात् कम्बोडिया, म्यांमार, लाओस और वियतनाम में, पृथक विशेष प्रयोजन साधनों के माध्यम से, विनिर्माण केंद्रों की स्थापना करेगी।

सुरक्षित भारत

68. मेरी सरकार महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए वचनबद्ध है। महिलाओं की सुरक्षा अधिवक्तृता और जागरूकता वाले कार्यक्रमों की सहायता के लिए, मैंने निर्भया कोष में अतिरिक्त ₹1000 करोड़ मुहैया कराने का निर्णय किया है।

पर्यटन

69. भारत में सांस्कृतिक विश्व धरोहर के 25 (पच्चीस) स्थल हैं। इनमें भूदृश्य बहाली, संकेत तथा भाषान्तर केन्द्र, पार्किंग, विकलांग व्यक्तियों के लिए अभिगमन सुविधाएं; सुरक्षा और शौचालयों सहित आगन्तुकों हेतु सुख-सुविधाएं; तथा प्रकाशीकरण एवं उसके आस-पास रहने वाले व्यक्तियों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं आदि सुविधाओं की अभी भी पर्याप्त रूप से कमी है, और इनकी बहाली अपेक्षित है। मैं निम्नलिखित धरोहर स्थलों के लिए इन सुविधाओं पर आधारित कार्य शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ:

- i) पुराने गोवा के चर्च और कॉन्वेंट
- ii) हम्पी, कर्नाटक
- iii) एलीफेन्टा गुफाएं, मुम्बई
- iv) राजस्थान में कुम्भलगढ़ और अन्य पहाड़ी किले
- v) रानी की वाव, पाटन, गुजरात
- vi) लेह पैलेन्स, लद्दाख, जम्मू कश्मीर
- vii) वाराणसी मंदिर टाउन, उ.प्र.
- viii) जलियांवाला बाग, अमृतसर, पंजाब
- ix) कुतुब शाही मकबरा, हैदराबाद, तेलंगाना

70. 43 देशों के पर्यटक यात्रियों को जारी आगमन वीजा की सफलता के बाद, मैं इस सुविधा के अंतर्गत 150 देशों, को चरणों में, शामिल करना चाहता हूँ।

हरित भारत

71. अध्यक्ष महोदया, यह अच्छी तरह ज्ञात है कि पर्यावरणीय प्रदूषण अन्य लोगों की अपेक्षा गरीबों के लिए ज्यादा नुकसानदेह होता है। इसलिए हम वचनबद्ध हैं कि हमारी समूची विकास प्रक्रिया जहां तक संभव हो हरी-भरी हो। अधिकांश पेट्रोलियम उत्पादों पर हमारा वास्तविक "कार्बन टैक्स" अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। जहां तक कोयले का संबंध है, हमें प्रदूषण पर कर लगाने और विद्युत मूल्यन के बीच एक बेहतर सन्तुलन तलाशने की जरूरत है। तथापि, इस, वर्ष के आरम्भ में, मैं यह उपाय भी शुरू करना चाहता हूँ। मेरी सरकार फास्टर एडोप्शन एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल्स वाहन (एफएएमई) स्कीम भी आरंभ कर रही है। मैं, 2015-16 में इस स्कीम के लिए ₹75 करोड़ के आरंभिक परियोजना का प्रस्ताव करता हूँ। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का अपना लक्ष्य संशोधित करके 1,75,000 मेगावाट कर दिया है। इसमें सौर द्वारा 1,00,000 मेगावाट, पवन द्वारा 60,000 मेगावाट, बायोमांस द्वारा 10,000 मेगावाट और लघु पन बिजली से 5000 मेगावाट ऊर्जा की क्षमता शामिल है।

72. अध्यक्ष महोदया, हमने, घोटालों, घपलों और भ्रष्टाचार राज को पीछे छोड़ दिया है। सार्वजनिक प्रापण में कदाचार

को एक अधिप्रापण कानून और एक संस्थागत ढांचा, जो अनसीटरल मॉडल के अनुरूप हो, लाकर रोक सकते हैं। मुझे विश्वास है कि संसद को शीघ्र ही इस पर विचार करने की आवश्यकता है। क्या हमें प्रापण कानून की जरूरत है और यदि हां तो उसका आकार-प्रकार क्या हो?

73. दूसरी तरफ, सरकारी संविदाओं में उत्पन्न विवादों को सुलझाने में काफी समय लगता है, और उनके समाधान की प्रक्रिया भी काफी खर्चीली होती है। ऐसे विवादों के समाधान के लिए संस्थागत व्यवस्था को सुसाध्य बनाने के लिए, मेरी सरकार ऐसे विवादों के समाधान हेतु संस्थागत व्यवस्थाओं को सुचारु बनाने के लिए सार्वजनिक संविदा (विवादों का समाधान) विधेयक पुरःस्थापित करना चाहती है।

74. मेरा मानना है कि अवसंरचना के विविध क्षेत्रों में प्रचलित नियामक व्यवस्थाओं में भी आम दृष्टि और दर्शन के अभाव की समस्या से निपटने की भी आवश्यकता है। अतः हमारी सरकार विनियामक सुधार विधेयक पुरःस्थापित करना चाहती है। इससे अवसंरचना के विविध क्षेत्रों में एक सर्वमान्य दृष्टिकोण बहाल किया जा सकेगा।

स्किल इंडिया

75. भारत विश्व के सर्वाधिक युवा राष्ट्रों में से है। हमारे देश की कुल आबादी का 54% से भी अधिक हिस्सा 25 वर्ष से कम आयु के लोगों का है। आवश्यक है कि हमारे युवा 21वीं शताब्दी की नौकरियों के लिए शिक्षित और रोजगार पर रखे जाने योग्य हों। प्रधानमंत्री ने बताया है कि किस प्रकार 'स्किल इंडिया' कार्यक्रम और 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के बीच गहरा तालमेल बैठाया जा सकता है। आज भी हमारे सक्षम कार्यबल के 5% से भी कम को ऐसा औपचारिक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त हो पाता है ताकि वे रोजगार पर रखे जाने योग्य हों और रोजगार में बने रह सकें।

76. हम शीघ्र ही कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के जरिए एक राष्ट्रीय स्किल मिशन का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस मिशन के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों द्वारा चलाए जा रहे कौशल संबंधी कार्यक्रमों को समेकित किया जाएगा तथा हमारी सभी 31 क्षेत्रीय कौशल परिषदों में प्रक्रियाओं और परिणामों के मानकीकरण का अवसर प्रदान किया जाएगा। हम एक डिजिटल वाउचर कार्यक्रम भी तैयार कर रहे हैं। इससे प्रत्येक योग्यताप्राप्त छात्र किसी प्रमाणित प्रशिक्षण प्रदाता से प्राप्त कर सकेगा।

77. चूंकि भारत की कुल आबादी का लगभग 70% हिस्सा अभी भी गांवों में निवास करता है, अतः ग्रामीण युवाओं की नियोजनीयता में वृद्धि करना, भारत की आबादी में युवाओं की इस अधिक भागीदारी से लाभ उठाने की कुंजी है। इसे ध्यान में रखते हुए, हमने दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शुरू की है। इस स्कीम के लिए ₹1,500 करोड़ की राशि निश्चित की गयी है।

78. इस वर्ष श्री दीन दयाल उपाध्याय का 100वां जन्म दिवस मनाया जाएगा। सरकार इस महान राष्ट्रवादी के जन्म-दिवस को ठीक से मनाना चाहती है। शीघ्र ही 100वें जन्म दिवस आयोजन समिति के गठन की घोषणा कर दी जाएगी तथा समारोह हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

79. सभी गरीब और मध्यम वर्ग के छात्र अपनी पसंद की उच्च शिक्षा, बिना किसी धनाभाव का सामना किए प्राप्त कर सकें, इसे ध्यान में रखते हुए, मैं, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम के माध्यम से सभी छात्रवृत्तियों और साथ ही शिक्षा ऋण स्कीमों के आद्योपांत प्रशासन और निगरानी के लिए पूरी तरह से सूचना प्रौद्योगिकी युक्त छात्र वित्तीय सहायता प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूँ। हम सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी छात्र निधि की कमी के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रहें।

80. माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि जुलाई के बजट भाषण में, मैंने प्रत्येक राज्य में एक प्रमुख केंद्रीय संस्थान उपलब्ध कराने की अपनी मंशा जाहिर की थी। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्त वर्ष 2015-16 में जम्मू-कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और असम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों की स्थापना की जाए। बिहार में आयुर्विज्ञान को बढ़ावा देने के मद्देनज़र, मैं इस राज्य में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे अन्य संस्थान की स्थापना करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं, कर्नाटक में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) स्थापित करने तथा इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद को एक परिपूर्ण आईआईटी में अपग्रेड करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं, अमृतसर में एक बागवानी अनुसंधान तथा शिक्षा स्नातकोत्तर संस्थान स्थापित करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। जम्मू-कश्मीर तथा आंध्र प्रदेश में भारतीय प्रबंध संस्थान स्थापित किए जाएंगे। केरल में मैं, मौजूदा राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण संस्थान को निःशक्तता अध्ययन तथा पुनर्वास विश्वविद्यालय में अपग्रेड करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं तीन नए राष्ट्रीय भेषज शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। जिनमें से एक-एक संस्थान क्रमशः महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जाएगा तथा नागालैंड और ओडिशा में एक-एक विज्ञान तथा शिक्षा अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

81. सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रशासन में सुधार लाने के लिए, सरकार का विचार एक स्वायत्त बैंक बोर्ड ब्यूरो स्थापित करने का है। यह ब्यूरो सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों की तलाश और उनका चयन करेगा और अलग-अलग कार्यनीति तथा नवोन्मेष वित्तीय तरीकों और लिखतों के जरिये पूंजी जुटाने की योजनाएं तैयार करने में उनकी मदद करेगा। यह बैंकों के लिए नियंत्रक और निवेश कंपनी स्थापित करने की दिशा में एक अंतरिम कदम होगा।

डिजिटल इंडिया

82. अध्यक्ष महोदया, मैं, सदन को बताना चाहूँगा कि हम डिजिटल इंडिया तैयार करने की दिशा में सही प्रगति कर रहे हैं। 2.5 लाख गांवों को जोड़ने वाले 7.5 लाख किमी के राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कार्यक्रम को और अधिक गति प्रदान की जा रही है जिसके लिए इच्छुक राज्यों को इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने की अनुमति प्रदान की गई है, जिस पर आने वाले व्यय की दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार प्रतिपूर्ति की जाएगी। आंध्र प्रदेश पहला राज्य है, जिसने कार्यान्वयन के इस तरीके के लिए अपना विकल्प दिया है।

83. जैसा कि सदस्यगण जानते हैं, वित्त आयोग ने, अपनी सिफारिशें करते समय विशेष श्रेणी और अन्य राज्यों के बीच के भेद को खत्म कर दिया है। इसके अलावा बिहार और पश्चिम बंगाल वित्त आयोग की सिफारिशों से सर्वाधिक लाभान्वित होने जा रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों को भी तीव्र विकास करने के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसलिए, मैं, बिहार और पश्चिम बंगाल को उसी प्रकार की विशेष सहायता देने का प्रस्ताव करता हूँ जैसी आंध्र प्रदेश सरकार की स्थिति में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। जहां तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का सम्बन्ध है, सरकार इनके पुनर्गठन के समय इन राज्यों के साथ की गई सभी कानूनी वचनबद्धताओं को पूरा करने के प्रति कृतसंकल्प हैं।

84. राज्यों को किए जाने वाले अन्तरण में भारी वृद्धि ने केंद्र के लिए समान अनुपात में राजकोषीय गुंजाइश में कमी की है, फिर भी हम गरीबों और नव-मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, गरीबों और वंचितों के लिए स्कीमों में पर्याप्त प्रावधान किया गया है। उदारगार्थ, मैंने, मध्याह्न भोजन सहित शिक्षा क्षेत्र के लिए ₹68,968 करोड़, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ₹33,152 करोड़ तथा मनरेगा सहित ग्रामीण विकास कार्यों हेतु ₹79,526 करोड़, आवास और शहरी विकास के लिए ₹22,407 करोड़, महिला एवं बाल विकास के लिए ₹10,351 करोड़, तथा जल संसाधन और नमामि गंगे के लिए ₹4173 करोड़ का आबंटन किया है। राज्यों द्वारा इन विषयों पर खर्च की गई महत्वपूर्ण राशि के साथ ही इन क्षेत्रों में विकास काफी बढ़ेगा। मैं, राज्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे इन क्षेत्रों में अपने बढ़े हुए संसाधनों का प्रभावी रूप से उपयोग करें।

85. अध्यक्ष महोदया, मैं दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कॉरीडोर के मामले में हुई अच्छी प्रगति से प्रसन्न हूँ। गुजरात में अहमदाबाद-धौलेरा निवेश क्षेत्र, और महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट शेन्द्रा-बिदकिन औद्योगिक पार्क, अब, बुनियादी अवसंरचना पर काम शुरू करने की स्थिति में हैं। चालू वर्ष में, मैंने ₹1,200 करोड़ की आरंभिक राशि निश्चित की है। तथापि, खर्चों के बढ़ने की स्थिति में, मैं, अतिरिक्त निधियां मुहैया काराऊंगा।

86. किसी भी अन्य चीज से पहले, मातृभूमि के एक-एक इंच की रक्षा सर्वोपरि है। अभी तक हम, उदास और निरुत्साही बर्ताव के बावजूद, आयात पर ही निर्भर रहे हैं। हमारी सरकार ने पहले ही रक्षा में एफडीआई की अनुमति दे दी है ताकि भारत नियंत्रित निकाय हमारे लिए ही नहीं, बल्कि निर्यात के लिए भी, रक्षा उपकरणों के विनिर्माता बनें। इस प्रकार, हम एयरक्राफ्टों सहित रक्षा-उपकरणों के क्षेत्र में उच्चतर आत्म-निर्भरता हासिल करने की दिशा में और मेक इन इंडिया नीति का पालन कर रहे हैं। सम्मानित सदन के सदस्यों ने देखा होगा कि हमने रक्षा उपकरणों की खरीद से जुड़े मामलों में पारदर्शी और शीघ्र निर्णय लिए हैं। ताकि हमारी रक्षा सेनाएं किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहें। इस वर्ष भी, मैंने सशस्त्र बलों की जरूरतों के लिए यथेष्ट संसाधन उपलब्ध कराए हैं। इस वर्ष संभावित व्यय ₹2,22,370 करोड़ के मुकाबले है, 2015-16 के लिए ₹2,46,727 करोड़ का बजट आबंटन किया गया है।

87. यद्यपि भारत में वित्तीय विषयों और अंतरराष्ट्रीय वित्त के उत्कृष्ट ज्ञाता हैं पर देश की प्रगति के लिए उनकी क्षमता को पूर्णतया प्रतिबिंबित और दोहन करने के लिए भारत में अवसर सीमित हैं। गुजरात में जीआईएफटी की परिकल्पना एक अन्तरराष्ट्रीय वित्त केंद्र के रूप में की गई थी परन्तु वास्तव में यह यह सिंगापुर या दुबई के जैसा ही अन्तरराष्ट्रीय वित्त केंद्र बन जाएगा और संयोगवश इसे भारतीयों द्वारा ही चलाया जाता है। यह प्रस्ताव वर्षों से ऐसा ही है। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता रही है कि जीआईएफटी का पहला चरण शीघ्र ही वास्तविकता बन जाएगा। यथोचित विनियम मार्च में जारी किए जाएंगे।

88. सरकार का वाणिज्यिक विवादों के त्वरित समाधान के लिए, विधि आयोग की 253वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर भारत में विभिन्न न्यायालयों में अनन्य वाणिज्यिक प्रभाग गठित करने का प्रस्ताव है। सरकार इस संबंध में हितधारकों से परामर्श करने के पश्चात संसद में एक विधेयक पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव करती है।

89. अध्यक्ष महोदया, सरकार पूर्व में जारी किए गए अध्यादेशों को संसद के अधिनियमों में बदलने के लिए अपेक्षित विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करेगी।

बजट अनुमान

90. मैं अब बजट 2015-16 के बजट अनुमान की ओर आता हूँ।

91. वित्त वर्ष के आयोजना-भिन्न व्यय के अनुमान इसके लिए ₹13,12,200 करोड़ अनुमानित हैं। आयोजना व्यय ₹465,277 करोड़ होना अनुमानित है जो 2014-15 के सं.अ. के बहुत करीब है। तदनुसार, कुल व्यय ₹17,77,477 करोड़ अनुमानित है। रक्षा, आंतरिक सुरक्षा पर व्यय और अन्य आवश्यक व्ययों के लिए जरूरतों हेतु समुचित रूप से व्यवस्था की गई है।

92. सकल कर प्राप्तियां ₹14,49,490 करोड़ अनुमानित हैं। राज्यों को अंतरण ₹5,23,958 करोड़ अनुमानित है। केंद्र सरकार का हिस्सा ₹9,19,842 करोड़ रुपए होगा। अगले वित्त वर्ष के लिए कर-भिन्न राजस्व ₹2,21,733 करोड़ अनुमानित हैं।

93. उपरोक्त अनुमानों के चलते, राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.9 प्रतिशत और राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 2.8 प्रतिशत होगा।

भाग ख

अध्यक्ष महोदय,

94. अब मैं अपने कर प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

95. कराधान सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने की एक लिखत है। कर संग्रहण, लोगों को अपने जीवन स्तर में सुधार लाने और गरीबी, बेरोजगारी तथा मंदगति से विकास संबंधी समस्याओं का निराकरण करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य देख-रेख, आवास तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में, सरकार की मदद करते हैं। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, विगत नौ महीनों में हमारा यह प्रयास रहा है कि एक स्थायी कराधान नीति और अप्रतिकूल कर-भिन्न प्रशासन को संपोषित किया जाए। हमारे कर प्रशासन का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण आयाम काले धन की बुराई के विरुद्ध संघर्ष है। इस दिशा में अनेक उपाय किए जा चुके हैं। मैं इस दिशा में और भी महत्वपूर्ण कदम उठाने का प्रस्ताव करता हूँ।

96. हमें यह सुनिश्चित करने के लिए विकास और निवेश के पुनरूद्धार की आवश्यकता है कि हमारे युवाओं के लिए और अधिक रोजगार सृजित हों तथा विकास के फायदे हमारे करोड़ों गरीब लोगों को प्राप्त हों। इसके लिए हमें एक समर्थकारी कर नीति की आवश्यकता है। मैं इस गरिमामयी सदन के पिछले सत्र में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लिए भारत के संविधान में संशोधन करने हेतु एक विधेयक पुरःस्थापित कर चुका हूँ। जीएसटी द्वारा हमारे आर्थिक कार्यों के मार्ग में एक युगांतकारी भूमिका निभाने की आशा है। इसके परिणामस्वरूप एक सामान्य भारतीय बाजार के विकास और वस्तुओं एवं सेवाओं की लागत पर इसके पड़ने वाले प्रभावों को कम करने से हमारी अर्थव्यवस्था में जबरदस्त सुधार होगा। हम अगले वर्ष से वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रहे हैं।

97. हमें अप्रत्यक्ष कराधान में इस युगान्तरकारी विधान को प्रत्यक्ष कराधान में परिवर्तनकारी उपायों के सदृश्य बनाने की आवश्यकता है। भारत में कारपोरेट कर की 30 प्रतिशत की मूल दर अन्य दूसरी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में विद्यमान दरों की तुलना में अपेक्षाकृत उच्च है, जो हमारे घरेलू उद्योग को अप्रतिस्पर्धी बनाता है। इसके अलावा, कारपोरेट करों का प्रभावी संग्रहण लगभग 23 प्रतिशत है। हम ही दोनों स्तरों पर हाथ धो बैठते हैं, अर्थात् हमारी गणना उच्च कारपोरेट करों वाली प्रणाली के रूप में की जाती है लेकिन अत्यधिक

छूटों की बजट से हमें वह कर प्राप्त नहीं हो पाता है। छूटों की प्रणाली से दबाव वाले समूह, मुकदमेबाजी को बढ़ावा मिला है तथा राजस्व की हानि हुई है। इससे परिहार्य विवेक की भी गुंजाइश पैदा होती है। अतः, मैं अगले 4 वर्षों में कारपोरेट कर की दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे निवेश के उच्चतर स्तर, उच्चतर विकास तथा और अधिक रोजगार का पथ प्रशस्त होगा। कर की दरों में कमी लाने की प्रक्रिया के साथ-साथ कारपोरेट करदाताओं के लिए विभिन्न प्रकार की कर छूटों और प्रोत्साहनों को युक्तिसंगत बनाया जाना तथा समाप्त करना भी आवश्यक है, जो संयोगवश रूप से बड़ी संख्या में कर विवादों का कारण बनते हैं।

98. मैं चाहता हूँ कि कारपोरेट कर की दर को चरणबद्ध रूप से कम किया जाए तथा छूटों को सही तरीके से कम किया जाए; लेकिन मेरा मानना है कि इस आशय का अग्रिम नोटिस देना उपयुक्त रहेगा कि ये बदलाव अगले वित्त वर्ष से आरम्भ हो जाएंगे। हमारी सुविचारित नीति, कर नीति में औचक आश्चर्यों और अस्थिरता से बचना है। तथापि, वैयक्तिक करदाताओं को छूटें मिलती रहेंगी क्योंकि वे बचतों को सुगम बनाते हैं जो निवेश और आर्थिक विकास में तब्दील हो जाती हैं।

99. अपने कर प्रस्तावों को अंतिम रूप प्रदान करते समय, मैंने कतिपय व्यापक विषय स्वीकार किए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल है:

- (क) काले धन पर काबू पाने के लिए उपाय;
- (ख) विकास और निवेश के पुनरूद्धार और घरेलू विनिर्माण के संवर्धन तथा 'मेक इन इंडिया' के जरिए रोजगार सृजन;
- (ग) व्यापार को सुगम बनाने में सुधार लाने के लिए न्यूनतम सरकार तथा अधिकतम अभिशासन;
- (घ) स्वच्छ भारत कार्यक्रमों के माध्यम से जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य में सुधार लाना;
- (ङ) मध्यम वर्ग के करदाताओं को लाभ; और
- (च) अर्थव्यवस्था के अधिकतम लाभों के लिए विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करना।

100. अध्यक्ष महोदय, मेरे कर प्रस्तावों का प्रथम और प्रमुख आधार काले धन की समस्या से कारगर ढंग से निपटना है क्योंकि यह समस्या हमारी अर्थव्यवस्था और समाज के प्राणाधार को आघात पहुँचाती है। गरीबी और असमानता की समस्याओं का तब तक निराकरण नहीं किया जा सकता जब तक कि काले धन के उत्पन्न होने और उसे छिपाने के कृत्य से प्रभावी रूप से और बलपूर्वक निपटा न जाए।

101. पिछले 9 महीनों में, इस दिशा में अनेक उपाय किए गए हैं। अक्टूबर 2014 में तब एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई जब

राजस्व विभाग से एक प्रतिनिधि मंडल ने स्विटजरलैंड का दौरा किया तथा स्विस् अधिकारी (क) आयकर-विभाग द्वारा जिन मामलों की स्वतंत्र रूप से जांच की जा रही है उनके संबंध में सूचना प्रदान करने; (ख) बैंक खातों की वास्तविकता की पुष्टि करने और गैर-बैंकिंग सूचना प्रदान करने और; (ग) ऐसी सूचना समय बद्ध रूप में प्रदान करने; और (घ) दोनों देशों के बीच सूचना के स्वतः आदान-प्रदान के लिए शीघ्रातिशीघ्र भारत के साथ बातचीत शुरू करने पर सहमत होना। अप्रकटीकृत विदेशी आस्तियों के मामलों में जांच को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है जिससे पर्याप्त मात्रा में असूचित आय का पता चला है। देश में विभिन्न स्रोतों से सूचना संग्रहण की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए, एक नई व्यवस्था लागू की जा रही है जिसमें रिपोर्ट करने वाले निकायों द्वारा विवरणों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दर्ज करना शामिल है। इसे आंकड़ों का निर्बाध समेकन और अधिक प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित होगा।

102. जो धन कानूनी रूप से देश की संपत्ति है उसका पता लगाना और देश में वापस लाना देश के प्रति हमारी सुनिश्चित प्रतिबद्धता है। मौजूदा कानून के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं का पालन करते हुए, हमने विदेश में जमा काले धन से विशेष रूप से निपटने के लिए एक व्यापक नया कानून निर्मित करने पर एक सुविचारित निर्णय लिया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, मैं संसद के वर्तमान सत्र में एक विधेयक पुरःस्थापित करना चाहता हूँ।

103. अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से काले धन के संबंध में प्रस्तावित नए कानून की कुछ प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालना चाहूँगा।

- (1) विदेशी आस्तियों के संबंध में आय और आस्तियों को छिपाना और कर वंचन अभियोजन-योग्य होगा तथा इसके लिए 10 वर्षों तक के कठोर कारावास का दंड दिया जा सकता है, इसके अतिरिक्त,
 - इस अपराध को अशमनीय बनाया जाएगा;
 - अपराधकर्ता को समझौता आयोग तक पहुँचने की अनुमति नहीं दी जाएगी; और
 - आय और आस्तियों को इस प्रकार छिपाए जाने के लिए कर के 300% की दर पर शास्ति लगायी जाएगी।
- (2) विदेशी आस्तियों के निबंध में रिटर्न जमा करने या अपर्याप्त प्रकटन सहित रिटर्न जमा करने के लिए अभियोजन चलाया जाएगा और इसके लिए 7 वर्षों तक के कठोर कारावास का दंड दिया जा सकता है।
- (3) किसी अप्रकटीकृत विदेशी आस्ति से आय या विदेशी आस्ति से अप्रकटीकृत आय पर अधिकतम सीमांत दर पर कर अधिरोपित किया

जाएगा। ऐसे मामलों में यदि अन्यथा कोई छूट या कटौती लागू होती है तो उसकी अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

- (4) विदेशी आस्तियों के लाभभोगी स्वामी या लाभभोगी व्यक्ति के लिए रिटर्न जमा करना अनिवार्य रूप से आवश्यक होगा, तब भी यदि कोई कर योग्य आय नहीं हो।
- (5) उपर्युक्त अपराधों के दुष्प्रेरक पर चाहे वह व्यक्ति, निकाय, बैंक या वित्तीय संस्था हो, अभियोजन चलाया जा सकता है और उसे दंडित किया जा सकता है।
- (6) विदेशी खाते को खोलने की तारीख के संबंध में निर्धारित द्वारा आय विवरणी में अनिवार्यतः उल्लेख करना अपेक्षित होगा।
- (7) किसी विदेशी आस्ति के संबंध में आय छिपाने या करवंचन के अपराध को धन-शोधन निवारण अधिनियम 2002 (पीएमएलए) के अंतर्गत एक स्थापित अपराध बनाया जाएगा। यह उपबंध प्रवर्तन एजेंसियों को विदेश में धारित बेहिसाबी आस्तियों को कुर्क या जब्त करने तथा काले धन के शोधन में लिप्त पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन चलाने की शक्ति प्रदान करेगा।
- (8) पीएमएलए के अंतर्गत "अपराध के आगम" की परिभाषा में संशोधन किया जा रहा है ताकि यदि किसी मामले में विदेश में स्थित आस्ति की जब्ती नहीं की जा सके तो भारत में समतुल्य आस्ति की कुर्की और जब्ती की जा सकती है।
- (9) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999(फेमा) में इस आशय का संशोधन किया जा रहा है कि यदि कोई विदेशी मुद्रा, विदेशी प्रतिभूति या इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में भारत से बाहर कोई स्थावर सम्पत्ति धारित है तो उक्त सम्पत्ति के मूल्य के समतुल्य भारत में स्थित किसी सम्पत्ति के संभावित अधिग्रहण की कार्यवाई शुरू की जा सकेगी। इस उल्लंघन को शास्ति अधिरोपण और पांच वर्ष के कारावास सहित अभियोजन के लिए भी उत्तरदायी ठहराया जा रहा है।

104. घरेलू काला धन समाप्ति के लिए, एक नया और अधिक व्यापक बेनामी संव्यहार (प्रतिषेध) विधेयक शीघ्र ही संसद के चालू सत्र में पुरःस्थापित किया जाएगा। इससे बेनामी सम्पत्ति का अधिग्रहण किया जा सकेगा तथा इसके लिए अभियोग चलाने के लिए व्यवस्था की जा सकेगी, इस

प्रकार, बेनामी सम्पत्ति विशेषकर रीयल एस्टेट के क्षेत्र में, काला धन के अर्जन के मुख्य अवसर और धारण पर रोक लगायी जा सकेगी।

105. देश में काले धन की समाप्ति के लिए बजट में कुछ अन्य उपायों के प्रस्तावों का भी जिक्र है। वित्त विधेयक में किसी स्थावर सम्पत्ति की खरीद के लिए नकद रूप में ₹20,000 या इससे अधिक की राशि के संदाय को स्वीकार किए जाने के निषेध के लिए, आयकर अधिनियम को संशोधित करने का प्रस्ताव भी शामिल है। एक लाख रुपए से अधिक मूल्य की किसी भी खरीद या बिक्री के लिए पैन का उल्लेख करना बाध्यकारी किया जा रहा है। थर्ड पार्टी रिपोर्टिंग निकायों द्वारा विदेशी मुद्रा बिक्रियों तथा सीमा पार संव्यवहारों की सूचना दिया जाना भी जरूरी है। उल्लेखनीय संव्यवहारों के विखंडन की जांच के लिए भी उपबंध किया जा रहा है: प्रवर्तन सुधारने की दृष्टि से, सीबीडीटी और सीबीईसी प्रौद्योगिकी का विकास करेगी एक दूसरे से सूचनाओं का आदान-प्रदान करेंगे।

106. अध्यक्ष महोदया, इस वर्ष मेरे कराधान प्रस्तावों का दूसरा स्तंभ घरेलू विनिर्माण क्षेत्र में विकास और निवेश की बहाली और उसके संवर्धन तथा मेक इन इण्डिया के माध्यम से नौकरियों का सृजन करना है। इस दिशा में देशी तथा विदेशी दोनों तरह की पूंजी आकर्षित करने के लिए, मैं अनेक उपायों का प्रस्ताव करता हूँ। श्रेणी-I और श्रेणी-II दोनों ही वैकल्पिक निवेश निधियों को टैक्स 'पासथ्रू' की अनुमति देने का प्रस्ताव है, ताकि इन निधियों में निवेशकों पर कर वसूला जाए। इससे इन निधियों को उच्चतर संसाधन जुटाने में इस्तेमाल किया जा सकेगा और लघु तथा मझोले उद्यमों, अवसंरचना और सामाजिक परियोजनाओं में अधिक निवेश किया जाएगा, और नए उद्यमों तथा आरंभिक उपक्रमों में अधिक निजी इक्विटी मुहैया कराई जाएगी।

107. पिछले बजट में उन्हें आंशिक पास-थ्रू देते हुए, रीयल एस्टेट निवेश ट्रस्टों (आरईआईटी) और अवसंरचना निवेश ट्रस्टों (इनविट्स) को प्रोत्साहन करने की दृष्टि से उपाय किया गया था। विनिर्माण गतिविधियों की बहाली करने के लिए सामूहिक निवेश महत्वपूर्ण है। विभिन्न पूर्ण परियोजनाओं में भारी मात्रा में निधियां अवरुद्ध हैं जिन्हें नई अवसंरचनात्मक परियोजनाएं शुरू करने को सुसाध्य बनाने के लिए जारी किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए मैं, आरईआईटी तथा इनविट्स इकाइयों की लिस्टिंग के समय पर विद्यमान प्रायोजकों के लिए प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) का संदाय करने की शर्त पर पूंजीगत अभिलाभ प्रणाली को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव करता हूँ। आरईआईटी की निजी आस्ति से भाड़ा अर्जित आय पास-थ्रू सुविधायुक्त होगी।

108. वर्तमान कराधान संरचना में ऑफशोर लोकेशनों से काम कर रहे निधि प्रबंधकों के लिए प्रोत्साहन अंतर्निहित है। इन अपतटीय निधि प्रबंधकों को भारत में दुबारा लाने-बसाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु में स्थायी स्थापन (पी.ई.)

मानकों को इस आशय से आशोधित करने का प्रस्ताव करता हूँ कि भारत में निधि प्रबंधक की उपस्थित मात्र से ही ऑफशोर निधियों की पी.ई. गठित नहीं होगी जिसके प्रतिकूल परिणाम होंगे।

109. सामान्य अपवंचन निवारक नियमावली (गार) के कार्यान्वयन का मामला बहस का विषय रहा है। देश में निवेश की भावना अब सकारात्मक हो चली है और हमें इस गति को और तेज करने की जरूरत है। गार से संबंधित कतिपय विवादास्पद मामले भी हैं जिन्हें सुलझाए जाने की आवश्यकता है। अतः, गार के लागू होने को दो वर्षों तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, यह भी निर्णय लिया गया है कि जब भी गार लागू होगा तो वह 01.04.2017 को या उसके बाद किए जाने वाले निवेशों के लिए भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा।

110. आज मैं देखता हूँ कि अनेक युवा उद्यमी व्यवसायिक उद्यम चला रहे हैं अथवा नए व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। इन्हें नवीनतम प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है। इसलिए निम्न लागत पर छोटे व्यवसायों को प्रौद्योगिक अंतर्वाह सुसाध्य बनाने के लिए, मैं तकनीकी सेवाओं के लिए रायल्टी और शुल्क पर आयकर की दर 25% से घटाकर 10% करने का प्रस्ताव करता हूँ।

111. रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने के लिए, यह प्रस्ताव है कि नए नियमित कर्मकारों के रोजगार हेतु कटौती के लाभ सभी व्यवसाय निकायों को दिया जाए। न्यूनतम 100 नियमित कर्मकारों की पात्रता की आरंभिक सीमा घटाकर 50 की जा रही है।

112. घरेलू विनिर्माण और मेक इन इंडिया के संवर्धन के संदर्भ में, अप्रत्यक्ष करों की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए अप्रत्यक्ष करों में, कुछ निविष्टियों, कच्चे माल, मध्यवर्तियों और सभी 22 मदों के संघटकों पर बुनियादी सीमाशुल्क की दर घटाने का प्रस्ताव करता हूँ ताकि शुल्क व्युत्क्रम को न्यूनतम किया जा सके और अनेक क्षेत्रों में विनिर्माण लागत घटाई जा सके। एसएडी लगाने के कारण कुछ अन्य परिवर्तन सेनवैट क्रेडिट संग्रहण की समस्या का समाधान कर देंगे। आईटीए बाउंड मदों के विनिर्माण में प्रयोग हेतु पापुलेटिड प्रिंटेड सर्किट बोर्डों के सिवाय, सभी वस्तुओं को पूर्ण छूट देने और वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त पर कुछ अन्य निविष्टियों और कच्चे माल के आयातों पर एसएडी घटाने का प्रस्ताव करता हूँ। विभिन्न परिवर्तनों का ब्यौरा बजट भाषण के अनुबंध में दिया गया है।

113. मेरा अगला प्रस्ताव बिजनेस करने को सहज बनाने पर ध्यान देते हुए न्यूनतम शासन और अधिकतम अभिशासन तथा कर राजस्व पर समझौता किए बगैर कर प्रक्रियाओं के सरलीकरण के बारे में है। देश में 2013-14 में कुल धन कर

संग्रहण ₹1008 करोड़ था। क्या कोई कर जिसके संग्रहण में अधिक लागत लगती हो और लाभ कम होता हो उसे जारी रखा जाए या इसे निम्न लागत और उच्च प्राप्ति वाले कर से बदल दिया जाए? धनी व्यक्तियों को, कम आय वाले व्यक्तियों की तुलना में, अधिक कर देना चाहिए इसलिए मैंने धन कर समाप्त करने और ₹1 करोड़ वार्षिक से अधिक की कर योग्य आय वाले बड़े धनवानों पर 2% अतिरिक्त अधिभार से प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे कर सरलीकरण का मार्ग प्रशस्त होगा और विभाग को कर अनुपालन और कराधार बढ़ाना सुनिश्चित करने पर अधिक ध्यान देने में समर्थ बनाएगा। ₹1008 करोड़ के कर त्याग देने के एवज में, इन उपायों के जरिए विभाग को 2% अतिरिक्त प्रभार से लगभग ₹ 9,000 करोड़ का संग्रहण होगा। इसके अतिरिक्त, व्यष्टियों और कंपनियों द्वारा धारित धन का पता लगाने के लिए, आस्तियों के बारे में सूचना, जो धन-कर विवरणी में प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है, को आयकर विवरणियों में ले लिया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि धन कर का उत्पादन किसी आय को टेक्स नेट से बचने न दे।

114. आयकर अधिनियम में अप्रत्यक्ष अंतरण संबंधी उपबंध जो पिछली सरकारों की देन है, में अनेक अस्पष्टताएं हैं। इस उपबंध को समुचित रूप से संशोधित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, विदेशी कंपनियों द्वारा अपने शेयरधारकों को अदा किए गए लाभांशों के अप्रत्यक्ष अंतरण के उपबंधों को लागू करने संबंधी चिंताओं का समाधान केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा स्पष्टीकारक परिपत्र के जरिए किया जाएगा। ये परिवर्तन शक्तियों के विवेकशील प्रयोग की सभांशना समाप्त करेंगे और करदाताओं को अवरोध मुक्त ढांचा उपलब्ध कराएंगे।

115. इसके अतिरिक्त, छोटे करदाताओं से जुड़ी दिक्कतों और घरेलू अंतरण मूल्य निर्धारण में अनुपालन लागत कम करने के लिए, मैं आरंभिक सीमा ₹ 5 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 20 करोड़ करने का प्रस्ताव करता हूँ।

116. विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए मैट उपबंधों को तर्क-संगत बनाने के लिए उन प्रतिभूतियों, जिनपर निम्न दर पर कर लगता है, में लेनदेन पर पूंजी अभिलाभों से उनकी आय के अनुरूप लाभ मैट के अध्यक्ष नहीं होंगे।

117. कर प्रशासन सुधार आयोग ने कर विभागों में प्रशासनिक सुधार के लिए अनेक सिफारिशें की हैं। ये सिफारिशें जांच के अंतिम स्तर पर हैं और इस वर्ष के दौरान उपयुक्त रूप से कार्यान्वित की जाएंगी।

118. वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में किए गए सुधारों के भाग के रूप में, मैं शिक्षा उप-कर, और माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा उप-कर को केंद्रीय उत्पाद-शुल्क में शामिल करने का प्रस्ताव करता हूँ। प्रभावी रूप से, उपकरणों सहित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क की 12.36% की सामान्य दर को 12.5% के समतुल्य पूर्णांकित की जा रही है। मैं, अनुबंध में दिए गए विवरण के अनुसार, कतिपय अन्य जिंसें में केंद्रीय उत्पाद-

शुल्क की विशिष्ट दरों में संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूँ। तथापि, पेट्रोल और डीजल के मामले में, ऐसी विशिष्ट दरों का, वर्तमान में, उनपर उद्ग्रहित शिक्षा उपकर की मात्रा तक शामिल करने के लिए संशोधन किया जा रहा है ताकि उत्पाद-शुल्कों के कुल प्रभाव में कोई परिवर्तन न हो। 12% से कम उत्पाद-शुल्क की यथामूल्य दरों और कुछ अपवादों के साथ 12% से उच्चतर दरों में कोई वृद्धि नहीं की जा रही है। सिगरेट पर उत्पाद-शुल्क लगाने और पान मसाला, गुटखा और अन्य कतिपय तम्बाकू उत्पादों पर प्रवृत्त मिश्रित उत्पाद-शुल्क स्कीम में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं।

119. घरेलू चमड़ा फुटवियर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चमड़े से बने ऊपरी भाग वाले फुटवियरों और जिनका खुदरा मूल्य ₹ 1000 प्रति जोड़ी से अधिक है पर उत्पाद-शुल्क घटाकर 6% किया जा रहा है।

120. व्यवसाय करने को और अधिक सहज करने के लिए, ऑनलाइन केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सेवा कर पंजीकरण दो कार्यदिवसों में किया जाएगा। इन करों के अधीन निर्धारित डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए इनवायसेज को जारी करने और इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड रखने की अनुमति होगी। इन उपायों से कागजी काम और लालफीताशाही में कमी आएगी। निविष्टियों और निविष्टि सेवाओं पर सेनवैट क्रेडिट लेने की समय-सीमा छह माह से बढ़ाकर एक वर्ष की जा रही है। यह भी व्यवसाय सहजता का एक उपाय है।

121. कारोबार और उद्योग में वस्तु एवं सेवा कर लागू करने की काफी उत्सुकता है। केंद्र और राज्यों दोनों द्वारा सेवाओं पर कर उद्ग्रहण के सुचारु अंतरण को सहज बनाने के लिए, सेवा कर और शिक्षा उप-कर की 12.36 प्रतिशत की वर्तमान दर में वृद्धि करके 14% की समेकित दर करने का प्रस्ताव है।

122. अध्यक्ष महोदया, घरों की साफ-सफाई और स्वच्छ पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य हैं। इसलिए इस वर्ष, मेरे कराधान प्रस्तावों का चौथा आधार स्वच्छ भारत अभियान के कार्यक्रमों से संबंधित है। मैंने, अपने प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों में, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व वाले अंशदानों को छोड़कर, स्वच्छ भारत कोष में दिए जाने वाले अंशदानों के लिए 100% कटौती का प्रस्ताव किया है। इसी प्रकार का कर उपाय स्वच्छ गंगा निधि के लिए भी प्रस्तावित है।

123. अप्रत्यक्ष करों में, स्वच्छ पर्यावरण कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए कोयला, आदि के प्रति मीट्रिक टन पर स्वच्छ ऊर्जा उप-कर ₹100 से बढ़ाकर ₹200 करने का प्रस्ताव करता हूँ। औद्योगिक प्रयोग को छोड़कर एथिलिन के पालिमरों के बोरों और बस्तों पर उत्पाद शुल्क 12% से बढ़ाकर 15% किया जा रहा है। यदि आवश्यकता होती है, तो सभी अथवा कतिपय सेवाओं पर 2% अथवा इससे कम दर पर स्वच्छ भारत उप-कर लगाने के लिए समर्थकारी प्रावधान करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। यह उप-कर

अधिसूचित होने की तारीख से प्रभावी होगा। इस उप-कर से सृजित संसाधनों का उपयोग स्वच्छ भारत के वित्तपोषण और संवर्द्धन कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा।

124. सामान्य जल-मल व्ययन उपचार संयंत्रों की सेवाओं को सेवा कर से छूट देने का भी प्रस्ताव है। विद्युत से परिचालित वाहनों और हाईब्रिड वाहनों के विनिर्माण के लिए विनिर्दिष्ट कलपुर्जों पर वर्तमान में उपलब्ध सीमा-शुल्क और उत्पाद शुल्क से छूट, और एक वर्ष बढ़ाकर, 31.03.2016 तक की जा रही है।

125. अध्यक्ष महोदया, इस वर्ष मेरे कराधान प्रस्तावों का पांचवा स्तंभ है मध्यम वर्गीय कर दाताओं को लाभ प्रदान करना। इस संबंध में प्रस्ताव निम्नवत हैं:

- स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती सीमा बढ़ाकर ₹15,000 से ₹25,000 करना।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा मौजूदा ₹20,000 से बढ़कर ₹30,000 होगी।
- 80 वर्ष और इससे अधिक आयु के बहुत वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जो स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत नहीं आते हैं; उनके उपचार पर किए गए व्यय के लिए ₹30,000 की कटौती की अनुमति होगी।
- बहुत वरिष्ठ नागरिकों के मामले में गंभीर प्रकृति की विनिर्दिष्ट बीमारी के कारण होने वाले व्यय के लिए ₹60,000 की कटौती सीमा बढ़ाकर ₹80,000 करने का प्रस्ताव है।
- आय कर अधिनियम की धारा 80घघ और धारा 80प के तहत विकलांग व्यक्तियों के लिए ₹25,000 की अतिरिक्त कटौती की अनुमति होगी।
- पेंशन निधि और नई पेंशन योजना में अंशदान के कारण कटौती की सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.5 लाख करने का प्रस्ताव है।
- व्यष्टियों को सामाजिक सुरक्षा नेट, और पेंशन की सुविधा मुहैया कराने के लिए, धारा 80गगघ के तहत नई पेंशन योजना में अंशदान के लिए अतिरिक्त ₹50,000 की कटौती प्रदान करने का प्रस्ताव है इससे भारत पेंशन रहित समाज के बजाय पेंशनभोगी समाज बन सकेगा।
- सुकन्या समृद्धि स्कीम में निवेश पहले से ही धारा 80ग के तहत कटौती के लिए पात्र है। जमा राशि पर ब्याज भुगतान सहित लाभार्थियों के लिए सभी भुगतानों को भी पूरी छूट दी जाएगी।

□ परिवहन भत्ता छूट को ₹800 से बढ़ाकर ₹1600 प्रतिमाह किया जा रहा है।

□ वरिष्ठ नागरिकों के फायदे के लिए वरिष्ठ बीमा योजना पर कर छूट दी जाएगी।

126. अध्यक्ष महोदया, मैं अपर्याप्त राजकोषीय गुंजाइश के बावजूद, व्यष्टि कर दाताओं को रियायत दे रहा हूं। पिछले बजट और इस बजट में मध्यम वर्गीय करदाताओं को दी गई रियायतों को ध्यान में रखते हुए, आज वैयक्तिक कर दाता को ₹4,44,200 का कर लाभ उपलब्ध कराया गया है, जैसाकि अनुबन्ध में देखा जा सकता है। जैसे ही मेरी वित्तीय क्षमता सुधरेगी, व्यष्टि कर दाताओं को और भी बहुत कुछ दिया जाएगा।

127. अध्यक्ष महोदया, कराधान से संबंधित अनेक विशिष्ट प्रस्ताव हैं। इनमें सड़क और अन्य अवसंरचना में निवेश का वित्तपोषण करने के लिए ₹4 प्रतिलीटर की सीमा तक लगने वाले विद्यमान उत्पाद-शुल्क को सड़क उपकरण में परिवर्तित करना शामिल है इन सेक्टरों के लिए इस उपाय का जरिए ₹40,000 करोड़ की राशि उपलब्ध करायी जाएगी। सेवा कर में, फलों और सब्जियों के संबंध में कतिपय प्रशीतनपूर्व भण्डारण सेवाओं को छूट दी जा रही है ताकि इस महत्वपूर्ण सेक्टर में मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित किया जा सके। सेवा कर के अंतर्गत नकारात्मक थोड़ी सी छोटी की जा रही है और कराधार बढ़ाने के लिए कतिपय अन्य छूटों को वापस लिया जा रहा है।

128. योग भारत का विश्व को एक बहुत बढ़िया तोहफा है। आय कर अधिनियम की धारा 2(15) के तहत धर्मार्थ प्रयोजन के दायरे में योग को शामिल करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, बहुत से वास्तविक धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा सामना की जा रही समस्या को कम करने के लिए, व्यापार, वाणिज्य या कारोबार प्रकृति के क्रियाकलापों से होने वाली प्राप्तियों पर अधिकतम सीमा संशोधित करके ₹25 लाख की मौजूदा सीमा से कुल प्राप्तियां 20% करने का प्रस्ताव है। गैर-लाभकारी संगठनों का एक नेशनल डेटा आधार भी विकसित किया जा रहा है।

129. कुछ समय से प्रत्यक्ष कर संहिता के अधिनियमन पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। प्रत्यक्ष कर संहिता के अधिकांश उपबन्धों को आय कर अधिनियम में पहले ही शामिल कर लिया गया है। प्रत्यक्ष कर संहिता के कुछेक पहलुओं में, जिन्हें छोड़ दिया गया था उनके बारे में हमने वर्तमान बजट में कुछ मुद्दों का समाधान किया है। इसके अतिरिक्त, आय कर अधिनियम के अधीन विधि शास्त्र को सुविकसित किया गया है। इन सब पहलुओं पर विचार करते हुए, प्रत्यक्ष कर संहिता जैसाकि आज मौजूद है, इसे आगे बढ़ाने में कोई खास फायदा नहीं होगा।

130. अध्यक्ष महोदया, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों का ब्यौरा बजट भाषण के अनुबंध और सभा पटल पर रखे गए

अन्य बजट दस्तावेजों में दिया गया है। मेरे प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों से ₹8,315 करोड़ की राजस्व हानि होगी जबकि अप्रत्यक्ष करों में प्रस्तावों से ₹23,383 करोड़ की प्राप्ति हो सकती है। अतः सभी कर प्रस्तावों के निवल प्रभाव से ₹15,068 करोड़ का राजस्व अभिलाभ होगा।

निष्कर्ष

131. अध्यक्ष महोदया, निष्कर्ष स्वरूप यह स्पष्ट है कि इस बजट की आशाएं बहुत ऊंची रही हैं। लोगों ने आमूल-चूल सुधारों के लिए हमसे आग्रह किया था। वे भी मानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विशाल सुपर टैंकर या हाथी है। अध्यक्ष महोदया, हाथी धीरे चलता है पर चलता जरूर है। यहां तक कि हमारे धुर विरोधी भी इस बात को मानेंगे कि हम तेजी से आगे बढ़े हैं। मैं समझता हूँ कि मैंने इस भाषण में तात्कालिक तौर पर किए जाने वाले उपायों का ही जिक्र स्पष्ट रूप से नहीं किया है, बल्कि भविष्य की एक रूपरेखा भी प्रस्तुत की है।

132. मेरा मानना है कि मेरी सरकार पूर्णतया एक ईमानदार सरकार है। हमने हमेशा वही किया है जो हम कहते और करते हैं। अध्यक्ष महोदया, जिसके लिए हमने वोट पाए, जिसके लिए हम सत्ता में आए, हम इस बदलाव, विकास, नौकरियों और मौलिकता, गरीब और वंचित तबकों के कारगर उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं। “दरिद्र नारायण” के प्रति हमारी वचनबद्धता अक्षुण्ण है, जो जाति, पंथ या धर्म को ध्यान में रखे बिना समता और सबके लिए न्याय की हमारी संवैधानिक वचनबद्धता है। यह उपनिषद् के इस मंत्र की भावना के अनुरूप है:

ओउम् सर्वे भन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा काश्चिद् दुःखः भाग भवत।
ओउम् शांति..... शांति.....शांति.....
ओउम्! सभी सुखी हों,
सभी निरोग हों,
सभी अच्छा देखने वाले हों,
कभी किसी को कोई दुःख-शोक न हो,

133. अध्यक्ष महोदया, इन्ही शब्दों के साथ मैं यह बजट सदन को समर्पित करता हूँ।

अनुबंध

- **प्राकृतिक संसाधनों का आबंटन:** कोयला ब्लॉकों के आबंटन की नीलामी और खनन क्षेत्र में सुधार से यह सुनिश्चित होगा कि देश और उसके लोगों के विकास के लिए संसाधनों का उपयोग किया जाता है।
- **वित्तीय समावेशन:** प्रधान मंत्री जन धन योजना के माध्यम से प्रत्येक भारतीय को इस वित्तीय समावेशन व्यवस्था का अंग बनाना है;

- **आम आदमी का स्वास्थ्य और स्वच्छता:** स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए ‘स्वच्छ भारत’ अभियान की सफलतापूर्वक शुरुआत से बेहतर उत्पादकता और गरीब का कल्याण हो सकेगा।
- **बालिका और उनकी शिक्षा:** शेष प्राथमिक विद्यालयों में शौचालयों के निर्माण के लिए एक अभियान शुरू किया और साथ ही बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान का भी शुभारंभ किया गया है।
- **युवाओं के लिए रोजगार का सृजन:** ‘मेक इन इंडिया’ अभियान की शुरुआत की गई है और इसे एक व्यापक प्रक्रिया और नीति पुनर्निर्माण के साथ संयोजित किया गया है ताकि भारत के लाखों युवाओं के लिए नौकरी के अवसरों के सृजन हेतु वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाया जा सके।
- **बाधा रहित कारोबारी माहौल:** कर आतंकवाद को समाप्त करके एक अ-प्रतिकूल कर प्रणाली स्थापित की गई; वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर राजनीतिक सहमति सुनिश्चित की गई जिससे सांविधिक संशोधन विधेयक के विधानमंडल में पारित किया जा सके।
- **गरीबों को लाभों की सुपुर्दगी की प्रक्रिया दक्ष बनाई गई:** तकनीकी का प्रयोग करके राष्ट्रीय स्तर पर रसोई गैस सब्सिडी के सीधे अंतरण की शुरुआत की गई।
- **रोजगारों का सृजन करने के लिए निवेश को आकर्षित करना:** रक्षा, बीमा और रेलवे अवसंरचना में एफडीआई की अधिकतम सीमा में वृद्धि की गई; निर्माण और चिकित्सा उपकरण क्षेत्रों में एफडीआई के लिए शर्तों को युक्तियुक्त बनाया गया;
- **रोजगार बाजारों का विस्तार और श्रमिक कल्याण को सुनिश्चित करना:** जिन राज्यों ने अपने श्रमिक कानूनों में सुधार किया है तथा ‘श्रमेव जयते’ अम्बेला कार्यक्रम के इस क्षेत्र में व्यवस्थापरक बदलाव लाया है, उन्हें सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
- **बेहतर कृषि-उत्पादकता; कृषकों की अधिक आय:** कृषि में बेहतर उत्पादकता के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड हेतु कार्यक्रम प्रारंभ किया गया।
- **देश को ऊर्जा संपन्न बनाना:** कोयले की अनिश्चितता के बावजूद, ऊर्जा क्षेत्र में तीव्र गति से वृद्धि हुई और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आरंभ किए गए।
- **प्रौद्योगिकी - जमीन से आकाश तक:** सभी गांवों को ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी, मंगल ग्रह मिशन की सफलता के साथ ज्ञान और नवाचार आधारित समाज बनाने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम आरंभ

- किया गया।
- **कौशल युक्त भारत कार्यक्रम:** कौशल विकास के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया गया है जो एक व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ करने वाला है।
- **सरकार में क्षमता और बेहतर कार्य संस्कृति:** बिना भय के उत्तरदायित्व और क्षमता और पारदर्शिता के साथ कार्य संस्कृति का शुभारंभ किया गया; अनेक क्षेत्रों में नागरिकों को विश्वास दिलाने और स्वयं प्रमाणन को प्रोत्साहित करने का माहौल बनाया गया।
- **रेड टेप टू रेड कारपेट:** लालफीताशाही को समाप्त करके भारत में अनेक प्रक्रियाएं, नियमों और विनियमों में सुधार करके और यौक्तिकीकरण द्वारा 'कारोबार कार्य को सुकर' बनाया।
- **देश के उत्तर-पूर्वी भाग को मुख्य धारा में लाना:** प्रधान मंत्री की दो यात्राओं और महत्वपूर्ण अवसरचना परियोजनाओं की शुरुआत के साथ विकास प्रक्रिया में उत्तर-पूर्व को विशेष प्राथमिकता दी गई है।
- **राष्ट्र और इसकी संस्कृति पर गर्व:** योग, नमामि गंगे, घाट और धरोहर नगर विकास कार्यक्रमों को संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता दिलाकर भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शक्ति को सामर्थ्य प्रदान की।

बजट भाषण के भाग ख में अनुबंध

वित्त विधेयक, 2015 में आय-कर अधिनियम, 1961, धन-कर अधिनियम, 1957, उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, वित्त अधिनियम, 1994 और वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधनों का सार निम्नलिखित है :

प्रत्यक्ष कर

2. कर की दरें

- 2.1. यह प्रस्ताव है कि वित्त वर्ष 2015-16 में अर्जित आय, निर्धारण वर्ष 2016-17 में निर्धारणीय, के संबंध में व्यक्तिगत आय कर की दर में और विदेशी कंपनियों के लिए कर की दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- 2.2. यह भी प्रस्ताव है कि 1 करोड़ रुपए से अधिक की आय वाले व्यक्तियों, हिंदु अविभक्त कुटुम्बों (एचयूएफ), व्यक्तियों के संगम (एओपी), व्यक्तियों के निकाय (बीओआई), कृत्रिम वैधिक व्यक्तियों, फर्मों सहकारी सोसाइटियों और स्थानीय प्राधिकरणों पर 12 प्रतिशत की दर से प्रभार उदग्रहीत किया जाए। 1 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए तक की आय

वाली घरेलू कंपनियों के मामले में प्रभार 7 प्रतिशत की दर से उदग्रहित करने का प्रस्ताव है और 10 करोड़ रुपए से अधिक आय वाली घरेलू कंपनियों पर 12 प्रतिशत की दर से प्रभार उदग्रहित करने का प्रस्ताव है।

- 2.3. यह भी प्रस्ताव है कि विदेशी कंपनियों के मामले में यदि आय 1 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए तक है तो 2 प्रतिशत की दर से, तथा यदि आय 10 करोड़ रुपए से अधिक है तो 5 प्रतिशत की दर से प्रभार उदग्रहित किया जाता रहेगा।
- 2.4. यह भी प्रस्ताव है कि कंपनियों द्वारा लाभांशों के संवितरण और शेयरों की पुनःखरीद अथवा म्यूचुअल फंडों और आय के संवितरण पर प्रतिभूतीकरण न्यासों द्वारा संदेय अतिरिक्त आय पर कर 10 प्रतिशत की चालू दर के स्थान पर 12 प्रतिशत की दर से प्रभार उदग्रहित किया जाए।
- 2.5. सभी कर दाताओं के लिए सर्वव्यापीकृत गुणवत्ता आधारित शिक्षा उपलब्ध कराने और इसके लिए वित्त-पोषण प्रदान कराने की सरकार की प्रतिबद्धता की पूर्ति के लिए 2 प्रतिशत की दर से आय कर पर शिक्षा उप कर और कर तथा प्रभार पर 'माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर' नामक 1 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रभार वित्त वर्ष 2015-16 के लिए जारी रखने का प्रस्ताव है।

3. क. काला धन नियंत्रण के लिए उपाय

- 3.1. स्थावर भू-संपदा में काले धन के सृजन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से, आय कर अधिनियम की धारा 269धध और धारा 269न के उपबंधों में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि स्थावर संपत्ति में किसी लेन-देन के लिए 20,000/- अथवा अधिक रुपए की नकद अग्रिम स्वीकृति या अदायगी को प्रतिषिद्ध किया जा सके। ऐसे उपबंधों के उल्लंघन के मामले में समान धनराशि की शास्ति का उपबंध करने का प्रस्ताव भी है।
- 3.2. सीमा शुल्क (सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 132) से संबंधित किसी कारोबार के निष्पादन में गलत घोषणा करने/गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने के अपराध की व्यापार आधारित धन-शोधन पर रोक लगाने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अंतर्गत स्थापित अपराध की संज्ञा देना।

4. ख. घरेलू विनिर्माण के संवर्धन और निवेश माहौल (मेक इन इंडिया) में सुधार करने के उपाय

- 4.1. विभिन्न हितधारकों से प्राप्त अभ्यावेदनों और इस संबंध में हुए अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए, यह प्रस्ताव है कि सामान्य परिहार्य-रोधी नियमों

- (जनरल एंटी अवोइडेंस रूल्स) के प्रवर्तन को 2 वर्ष तक स्थगित रखा जाए। तदनुसार, इसे वित्त वर्ष 2017-18 (वि.वर्ष 2018-19) और पश्चातवर्ती वर्षों की आय के लिए लागू करने का प्रस्ताव है। यह भी प्रस्ताव है कि 31.03.2017 तक किए गए निवेश जीएएआर के अंतर्गत नहीं आएंगे।
- 4.2 वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) की कराधान पद्धति को सहज बनाने के उद्देश्य से, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा अभिशासित एआईएफ श्रेणी-I और श्रेणी-II की भी सभी उप-श्रेणियों को पास-थ्रू दर्जा प्रदान करने का प्रस्ताव है।
- 4.3 भारत में अपतटीय निधियों के निधि प्रबंधकों को पुनःअवस्थित करने को सुगम बनाने के उद्देश्य से, स्थायी स्थापन (पीई) मानकों में सुधार करने का प्रस्ताव है।
- 4.4 आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 94 के उपबंधों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, यह प्रस्ताव है कि आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना के अधिसूचित क्षेत्रों में 1.4.2015 से 31.3.2020 की अवधि के दौरान स्थापित नई विनिर्माण यूनिटों को अतिरिक्त निवेश भत्ता (@15%) और अतिरिक्त अवक्षयण (@15%) उपलब्ध कराया जाए।
- 4.5 स्थावर संपदा निवेश न्यासों और अवसंरचना निवेश न्यासों के संबंध में, यह प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव है कि प्रयोजक के साथ सूचीकरण के समय यूनिटों की भारी बिक्री के संबंध में वही व्यवहार किया जाएगा जो उसके लिए उस समय उपलब्ध होगा; यदि उसने प्रत्यक्ष सूचीकरण की अवस्था में विशेष प्रयोजन संस्था की उसकी शेयरधारिता की बिक्री करने पर किया जाता। इसके अतिरिक्त, स्थावर संपदा निवेश न्यास द्वारा प्रत्यक्ष रूप से धारित स्थावर संपदा आस्तियों से उत्पन्न होने वाली किराये संबंधी आय को भी न्यास के जरिए पारित किए जाने और स्थायी संपदा निवेश न्यास के यूनिट धारकों को कर लगाए जाने की अनुमति दिए जाने का भी प्रस्ताव है।
- 4.6 आयकर अधिनियम की धारा 194ठघ के उपबंधों में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है जिससे कार्पोरेट बंध पत्रों और सरकारी प्रतिभूतियों से विदेशी निवेशकों (एफआईआई और क्यूएफआई) की आय के संदर्भ में 5% कर की घटी दर की अनुप्रयोज्यता अवधि 31.5.2015 से बढ़ाकर 30.6.2017 तक की जा सके।
- 4.7 लघु कंपनियों द्वारा सामना की गई समस्याओं का निराकरण करने और प्रौद्योगिकी अंतर्वाह को सुकर बनाने के उद्देश्य से आयकर अधिनियम की धारा 115क के उपबंधों में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है जिससे तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी पर कर दर को 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया जा सके।
- 4.8 रोजगार सृजन को सुकर बनाने के उद्देश्य से, आयकर अधिनियम की धारा 80जजकक के उपबंधों में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है जिससे यह प्रावधान किया जा सके कि उक्त धारा के अधीन कर लाभ किसी कारखाने में वस्तुओं के विनिर्माण से लाभ प्राप्त करने वाले और वर्ष के दौरान नियोजित 50 से अधिक कामगारों में नए नियमित कामगारों को मजदूरी की अदायगी करने वाले प्रत्येक 'व्यक्ति' के लिए उपलब्ध होगा।
- 4.9 किसी विनिर्माण यूनिट या विद्युत के उत्पादन या वितरण में लगी किसी यूनिट द्वारा संस्थापित नए संयंत्र या मशीनरी पर 20 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त मूल्यहास की अनुमति है। तथापि, यदि पिछले वर्ष के 30 सितम्बर तक आस्ति संस्थापित की जाती है तो केवल 10 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्यहास की अनुमति है। उत्तरवर्ती वित्त वर्ष में शेष 10 प्रतिशत के अतिरिक्त मूल्यहास की ही अनुमति है।
5. **ग. कारोबार विवाद समाधान को सुकर बनाने के लिए न्यूनतम सरकार और अधिकतम अभिशासन**
- 5.1 वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 9 को यह स्पष्ट करने के लिए संशोधित किया गया था कि यदि किसी कंपनी या संस्था में कोई आस्ति, शेयर होने के कारण, या ब्याज, भारत में स्थित किसी शास्ति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना मूल्य पर्याप्त रूप से प्राप्त कर लेती है, तो ऐसे शेयर या ब्याज के अंतरण से प्रोदभूत लाभ भारत में कर योग्य होगा। स्पष्टीकारक संशोधन के उपरांत, विभिन्न पक्षकारों से बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए जिनमें संशोधित उपबंधों में प्रयुक्त कतिपय शब्दों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगे गए थे। चिन्ताओं की जांच-पड़ताल करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति भी गठित की गई थी। विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं और विभिन्न हितधारकों द्वारा उठाई गई चिन्ताओं को ध्यान में रखते हुए, आयकर अधिनियम के उपबंधों में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है जिससे निम्न प्रावधान किया जा सके—
- * शेयर या ब्याज को भारत में स्थित आस्तियों से पर्याप्त रूप से अपना मूल्य प्राप्त करने वाला माना जाएगा, यदि विनिर्दिष्ट तारीख को, ऐसी आस्तियों का मूल्य कंपनी या संस्था द्वारा स्वामित्वाधीन सभी आस्तियों के उचित बाजार मूल्य का कम से कम पचास प्रतिशत को

- प्रदर्शित करता हो। तथापि, यदि भारतीय आस्तियों का मूल्य 10 करोड़ रुपए से अधिक न हो तो अप्रत्यक्ष अंतरण के उपबंध लागू नहीं होंगे। इसके अलावा, भारतीय आस्तियों के अप्रत्यक्ष अंतरण से उत्पन्न होने वाले लाभों के कराधान के लिए अनुपातिकता का सिद्धांत लागू होगा।
- * भारतीय कंपनी, भारतीय कंपनी या संस्था की स्वामित्व संरचना या नियंत्रण को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित करने के आशय वाले अपतटीय संव्यवहार से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगी। अनुपालन न करने पर, शास्ति लगाए जाने का भी प्रस्ताव है।
- * अप्रत्यक्ष कर संबंधी उपबंध उस मामले में लागू नहीं होंगे जहां किसी संस्था से जुड़े उद्यमों के साथ-साथ किसी विदेशी कंपनी में शेयर या ब्याज के अंतरणकर्ता के पास न तो नियंत्रण या प्रबंधन का अधिकार हो, न मत देने की शक्ति हो अथवा शेयर पूंजी या ब्याज विदेशी कंपनी या संस्था में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय आस्तियों की धारिता में कुल मतदान शक्ति या कुल शेयर पूंजी के पांच प्रतिशत से अनाधिक हो।
- * आमेलन या वि-संबद्धन की स्कीम के अधीन किसी भारतीय कंपनी के शेयरों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना मूल्य पर्याप्त रूप से प्राप्त करने वाली विदेशी कंपनी के शेयर के अंतरण के संदर्भ में पूंजीगत लाभों को छूट दी जाएगी।
- 5.2 आयकर अधिनियम की धारा 92खक के उपबंधों में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है जिससे अंतरण मूल्य निर्धारण विनियमों की विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहारों की प्रारम्भिक सीमा को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया जा सके।
- 5.3 आयकर अधिनियम की धारा 2(15) के उपबंधों में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है जिससे "योगा" को "धर्मार्थ प्रयोजन" की परिभाषा में कार्यकलाप की विशिष्ट श्रेणी में शामिल किया जा सके और असली धर्मार्थ संगठनों द्वारा किए गए कारोबारी प्रकृति के कार्यकलापों के लिए इस शर्त के अधधीन राहत का भी प्रावधान किया जा सके कि ऐसे कार्यकलापों से आय कुल प्राप्तियों के 20 प्रतिशत से कम हो।
- 5.4 यह प्रस्ताव है कि सेबी अधिदेश के अनुसार समाशोधन नियमों द्वारा स्थापित मूल समझौता गारंटी निधि की आय को कर मुक्त किया जाए।
- 5.5 आयकर अधिनियम की धारा 255 के उपबंधों को संशोधित करने का प्रस्ताव है ताकि आयकर अपील अधिकरण की एकल सदस्य पीठ द्वारा सुने जाने वाले मामले के संबंध में मौद्रिक सीमा को 5,00,000 रुपए से बढ़ाकर 15,00,000 की जाए।
- 5.6 आयकर अधिनियम के उपबंधों को संशोधित करने का प्रस्ताव है ताकि सेबी विनियम 1996, के अनुसार म्युचुअल फंड की स्कीमों के समेकन की प्रक्रिया के अंतर्गत म्युचुअल फंड की स्कीम की अंतरण पर कर तटस्थता प्रदान की जा सके।
- 5.7 आयकर अधिनियम के उपबंधों को संशोधित करने का प्रस्ताव है ताकि हर वर्ष विधि के एक ही प्रश्न पर निर्धारिती के समान मामले में राजस्व द्वारा पुनरावृत्ति स्वरूप की अपीलों की पूर्व सुनवाई के लिए एक तंत्र की व्यवस्था की जाए।
- 5.8 यह प्रस्ताव है कि विदेशी अधिकार क्षेत्रों में संगत करों के संबंध में राहत प्रदान करने के लिए नियम निर्धारित करने हेतु बोर्ड को सशक्त किया जाए।
- 5.9 यह प्रस्ताव है कि कर दाताओं पर अनुपालन भारांश को कम करने के लिए 2016-17 से (निर्धारण वर्ष) धन कर के उपग्रहण समाप्त किया जाए। ऐसे उत्साधन के कारण हुई राजस्व हानि को घरेलू कम्पनियों और सभी कारपोरेट-भिन्न करदाताओं के मामले में विद्यमान अधिभार में 2 प्रतिशत की वृद्धि करके प्रतिपूर्ति करने का प्रस्ताव है।
- 5.10 करदाताओं को समझौता आयोग के रूप में उपलब्ध विकास समाधान तंत्र की युक्तिसंगत बनाने की दृष्टि से यह उपबंधित करने का प्रस्ताव किया जाता है कि निर्धारण अधिकारी द्वारा फिर से खोले गए निर्धारण वर्ष के संबंध में निपटान आयोग को आवेदन प्रस्तुत करते समय निर्धारिती अन्य निर्धारण वर्षों के संबंध में भी आवेदन कर सकता है जिनके संदर्भ में कार्यवाही फिर से शुरू की जा सकती है बशर्ते उन निर्धारण वर्षों के लिए आय रिटर्न निर्धारिती द्वारा जमा कराया गया हो।
- 6. घ. स्वच्छ भारत कार्यक्रम के जरिए जीवन की गुणवत्ता और जन स्वास्थ्य में सुधार करना**
- 6.1 यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि स्वच्छ भारत कोष (निवासी और अनिवासी दोनों द्वारा) और स्वच्छ गंगा निधि (निवासी द्वारा) में दिए गए दान (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार किए गए सीएसआर अंशदानों को छोड़कर) आयकर अधिनियम की धारा 80छ के अंतर्गत 100% कटौती के पात्र होंगे।

7. ड. मध्यम वर्ग करदाताओं के लिए लाभ

व्यक्तिगत करदाताओं के बीच बचतों को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य देख-रेख को संवर्धित करने की दृष्टि से, आयकर अधिनियम के अंतर्गत प्रोत्साहनों के माध्यम से अनेक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है। इनका विवरण निम्नवत है :

- 7.1 यह उपबंधित करने का प्रस्ताव है कि सुकन्या समृद्धि योजना में किए जाने वाला निवेश धारा 80ग के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र होगा तथा इस स्कीम से किये जाने वाले किसी भी संदाय पर कर नहीं लगेगा।
- 7.2 आयकर अधिनियम की धारा 80घ के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कटौती की सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए (वरिष्ठ नागरिकों के मामले में 20,000 से बढ़ाकर 30,000 करना) करने का प्रस्ताव है। यह भी प्रस्ताव है कि अत्यंत वरिष्ठ नागरिक जो स्वास्थ्य बीमा लेने के लिए तैयार नहीं हैं, के मामले में उसी धनराशि की व्यय की कटौती की अनुमति दी जाए।
- 7.3 यह प्रस्ताव है कि आय कर अधिनियम की धारा 80घघख के अंतर्गत अत्यंत वरिष्ठ नागरिक के मामले में निर्दिष्ट बीमातियों के कारण होने वाले व्यय पर कटौती की सीमा 60,000 रुपए से बढ़ाकर 80,000 रुपए कर दी जाए।
- 7.4 यह प्रस्ताव है कि आयकर की धारा 80घघ के अंतर्गत आश्रित विकलांग व्यक्ति के चिकित्सा उपचार सहित, देख भाल के संबंध में कटौती की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दी जाए। यह भी प्रस्ताव है कि गंभीर विकलांगता की दशा में, कटौती की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए कर दी जाए।
- 7.5 यह प्रस्ताव है कि आयकर अधिनियम की धारा 80प के अंतर्गत विकलांग व्यक्ति के मामले में कटौती की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दी जाए। यह भी प्रस्ताव है कि गंभीर विकलांग की दशा में कटौती की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए कर दी जाए।
- 7.6 प्रस्ताव है कि आयकर अधिनियम की धारा 80गगग के अंतर्गत एलआईसी या इरडा अनुमोदित बीमाकर्ता की पेंशन निधि में अंशदान के कारण कटौती की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी जाए।
- 7.7 यह प्रस्ताव है कि आयकर अधिनियम की धारा 80गगघ के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन स्कीम में कर्मचारी

द्वारा किए जाने वाले अंशदान के कारण कटौती की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपए कर दी जाए। यह भी प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय पेंशन स्कीम में किए गए अंशदान के संबंध में 1.50 लाख रुपए की सीमा के अलावा, 50,000 रुपए की कटौती प्रदान की जाए।

- 7.8 आयकर अधिनियम की धारा 197क के उपबंधों को संशोधित करने का प्रस्ताव है ताकि जीवन बीमा पॉलिसी की कर योग्य परिपक्वता आगमों में प्राप्तकर्ताओं द्वारा कर की कटौती न किए जाने की स्वयं घोषणा दर्ज करने की सुविधा दी जा सके।
- 7.9 आयकर अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी निवासी से स्थावर संपत्ति खरीद रहे किसी व्यक्ति को कर कटौती करानी अपेक्षित है किंतु इस प्रकार काटे गए कर को जमा करने के लिए टैन प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है। किसी अनिवासी से स्थावर संपत्ति खरीदने वाले किसी व्यक्ति अथवा हिंदू अविभक्त परिवार को वही सुविधा देने की दृष्टि से, यह प्रस्ताव है कि किसी व्यक्ति अथवा हिंदू अविभक्त परिवार जो किसी अनिवासी से स्थावर संपत्ति के अधिग्रहण पर कर कटौती की जानी अपेक्षित है, द्वारा टैन प्राप्त करने की शर्त को शिथिल किया जाए।
- 7.10 यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग नियंत्रण निधि को दिए गए दान आयकर अधिनियम की धारा 80छ के अंतर्गत 100% कटौती के पात्र हैं।
- 7.11 पैरा 99 में उल्लिखित कर कटौतियों के ब्यौरे
- | | |
|---|------------------|
| ● धारा 80ग के अन्तर्गत कटौती | ₹1,50,000 |
| ● धारा 80गगघ के अन्तर्गत कटौती | ₹50,000 |
| ● मकान सम्पत्ति ऋण पर ब्याज पर कटौती | ₹2,00,000 |
| (स्वयं द्वारा अधिगृहित सम्पत्ति) | |
| ● स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर धारा 80घ के अन्तर्गत कटौती | ₹25,000 |
| ● परिवहन भत्ते पर छूट | ₹19,200 |
| जोड़ | ₹4,44,200 |

8. च. अर्थव्यवस्था में लाभ बढ़ाने के लिए अनोखे प्रस्ताव

- 8.1 यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि किसी स्थायी प्रतिष्ठान (पीई) अथवा विदेशी बैंक की शाखा द्वारा अपने मुख्यालय और विदेशी शाखा में अदा किए गए

- ब्याज की प्रभार्यता कराधान के स्रोत नियम के अंतर्गत और आय की संगणना के लिए उस स्थायी प्रतिष्ठान अथवा शाखा के साथ व्यवहार करने और टीडीएस लगाने के प्रयोजनार्थ कर योग्य निकाय माना जाए।
- 8.2 किसी समुद्री कर्मी, चाहे वह भारतीय या विदेशी जहाज कार्यरत हो, के मामले में 'निवासी' स्तर के निर्धारण के प्रयोजनार्थ भारत में रहने की अवधि की संगणना के एक समान तरीके की व्यवस्था करने के दृष्टिगत यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि नियमों में इसके निर्धारण के लिए सीबीडीटी को समर्थकारी शक्ति दी जाए।
- 8.3 तलाशी मामले में, प्रस्ताव है कि जब्त की गई नकद राशि निर्धारित के निबटान आवेदन के अंतर्गत उसकी कर देयता के प्रति समायोजित की जाए।
- 8.4 अनिवासियों को किए गए भुगतानों पर समुचित कर कटौती सुनिश्चित करने की दृष्टि से, यह प्रस्ताव है कि आयकर की धारा 195 के उपबंधों को संशोधित किया जाए जिससे कि निश्चित विदेशी प्रेषणों, जिनके बारे में यह दावा किया जाता है कि उन पर कर नहीं लगता है, के संबंध में जानकारी जुटाने के लिए सी.बी.डी.टी. को समुचित रूप से सशक्त बनाया जा सके।

अप्रत्यक्ष कर

क. घरेलू विनिर्माण और 'मेक इन इंडिया' को संवर्धित करने के लिए वृद्धि और निवेश चक्र का पुनरुज्जीवन

सीमा शुल्क

I. शुल्क व्युत्क्रमण की समस्या के समाधान के लिए कतिपय निविष्टियों पर शुल्क में कमी:

1. बिजली इन्सुलेटर के विनिर्माण के प्रयोग हेतु 'धातु पुर्जे'।
2. इन्सुलेटिड वायर व केबलों के विनिर्माण में प्रयोग हेतु इथीलेन-प्रोपीलेन-नान-कंजुगेटिड-डिने रबड़ (ईपीडीएम), वाटर ब्लाकिंग टेप और माइका ग्लास टेप।
3. घरेलू माइक्रोवेव चूल्हों के विनिर्माण में प्रयोग होने वाले 1 के.वी. तक मैग्नेट्रॉन।
4. रेफ्रिजरेटर कंप्रेसरों के विनिर्माण में प्रयोग हेतु कंप्रेसर के लिए सी-ब्लाक, ओवर लोड प्रोटेक्टर (ओएलपी) और पाजीटिव थर्मल कोएफिशिएंट और कंप्रेसर हेतु क्रैंक शाफ्ट।
5. वाशकोटों के विनिर्माण में प्रयोग के लिए जियोलाइट, सेरिया जिनकोनिया कंपाउंड और सिरियम कंपाउंड,

जिनका आगे कैटालाइटिक कन्वर्टर के विनिर्माण में प्रयोग होना है।

6. हाइड्रोजन पराक्साइड के विनिर्माण हेतु एंथ्राकुइनोन।
7. उर्वरकों के विनिर्माण में प्रयोग हेतु सल्फ्यूरिक एसिड।
8. अधिकतम भंडारण क्षमता (विस्तारित सहित) क्षमता का प्रयोग करते हुए सिंगल सिक्वुएस में कम से कम 30 मिनट के लिए न्यूनतम 23 फ्रेम प्रति सैकंड पर 800x600 पिक्सल्स के न्यूनतम समाधान के चलते विडियो रिकार्डिंग की क्षमता वाले डिजिटल स्टिल इमेज विडियो कैमरा के कल-पुर्जे।

II. कच्चे माल की लागत घटाने के लिए बुनियादी सीमा शुल्क में कटौती:

1. इथीलीन डाइक्लोराइड (ईडीसी), बिनाईल क्लोराइड मोनोमर (वीसीएम) और स्टाइरीन मोनोमर (एसएम) 2.5% से 2%
2. इसोप्रेन और द्रवित बुटेन 5% से 2.5%
3. बुटाईल एक्रिलेट 7.5% से 5%
4. यूलेक्साइट अयस्क 2.5% से शून्य
5. एंटीमनी धातु, एंटीमनी वेस्ट और स्कैप 5% से 2.5%
6. विनिर्दिष्ट सीएनसी लेथ मशीनों और मशीन केंद्रों के विनिर्माण में प्रयोग हेतु विनिर्दिष्ट संघटक 7.5% से 2.5%
7. फ्लेक्सिबल मेडिकल विडियो एंडोस्कोप के विनिर्माण में प्रयोग हेतु कतिपय विनिर्दिष्ट निविष्टियां 5% से 2.5%
8. टेलीकम्यूनिकेशन ग्रेड आप्टिकल फाइबर केबलों के विनिर्माण में प्रयोग हेतु एचडीपीई 7.5% से शून्य
9. एलसीडी/एलईडी टीवी पैनलों के विनिर्माण में प्रयोग हेतु ब्लैक लाइट यूनिट मोड्यूल 10% से शून्य
10. आर्गेनिक लेड (ओलेड) टीवी पैनल 10% से शून्य
11. पेंसमेकर के विनिर्माण में प्रयोग हेतु विनिर्दिष्ट कच्चे माल [बैटरी, टिटिनियम, प्लाडियम वायर, यूटेक्टिक वायर, सिलीकान रेशे और रबड़ सोल्डर पेस्ट, रीड स्विच, डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, कंट्रोलर्स, कायल्स (स्टील), रबींग (सिलीकॉन)] सीवीडी और एसएडी से पूर्णतया छूट।
12. सोलर वाटर हीटर और इसके सिस्टम के विनिर्माण में प्रयोग हेतु सोलर स्लेक्टिव की तीन तहों वाले इवेक्यूएटिड ट्यूब-शून्य।
13. नवीकरणीय विद्युत प्रणाली (आरपीएस) इन्वर्टरों के विनिर्माण में प्रयोग हेतु एक्टिव एनर्जी कंट्रोलर (ईसी), एमएनआरई द्वारा प्रमाणन के अध्वधीन 5%।

14. टेबलेट कम्प्यूटर के विनिर्माण में प्रयोग हेतु कल पुर्जे और सहायक पुर्जे तथा इन कलपुर्जों और सहायक पुर्जों के विनिर्माण में प्रयोग हेतु उनके उप-हिस्से बीसीडी, सीवीडी और एसएडी से पूर्णतया छूट दी जा रही है।

III. सेनवैट क्रेडिट संग्रहण की समस्या के समाधान हेतु एसएडी में कमी

1. आईटीए बाउंड सामान के विनिर्माण में प्रयोग हेतु सीमाशुल्क टैरीफ के किसी अध्याय में आने वाले पापुलेटिड पीसीबी के सिवाय सभी सामान 4% से शून्य
2. उत्पाद शुल्क योग्य सामानों के विनिर्माण हेतु नापथा, एथीलीन डाइक्लोराइड (इडीसी), विनाईल क्लोराइड मोनोमेट (वीसीएम) और स्टाइरेन मोनोमेट (एसएम) 4% से 2%
3. लोहा व इस्पात; कापर, ब्रास और एल्यूमिनियम का धातु स्क्रैप 4% से 2%
4. एलईडी ड्राइवर, एलईडी लाइट के लिए एमसीपीईबी, फिक्सचर्स और एलईडी लैम्प के विनिर्माण में प्रयोग हेतु निविष्टियां 4% से शून्य।

IV. बुनियादी सीमा शुल्क में वृद्धि:

1. धातुकर्म कोक 2.5% से 5%
2. सीमाशुल्क टैरीफ के अध्याय 72 और 73 के अंतर्गत आने वाले लोहा और इस्पात तथा लोहे या इस्पात पर टैरीफ दर 10% से 15%। हालांकि, इन वस्तुओं पर बुनियादी सीमा शुल्क की विद्यमान प्रभावी दरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
3. वाणिज्यिक वाहनों पर टैरीफ दर 10% से 40% और प्रभावी दर 10% से 20%। हालांकि, पूरी तरह टूटे हुए वाहनों के वाणिज्यिक श्रेणी और पूरी तरह टूटे हुए वाहनों सहित बिजली चलित वाहनों पर सीमा शुल्क 10% जारी रहेगा।

V. विविध:

1. उन्नत इलमेनाइट पर निर्यात शुल्क 5% से घटाकर 2.5% किया जा रहा है।
2. सेलूलर फोनों सहित मोबाइल हैंडसेटों के लिए उत्पाद शुल्क संरचना बदली जा रही है। बिना सेनवैट क्रेडिट 1% अथवा सेनवैट क्रेडिट के साथ 6% से बिना सेनवैट क्रेडिट 1% अथवा सेनवैट क्रेडिट के साथ 12.5%
3. टेबलेट कम्प्यूटर्स के लिए उत्पाद शुल्क ढांचा सेनवैट क्रेडिट के बगैर 2% अथवा सेनवैट क्रेडिट के साथ 12.5% पर निर्दिष्ट किया जा रहा है।
4. डिजिटल स्टिल इमेज विडियो कैमरा जो अधिकतम भंडारण क्षमता (विस्तृत सहित) का प्रयोग करके, एक

बार में कम से कम 30 मिनट के लिए, न्यूनतम 23 फ्रेम प्रति सैकेंड पर, 800x600 पिक्सल की न्यूनतम विन्यास के साथ विडियो रिकॉर्डिंग करने में समर्थ हो, पर आधारभूत सीमा शुल्क शून्य कर दिया गया है। इन कैमरों के हिस्सों और पुर्जों पर आधारभूत सीमा शुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य किया जा रहा है।

5. विद्युत प्रचालित वाहनों और हाइब्रिड वाहनों के विनिर्दिष्ट भागों पर 6 प्रतिशत सीवीडी और शून्य एसएडी, शून्य आधारभूत सीमा शुल्क की रियायती सीमा शुल्क संरचना जो वर्तमान में 31.03.2015 तक उपलब्ध है को बढ़ाकर 31.03.2016 तक किया जा रहा है।

उत्पाद शुल्क

I. कतिपय वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क संरचना की पुनर्संरचना निम्नानुसार की जा रही है:

1. स्मार्ट कार्ड के लिए एकीकृत सर्किट (आईसी) के विनिर्माण में प्रयोग के लिए वेफरों पर 12% से 6%
2. एलईडी लाइटों, फिक्चर्स और एलईडी लैम्पों के लिए एईडी ड्राइवरों और एमसीपीसीबी के विनिर्माण में प्रयोग किए जाने वाले इंपुटों पर 12% से 6%
3. सेल्यूलर फोनों सहित मोबाइल हैंडसेटों पर सेनवैट क्रेडिट रहित 1% अथवा सेनवैट क्रेडिट सहित 6% से सेनवैट क्रेडिट रहित 1% अथवा सेनवैट क्रेडिट सहित 12.5%। सेल्यूलर फोनों सहित मोबाइल हैंडसेटों पर 1% की एनसीसीडी में कोई परिवर्तन नहीं है।
4. टेबलेट कम्प्यूटर्स पर सेनवैट क्रेडिट रहित 12% से 2% अथवा सेनवैट क्रेडिट सहित 12.5%
5. पेसमेकर्स के विनिर्माण में प्रयोग किए जाने वाले विनिर्दिष्ट कच्चे माल [बैटरी, टाइटेनियम, पल्लाडियम, तार, यूटेक्टिक तार, सिलिकान रोल और रबड़, सोलडर पेस्ट, रीड स्विच, डाटाडस, ट्रांजिस्टर्स, कैपेस्टिर्स नियंत्रकों, कॉयल (स्टील, ट्यूबिंग (सिलिकान))] पर शून्य।
6. एमएनआरई द्वारा प्रमाणन के अध्यक्षीन, पवन प्रचालित विद्युत जनरेटरों की ढलाई घटकों के विनिर्माण में प्रयोग होने वाले पिग आयरन एसजी ग्रेड और फेर्रो-सिलिकान-मैगनेशियम पर शून्य।
7. सौलर वाटर हीटर और सिस्टम पर सेनवैट क्रेडिट रहित 12% से शून्य अथवा सेनवैट क्रेडिट सहित 12.5%।
8. इलैक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिक विभाग द्वारा प्रमाणन के अध्यक्षीन सौलर पीवी सेलों के विनिर्माण हेतु सौलर पीवी रिबन के विनिर्माण में प्रयोग होने वाली राउंड कॉपर तार और टिन मिश्रितों पर शून्य।

II. विविध:

1. 1000 रुपए प्रति जोड़ी से अधिक के खुदरा बिक्री मूल्य चमड़े के जूतों (ऐसे जूते जिनका ऊपरी भाग 4107 या 4112 से 4114 हेडिंग के चमड़े से बना हो) पर 12% से 6%।
2. रेलवे अथवा ट्रामवे के ट्रैक निर्माण के माल पर रेलों को अदा किए गए शुल्क के मूल्य पर, यदि ऐसी रेलों को अदा किए गए शुल्क पर सेनवैट क्रेडिट का लाभ न लिया हो, तो उद्ग्रहीत उत्पाद शुल्क पर 17.03.2012 से 02.02.2014 की अवधि के लिए भूतलक्षी प्रभाव से छूट दी जा रही है।

ख. व्यवसाय को सुकर बनाने के लिए सुधार के लिए न्यूनतम सरकार और अधिकतम अभिशासन**I. उद्ग्रहणों की संख्या में कमी****उत्पाद शुल्क**

1. उत्पादन शुल्क योग्य वस्तुओं पर उद्ग्रह किए जाने वाले शिक्षा उप कर और माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा उपकर को आधारभूत उत्पाद शुल्क में शामिल किया जा रहा है। परिणामस्वरूप, उत्पादन शुल्क योग्य वस्तुओं पर उद्ग्रह किए जाने वाले शिक्षा उप कर और माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा उपकर पर पूर्णतया छूट दी जा रही है। आधारभूत उत्पाद शुल्क की मानक यथा मूल्य दर 12% से बढ़ाकर 12.5% की जा रही है और पेट्रोल, डीजल, सीमेंट, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों (बीड़ी को छोड़कर) पर आधारभूत उत्पाद शुल्क की विशिष्ट दरों में उचित रूप से परिवर्तन किया जा रहा है। **तथापि, पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद के विभिन्न शुल्कों के कुल प्रभाव में कोई परिवर्तन नहीं होगा।** कुछ अपवादों को छोड़कर अन्य आधारभूत उत्पाद शुल्क दरों (यथा मूल्य तथा विनिर्दिष्ट) में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क, शिक्षा उप कर उद्ग्रहित किया जाता रहेगा।

II. उत्पाद शुल्क उद्ग्रह के प्रयोजनों के लिए वस्तुओं के मूल्यांकन में निश्चितता और समरूपता सुनिश्चित करना:

1. आइस टी सहित अध्याय उप-शीर्ष 210120 के अंतर्गत आने वाली सभी वस्तुएं 30% की कटौती के साथ खुदरा बिक्री मूल्य के संदर्भ में केंद्रीय उत्पाद शुल्क के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 4क के अंतर्गत अधिसूचित की जा रही हैं। ऐसी वस्तुओं को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की तीसरी अनुसूची में भी शामिल किया जा रहा है।
2. नींबू शरबत और अन्य पेय पदार्थों जैसी वस्तुएं 35% की कटौती के साथ खुदरा बिक्री मूल्य के संदर्भ में केंद्रीय उत्पाद-शुल्क के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 4क के अंतर्गत अधिसूचित की जा रही हैं। ऐसी वस्तुएं केंद्रीय उत्पाद

शुल्क अधिनियम, 1944 की तीसरी अनुसूची में भी शामिल की जा रही हैं।

III. अनुपालन सुगमीकरण:

1. दो कार्यदिवसों के भीतर ऑनलाइन केंद्रीय उत्पाद शुल्क/सेवा कर पंजीकरण
2. निविष्टि और निविष्टि सेवाओं पर सेनवैट क्रेडिट लेने की समय-सीमा छह माह से बढ़ाकर एक वर्ष की जा रही है।
3. पंजीकृत डीलरों से विक्रेताओं से ग्राहक के परिसर तक वस्तुओं के प्रत्यक्ष प्रेषण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। रोजगार कामगारों के संबंध में भी इसी प्रकार की सुविधा अनुमत की जा रही है। पंजीकृत आयातकर्ता भी प्रत्यक्ष रूप से ग्राहक को आयात करने वाले पत्तन से वस्तुएं भेज सकता है।
4. सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर में शास्ति के प्रावधानों का यौक्तिकीकरण अनुपालन और शीघ्र विवाद समाधान को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है।
5. केंद्रीय उत्पाद/सेवाकर निर्धारितियों करदाताओं को डिजिटल तौर पर तैयार हस्ताक्षरित बीजक जारी करने और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकार्डों के रख-रखाव करने की अनुमति दी जा रही है।

IV. विविध:

1. प्रविष्टि 'जल' में वित्त अधिनियम, 2005 की सातवीं अनुसूची में शामिल खनिज जल (मिनरल वॉटर) तथा चीनी युक्त और मीठे तथा अन्य सुगन्धित सामग्री युक्त वातित जल है जिन पर @ 5% की दर से लगने वाली अतिरिक्त ड्यूटी की लेवी हटाई जा रही है। इसी प्रकार इन वस्तुओं पर मूल उत्पाद शुल्क 12% से बढ़ाकर 18% किया जा रहा है।
2. एम्बुलेंसों के चेसिस पर उत्पाद शुल्क 24% से घटाकर 12.5% किया जा रहा है।

ग. स्वच्छ भारत कार्यक्रमों के जरिए जीवन की गुणवत्ता और जन स्वास्थ्य सुधारना**सीमा और उत्पाद शुल्क**

1. कोयला, लिग्नाइट और पीट पर वसूले जा रहे स्वच्छ ऊर्जा उपकर की अनुसूचित दर को ₹100 प्रति टन से बढ़ा कर ₹300 प्रति टन किया जा रहा है। स्वच्छ ऊर्जा उपकर की लागू दर की ₹100 प्रतिटन से बढ़ाकर ₹200 प्रतिटन किया जा रहा है।
2. इलेक्ट्रिकल तौर पर चलने वाले वाहनों तथा हार्डब्रीड

वाहनों के विनिर्दिष्ट पुर्जों पर लगने वाली रियायती उत्पाद तथा सीमाशुल्क, जो कि अभी 31.03.2015 तक विद्यमान था, को बढ़ाकर 31.03.2016 तक किया जा रहा है।

3. औद्योगिक उपयोगी से परे पालीसर एथिलीन के थैलों और बोरों पर लगने वाले उत्पाद शुल्क के 12% से बढ़ाकर 15% किया जा रहा है।

सेवा कर

1. सभी अथवा कतिपय कर योग्य सेवाओं पर ऐसी कर योग्य सेवाओं के मूल्य पर एक स्वच्छ भारत उपकर लगाने में केन्द्रीय सरकार को सक्षम बनाने की दृष्टि से एक समर्थकारी उपबन्ध तैयार किया जा रहा है। इस उपकर से अर्जित राशि को स्वच्छ भारत की नवोन्मेषी पहलों पर खर्च किया जाएगा। यह उपकर अधिसूचना की तिथि से लागू होगा।
2. कामन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट आपरेटर द्वारा एफ्लुएंट ट्रीटमेंट के लिए उपलब्ध क्षेत्रों को छूट प्रदान की जा रही है।

घ. अर्थव्यवस्था में लाभों को अधिकतम करने के अनोखे प्रस्ताव

घ.1. कराधार को व्यापक बनाना

उत्पाद शुल्क

1. यूनिट कन्टेनरों में पैक संघनित कन्डेंस्ड दुग्ध पर सेनवेट क्रेडिट के बिना 2% अथवा सेनवेट क्रेडिट के साथ 6% की उत्पाद शुल्क लिया जा रहा था। इसे खुदरा बिक्री मूल्य के संदर्भ में मूल्यांकन किए जाने के प्रयोजन से 30% की कमी के साथ केन्द्रीय उत्पाद कर अधिनियम की धारा 4क के अधीन अधिसूचित किया जा रहा है।
2. मूंगफली मक्खन पर सेनवैट रहित 2% पर सेनेवैट क्रेडिट सहित 6% की दर से उत्पाद शुल्क लगाया जा रहा है।

सेवा कर

1. सेवा कर दरों में परिवर्तन

- (1) सेवा कर दर की 12% और शिक्षा उपकर से बढ़ाकर 14% किया जा रहा है। नई सेवा कर दर में 'शिक्षा उपकर' और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर' शामिल होगा। संशोधित दर अधिसूचना की तारीख से लागू होगी।

II ऋणात्मक सूची की समीक्षा

- (1) राइड, बाउलिंगऐल, ऐम्युजमेंट आर्केड, वाटर पार्क, थीम पाई आदि जैसी आमोद-प्रमोद की सुविधाएं प्रदान करके की जाने वाली सेवाओं पर की वसूली।

- (2) कन्सर्टों, गैर-मान्यता प्राप्त स्पोर्टिंग इवेन्ट, पेजेन्ट, म्युजिक कन्सर्ट और अवार्ड फंक्शनों में प्रवेश, यदि प्रवेश हेतु वसूली जाने वाली राशि 500 रुपए से अधिक हो, द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा पर सेवाकर की वसूली सिनेमैटोग्राफिक फिल्म, सर्कस, नृत्य, या नाटक, गीतनाटिका या मान्यता प्राप्त खेल कार्यक्रमों के प्रदर्शन में प्रवेश द्वारा सेवा पर छूट जारी रहेगी।

- (3) मानव खपत हेतु मादक द्रव्य के उत्पादन या विनिर्माण हेतु जॉब वर्क के रूप में किसी प्रक्रिया को करके दी जाने वाली सेवा पर सेवाकर की वसूली

- (4) ऋणात्मक सूची से किसी व्यावसायिक निकाय की सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं को अलग रखने के लिए एक समर्थकारी उपबंध किया जा रहा है। इस संशोधन को लागू कर दिए जाने पर सरकार द्वारा व्यावसायिक निकायों को प्रदान की जाने वाली सभी सेवाएं यदि विशेष रूप से छूट नहीं दी गई तो, तो वे कर योग्य हो जाएंगी।

III सामान्य छूट की समीक्षा

- (1) सरकार को प्रदान की जाने वाली निर्माण, सिविल संरचनाओं की मरम्मत आदि की विशिष्ट सेवाओं पर वर्तमान में उपलब्ध छूट केवल निम्नलिखित तक सीमित होगी:

(क) ऐतिहासिक स्मारक, पुरातात्विक महत्व की इमारतें या स्थल

(ख) नहर, बांध या अन्य सिंचाई संरचना;

(ग) (i) जल आपूर्ति (ii) जल उपचार या (iii) मल-जल उपचार या निबटान हेतु पाइपलाइन, कन्डिड या संयंत्र।

- (2) हवाई अड्डा या पत्तन से संबंधित मूल संरचनाओं को निर्मित करने, संरचित करने, चालू करने या संस्थापित करने पर कर छूट समाप्त की जा रही है।

- (3) (i) संगीत या (ii) नृत्य या (iii) थियेटर के रूप में लोक कला या क्लासिक की कला में परफॉर्म करने वाले कलाकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए छूट केवल ऐसे मामलों तक सीमित की जाएगी जिनमें प्रति परफॉर्मर्स (ब्रांड एम्बेस्डर) को छोड़कर वसूली गयी राशि 1,00,000 रुपए तक हो।

- (4) रेल या पोत या सड़क मार्ग से खाद्य सामग्रियों की ढुलाई के लिए छूट केवल चावल और दाल, आटा, दूध और नमक सहित खाद्यान्नों की ढुलाई तक ही सीमित होगी। कृषि उत्पादों की ढुलाई पर अलग से छूट दी गई है जो जारी रखी जाएगी।

(5) निम्नलिखित सेवाओं पर छूट हटाई जा रही है:

(क) किसी म्युचुअल फंड एजेंट द्वारा किसी म्युचुअल फंड या आस्ति प्रबंधन कंपनी को प्रदान की गई सेवाएं;

(ख) म्युचुअल फंड के वितरक या एएमसी प्रदाता; और

(ग) एजेंट द्वारा लॉटरी के वितरक को लॉटरी टिकट का विक्रय या विपणन

(6) निम्नलिखित सेवाओं पर छूट हटाई जा रही है:

(क) विभागीय स्तर पर संचालित सार्वजनिक टेलीफोन

(ख) केवल स्थानीय कॉलों को संचालित करने वाले गारंटीशुदा सार्वजनिक टेलीफोन

(ग) निःशुल्क टेलीफोन से हवाई अड्डा या अस्पताल को टेलीफोन करके सेवा प्रदान करना जिसके लिए कोई बिल जारी नहीं किया जाता।

(7) भारत से बाहर स्थित किसी कमीशन एजेंट द्वारा भारत में स्थित किसी निर्यातक को प्रदत्त सेवा पर मौजूदा छूट समाप्त की जा रही है। पूर्ववर्ती बजट में कानून में किए गए संशोधन जिसके द्वारा ऐसे एजेंटों द्वारा प्रदत्त सेवाएं कर नेट से बाहर कर दी गई हैं, को देखते हुए यह छूट अतिरिक्त हो चुकी है।

(घ) II राहत उपाय:

सीमाशुल्क

(1) कृत्रिम हृदय (बायें निलय के लिए सहायक उपकरण) को 5% के बुनियादी सीमाशुल्क और सीबीडी से छूट प्रदान की जाए।

उत्पाद शुल्क

(1) अगरबत्तियों के विनिर्माण के दौरान प्राप्त होने वाले विशेष तौर पर प्रयोग में लाये जाने वाले मध्यवर्ती यौगिक पदार्थ के लिए उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की जा रही है। अगरबत्तियों पर उत्पाद शुल्क शून्य है।

सेवा कर

(1) फलों और सब्जियों के पूर्व-अनुकूलन, पूर्व शीतलन, पक्कन, वैक्सिंग खुदरा पैकिंग, लेबलिंग की सेवाओं को कर से छूट दी जा रही है।

(2) वीएस पेंशन बीमा योजना द्वारा प्रदत्त जीवन बीमा सेवा को कर से छूट दी जा रही है।

(3) प्रदर्शक/थियेटर के स्वामी द्वारा वितरक या प्रदर्शक में निहित व्यक्तियों के एसोसिएशन जो प्रदर्शन में निधि एक सदस्य हो, के समक्ष चलचित्र के प्रदर्शन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा को कर से छूट दी जा रही है।

(4) रोगियों को प्रदान की जा रही सभी ऐम्बुलेन्स सेवाओं को कर से छूट दी जा रही है।

(5) संग्रहालय, चिडियाघर, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण और व्याघ्र आरक्षित अभ्यारण में प्रवेश के रूप में दी जाने वाली सेवा को छूट दी जा रही है।

(6) कारखाना से सड़क द्वारा निर्यात के लिए भूमि सीमा शुल्क केन्द्र ले जाई जाने वाली वस्तु को छूट दी जा रही है।

घ. III अवसंरचना के लिए अतिरिक्त संसाधनों का आबंटन

उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क

(1) पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल तेल पर लगाए जाने वाले अतिरिक्त सीमाशुल्क/उत्पाद शुल्क (सामान्यतः सड़क उपकरण के रूप में जाना जाता है) की अनुसूचित दरें 2 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 8 रुपए प्रति लीटर की जा रही है। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क (सामान्यतः सड़क उपकरण के रूप में जाना जाता है) की प्रभावी दरों को बढ़ाकर 2 रुपए प्रति लीटर से 6 रुपए प्रति लीटर किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल तेल पर (ब्रांडिड और गैर-ब्रांडिड दोनों) बुनियादी उत्पाद शुल्क दरों को 4 रुपए प्रतिलीटर कम किया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल पर बुनियादी उत्पाद शुल्क दरों को उपयुक्त रूप से बढ़ाया जा रहा है ताकि उनपर वर्तमान में लगाए जाने वाले शिक्षा उपकरण और माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा उपकरण को आमेहित किया जा सके। इस प्रकार से ब्रांडिड पेट्रोल पर बुनियादी उत्पाद शुल्क में निवल कटौती 3.46 रुपए प्रति लीटर गैर-ब्रांडिड पेट्रोल पर 3.49 रुपए प्रति लीटर, ब्रांडिड डीजल पर 3.63 रुपए प्रति लीटर और गैर ब्रांडिड डीजल पर 3.70 रुपए प्रति लीटर है। तथापि, पेट्रोल और डीजल पर कुल भार अपरिवर्तित है।

घ. IV जन सवास्थ्य का संवर्धन

उत्पाद शुल्क

(1) 65 मि.मी. से अनधिक लम्बाई वाले सिगरेट के लिए सिगरेट पर उत्पाद शुल्क 25% और अन्य लम्बाई के सिगरेट पर 15% बढ़ाया जा रहा है सिगार, चुरुट और सिगारिलोस पर इसी प्रकार की बढ़ोत्तरी करने का प्रस्ताव है।

- (2) वर्तमान में पान मसाला, गुटखा और चबाने वाले तम्बाकू पर लागू मिश्रित लेबी स्कीम के अंतर्गत देय उत्पाद शुल्क का निर्धारण करने के लिए उत्पादन के लिए संगत कारक के रूप में पैकिंग मशीन की अधिकतम गति विनिर्दिष्ट की जा रही है। तदनुसार गति के दायरे के संदर्भ में, जिसमें पैकिंग मशीन की अधिकतम गति आती है, उत्पादन और प्रति मशीन प्रतिमाह देय शुल्क को अधिसूचित किया जा रहा है।

घ.व सेवा कर से संबंधित अन्य उपाय

1. वित्त अधिनियम, 1994 में परिवर्तन

1. "सरकार" शब्द की परिभाषा अधिनियम में शामिल की जा रही है ताकि नकारात्मक सूची और सेवा कर में छूट के संदर्भ में इस शब्द की के क्षेत्र के संबंध में व्याख्यात्मक समस्याओं का समाधान किया जा सके।
2. निम्नलिखित पर कर लगाने के लिए विधायिका के आशय को विशिष्टरूप से बताने हेतु "सेवा" शब्द की परिभाषा में संशोधन करना:
 - i. चिट के संचालन द्वारा चिट फंड फोरमैन; और
 - ii. किसी लाटरी के आयोजन और संचालन के लिए राज्य के संवर्धन, विपणन, वितरण, बिक्री, या किसी अन्य तरीके से सहायता करने के लिए आयोजक राज्य द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत लाटरी का वितरक या बिक्री अभिकर्ता।
3. अधिनियम में यह विशिष्ट रूप से निर्धारित किया जा रहा है कि किसी करयोग्य सेवा के मूल्य में विधिक स्थिति को स्पष्ट करने और विवादों से बचने के लिए सेवा प्रदाता द्वारा की गई अथवा प्रभारित कोई प्रतिपूरणीय लागत या व्यय शामिल होगा।
4. अधिनियम की धारा 66च यह निर्धारित करती है कि जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो तब तक किसी सेवा के संदर्भ में, ऐसी सेवा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किसी इनपुट सेवा का संदर्भ सम्मिलित नहीं होगा। इस उपबंध के कार्यक्षेत्र को निर्देशित करने के लिए इस खंड में एक उदाहरण समाविष्ट किया जा रहा है।

2. उपशमन का यौक्तिकीकरण

1. रेल, सड़क और पोत द्वारा परिवहन क्षेत्रों में समानता लाने के लिए इन क्षेत्रों हेतु एक एक समान उपशमन निर्धारित किया जा रहा है। इनपुट, पूंजीगत वस्तुओं और इनपुट सेवाओं पर सेनवैट क्रेडिट का लाभ न उठाने की एकसमान शर्त के अध्याधीन ऐसी सेवा के 30 प्रतिशत मूल्य पर सेवाकर देय होगा। वर्तमान में, रेल परिवहन के

मामले में 30 प्रतिशत मूल्य, सड़क परिवहन के मामले में 25 प्रतिशत मूल्य और पोतों द्वारा परिवहन के मामले में 40 प्रतिशत मूल्य पर कर देय है।

2. एकजक्यूटिव (कारोबार/प्रथम श्रेणी) हवाई यात्रा, जिसमें सेवा का घटक उच्चतर है, मैं उपशमन को 60 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत किया जा रहा है। परिणामतः, कारोबार श्रेणी के लिए भाड़ा मूल्य के 60 प्रतिशत पर सेवा कर देय होगा।
3. चिट फंड सेवा पर उपशमन को वापस लिया जा रहा है।

3. सेवा कर नियम

1. संकलनकर्ता मॉडल के अधीन प्रदान की गई किसी सेवा के संदर्भ में, संकलनकर्ता को सेवाकर की अदायगी हेतु उत्तरदायी माना जा रहा है। यदि किसी भी तरह संकलनकर्ता के ब्रांड नाम का प्रयोग करके सेवा प्रदान की जाती है।
2. सेवाकर दर में ऊर्ध्वगामी संशोधन के परिणामस्वरूप, विनिर्दिष्ट सेवाओं, अर्थात्, जीवन बीमा सेवा, हवाई यात्रा अभिकर्ता सेवाओं, बैंकों या प्राधिकृत डीलरों द्वारा प्रदत्त धन परिवर्तन सेवा, और लाटरी वितरण तथा बिक्री अभिकर्ता द्वारा प्रदत्त सेवा पर विन्यास दर को आनुपातिक रूप से संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है।

4. परावृत प्रभार प्रणाली

1. जब किसी निकाय कार्पोरेट को व्यक्ति विशेष हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब; साझेदारी वाले प्रतिष्ठान द्वारा जनशक्ति आपूर्ति और सुरक्षा सेवाएं प्रदान की गई हैं तो उन्हें सरलीकरण उपाय के रूप में पूर्ण परावृत प्रभार के तहत लाया जा रहा है। वर्तमान में, इन पर आंशिक परावृत प्रभार प्रणाली के तहत कर लगाया जाता है।
2. म्यूचुअल फंड अभिकर्ताओं, म्यूचुअल फंड वितरकों और लाटरी अभिकर्ताओं द्वारा प्रदत्त सेवाओं को ऐसी सेवाओं पर छूट वापस ले लेने के परिणामस्वरूप परावृत प्रभार के तहत लाया जा रहा है।

5. सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004

सेवा प्राप्त कर्ता द्वारा आंशिक परावृत प्रभार के तहत अदा किए गए सेवा कर को व्यापार को सुकर बनाने के उपाय के रूप में सेवा प्रदाता को सेवा मूल्य की अदायगी से जोड़े बिना क्रेडिट की अनुमति प्रदान करने के लिए सेनवैट क्रेडिट नियमावली में संशोधन किए जा रहे हैं।

डॉ. रजत भार्गव, संयुक्त सचिव (बजट)

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(BUDGET DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2015

F. No.2(2)/2015-B(D).—The following is published for general information :—

Budget 2015-2016

Speech of Arun Jaitley Minister of Finance

28th February, 2015

Madam Speaker,

I rise to present the Budget of the Union for the year 2015-16.

2. I present this Budget in an economic environment which is far more positive than in the recent past. When other economies are facing serious challenges, India is about to take-off on a faster growth trajectory once again. The International Monetary Fund (IMF) has downgraded its earlier forecast of global economic growth by 0.3%, and the World Trade Organization has revised its forecast of world trade growth from 5.3% to 4%. Forecasts for India, however, have either been upgraded, or remained the same, without downgrades. Madam Speaker, we have also embraced the States as equal partners in the process of economic growth. States have been economically empowered more than ever before and it is my belief that every rupee of public expenditure, whether undertaken by the Centre or the States, will contribute to the betterment of people's lives through job creation, poverty elimination and economic growth.

3. In the last nine months, the NDA Government headed by Prime Minister Shri Narendra Modi, has undertaken several significant steps to energise the economy. The credibility of the Indian economy has been re-established. The world is predicting that it is India's chance to fly.

Kuch to phool khilaye humne, aur kuch phool
khilane hai

Mushkil yeh hai bag me ab tak, kaante kai
purane hai

4. Though the Union Budget is essentially a Statement of Account of public finances, it has historically become a significant opportunity to indicate the direction and the pace of India's economic policy. My proposals, therefore, lay out the roadmap for

accelerating growth, enhancing investment and passing on the benefit of the growth process to the common man, woman, youth and child: those, whose quality of life needs to be improved. This is the path which we will doggedly and relentlessly pursue. As the Prime Minister has often said, we are a round-the-clock, round-the-year Government.

5. Madam, allow me to describe the changes in the Indian economy since we first took office. In November, 2012, CPI inflation, stood at 11.2%, the current account deficit by the first quarter of 2013-14 had reached 4.6% of GDP, and normal foreign inflows until March 2014 were \$15 billion. We inherited a sentiment of, if I may say so, doom and gloom, and the investor community had almost written us off.

6. We have come a long way since then. The latest CPI inflation rate is 5.1%, and the wholesale price inflation is negative; the current account deficit for this year is expected to be below 1.3% of GDP; based on the new series, real GDP growth is expected to accelerate to 7.4%, making India the fastest growing large economy in the world; foreign inflows since April 2014 have been about \$55 billion, so that our foreign exchange reserves have increased to a record \$340 billion; the rupee has become stronger by 6.4% against a broad basket of currencies; and ours was the second-best performing stock market amongst the major economies. In short, Madam Speaker, we have turned around the economy dramatically, restoring macro-economic stability and creating the conditions for sustainable poverty elimination, job creation and durable double-digit economic growth. Domestic and international investors are seeing us with renewed interest and hope.

7. While being mindful of the challenges, Madam Speaker, this gives us reason to feel optimistic. With all the humility at my command, I submit that this opportunity has arisen because we have created it. The people of India had voted resoundingly for quick change, faster growth and highest levels of transparency. They wanted the scam, scandal and corruption Raj to end. They wanted a Government in which they can trust. We have lived up to that trust.

8. Our actions have not been confined to the core or macro-economic areas alone. Illustratively, action has been taken with regard to allocation of natural resources; financial inclusion; health and hygiene of the common man; girls and their education; employment for the youth; improved and non-adversarial tax administration; effective delivery of benefits; investment and job creation; welfare of

labour; agricultural productivity and increasing farm incomes; power; digital connectivity; skilling our youth; efficient and better work culture in Government; ease of doing business; mainstreaming North Eastern States; and, reviving our pride in the nation and culture. I am giving the details in an Annexure to this speech.

9. Madam Speaker, of the work that we have done, I would like to talk of three achievements as they demonstrate the quality and conviction of our government. One is the success of the Jan Dhan Yojana. Financial inclusion has been talked about for decades now. Who would have thought that in a short period of 100 days, over 12.5 crore families could have been brought into the financial mainstream? The other is coal auctions. Earlier, the States only got benefits of royalty. Now, by the transparent auction process that we are carrying out, the coal bearing States will be getting several lakh of crore of rupees which they can use for creation of long awaited community assets and for welfare of their people.

10. The third is 'Swachh Bharat' which we have been able to transform into a movement to regenerate India. I can speak of, for example, the 50 lakh toilets already constructed in 2014-15, and I can also assure the Members of this august House that we will indeed attain the target of building six crore toilets. But, Madam, Swachh Bharat is not only a programme of hygiene and cleanliness but, at a deeper level, a programme for preventive health care, and building awareness.

11. We are now embarked on two more game changing reforms. GST and what the Economic Survey has called the JAM Trinity – Jan Dhan, Aadhar and Mobile – to implement direct transfer of benefits. GST will put in place a state-of-the-art indirect tax system by 1st April, 2016. The JAM Trinity will allow us to transfer benefits in a leakage-proof, well-targeted and cashless manner.

12. Madam Speaker, one of the major achievements of my government has been to conquer inflation. This decline, in my view, represents a structural shift. Going forward, we expect CPI inflation to remain at close to 5% by the end of the year. This will allow for further easing of monetary policy.

13. To ensure that our victory over inflation is institutionalized and hence continues, we have concluded a Monetary Policy Framework Agreement with the RBI, as I had promised in my Budget Speech for 2014-15. This Framework clearly states the

objective of keeping inflation below 6%. We will move to amend the RBI Act this year, to provide for a Monetary Policy Committee.

14. The Central Statistics Office has recently released a new series for GDP, which involves a number of changes relative to the old series. Based on the new series, estimated GDP growth for 2014-15 is 7.4%. Growth in 2015-16 is expected to be between 8 to 8.5%. Aiming for a double-digit rate seems feasible very soon.

15. I now come to the task ahead of us. In respect of social and economic indicators, for seven decades now, we have worked in terms of percentages, and numbers of beneficiaries covered. It is quite obvious that incremental change is not going to take us anywhere. We have to think in terms of a quantum jump.

16. The year 2022 will be the Amrut Mahotsav, the 75th year, of India's independence. The vision of what the Prime Minister has called 'Team India', led by the States and guided by the Central Government, should include:

- (i) A roof for each family in India. The call given for 'Housing for all' by 2022 would require Team India to complete 2 crore houses in urban areas and 4 crore houses in rural areas.
- (ii) Each house in the country should have basic facilities of 24-hour power supply, clean drinking water, a toilet, and be connected to a road.
- (iii) At least one member from each family should have access to the means for livelihood and, employment or economic opportunity, to improve his or her lot.
- (iv) Substantial reduction of poverty. All our schemes should focus on and centre around the poor. Each of us has to commit ourselves to this task of eliminating absolute poverty.
- (v) Electrification, by 2020, of the remaining 20,000 villages in the country, including by off-grid solar power generation.
- (vi) Connecting each of the 1,78,000 unconnected habitations by all

- weather roads. This will require completing 1,00,000 km of roads currently under construction plus sanctioning and building another 1,00,000 km of road.
- (vii) Good health is a necessity for both quality of life, and a person's productivity and ability to support his or her family. Providing medical services in each village and city is absolutely essential.
- (viii) Educating and skilling our youth to enable them to get employment is the altar before which we must all bow. To ensure that there is a senior secondary school within 5 km reach of each child, we need to upgrade over 80,000 secondary schools and add or upgrade 75,000 junior/middle, to the senior secondary level. We also have to ensure that education improves in terms of quality and learning outcomes.
- (ix) Increase in agricultural productivity and realization of reasonable prices for agricultural production is essential for the welfare of rural areas. We should commit to increasing the irrigated area, improving the efficiency of existing irrigation systems, promoting agro-based industry for value addition and increasing farm incomes, and reasonable prices for farm produce.
- (x) In terms of communication, the rural and urban divide should no longer be acceptable to us. We have to ensure connectivity to all the villages without it.
- (xi) Two-thirds of our population is below 35. To ensure that our young get proper jobs, we have to aim to make India the manufacturing hub of the world. The Skill India and the Make in India programmes are aimed at doing this.
- (xii) We also have to encourage and grow the spirit of entrepreneurship in India and support new start-ups. Thus can our youth turn from being job-seekers, to job-creators.

- (xiii) The Eastern and North Eastern regions of our country are lagging behind in development on many fronts. We need to ensure that they are on par with the rest of the country.

17. By the time of the 75th year of Indian independence, Amrut Mahotsav of our independence is reached, we have to achieve all of the above, so that India becomes a prosperous country; and a responsible global power. This will be our true and meaningful tribute to our freedom fighters.

Major Challenges Ahead

18. As I stated earlier, Madam Speaker, I am also mindful of the five major challenges I have to reckon with. Firstly, Agricultural incomes are under stress. Our second challenge is increasing investment in infrastructure. With private investment in infrastructure via the public private partnership (PPP) model still weak, public investment needs to step in, to catalyse investment.

19. Our third major challenge is that manufacturing has declined from 18% to 17% of GDP as per new GDP data; and manufacturing exports have remained stagnant at about 10% of GDP. The Make in India programme is aimed at meeting this challenge, thus creating jobs.

20. Fourth, we need to be mindful of the need for fiscal discipline in spite of rising demands for public investment. In keeping with the true spirit of co-operative federalism, we have devolved a 42% share of the divisible pool of taxes to States. As members of this august House are aware, this is an unprecedented increase which would empower states with more resources. The devolution to the States would be of the order of ₹5.24 lakh crore in 2015-16 as against the devolution of ₹3.38 lakh crore as per revised estimates of 2014-15. Another ₹3.04 lakh crore would be transferred by way of grants and plan transfers. Thus, total transfer to the States will be about 62% of the total tax receipts of the country.

21. In spite of the consequential reduced fiscal space for the Centre, the Government has decided to continue supporting important national priorities such as agriculture, education, health, MGNREGA, and rural infrastructure including roads. Programmes targeted for the poor and the under-privileged, will be continued by us.

22. With fiscal space not just reduced but squeezed, I have to meet the fifth challenge of maintaining fiscal discipline. Economic growth this year, at 11.5%, was lower in nominal terms by about 2%, due to lower inflation. Consequently, tax buoyancy was also significantly lower. Despite this, Madam, I have kept my word, and we will meet the challenging fiscal deficit target of 4.1% of GDP, that we had inherited. Madam Speaker, I need to overcome these challenges to reduce and eliminate poverty.

Fiscal Roadmap

23. I want to underscore that my government still remains firm on achieving the medium term target of 3% of GDP. But that journey has to take account of the need to increase public investment. The total additional public investment over and above the RE is planned to be ₹1.25 lakh crore out of which ₹70,000 crore would be capital expenditure from budgetary outlays. We also have to take into account the drastically reduced fiscal space; uncertainties that implementation of GST will create; and the likely burden from the report of the 7th Pay Commission. Rushing into, or insisting on, a pre-set time-table for fiscal consolidation pro-cyclically would, in my opinion, not be pro-growth. With the economy improving, the pressure for accelerated fiscal consolidation too has decreased. In these circumstances, I will complete the journey to a fiscal deficit of 3% in 3 years, rather than the two years envisaged previously. Thus, for the next three years, my targets are: 3.9%, for 2015-16; 3.5% for 2016-17; and, 3.0% for 2017-18. The additional fiscal space will go towards funding infrastructure investment.

24. I am moving amendments accordingly, in the Finance Bill, to the FRBM Act.

25. Madam Speaker, I want to round up the discussion on the fiscal road map on an optimistic note. While there is a compositional shift, the aggregate envelope for job creation, poverty elimination and building infrastructure is not disturbed; in fact it goes up this year, and every subsequent year, in the same proportion as the tax revenues of the Union, and the State Governments increase. From this national perspective of public finances, not only is the path to fiscal consolidation on track, aggregate annual capital expenditure of the Governments, as a whole, can be expected to rise significantly, by more than 0.5% of GDP.

26. Madam Speaker, it may be noted that the budget reflects considerable scaling up of

disinvestment figures. This will include both disinvestment in loss making units, and some strategic disinvestment.

Good Governance

27. Madam, Speaker, this Government is committed in its resolve, as Indians, to regain our pre-eminence as a just and compassionate country. Well-intentioned schemes introduced in the past, have often been ill-targeted, riddled with leakages and delivered with inefficiency. The same is true of subsidies. Subsidies are needed for the poor and those less well off. What we need is a well targeted system of subsidy delivery. We need to cut subsidy leakages, not subsidies themselves. We are committed to the process of rationalizing subsidies based on this approach.

28. We have embarked on that path. The direct transfer of benefits, started mostly in scholarship schemes, will be further expanded with a view to increasing the number of beneficiaries from the present 1 crore to 10.3 crore. Similarly, ₹6,335 crore have so far been transferred directly, as LPG subsidy to 11.5 crore LPG consumers. I am sure, persons who are better-off, such as those in the top tax bracket, and those genuinely concerned for the welfare of the poor, such as members of this House, will give up their LPG subsidy voluntarily.

Agriculture

29. Our commitment to farmers runs deep. We have already taken major steps to address the two major factors critical to agricultural production: soil and water. An ambitious Soil Health Card Scheme has been launched to improve soil fertility on a sustainable basis. In order to improve soil health, I also propose to support Agriculture Ministry's organic farming scheme – "Paramparagat Krishi Vikas Yojana". The Pradhanmantri Gram Sinchai Yojana is aimed at irrigating the field of every farmer and improving water use efficiency to provide 'Per Drop More Crop'. I am allocating ₹5,300 crore to support micro-irrigation, watershed development and the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana. I urge the States to chip in substantially in this vital sector.

30. To support the agriculture sector with the help of effective and hassle-free agriculture credit, with a special focus on small and marginal farmers, I propose to allocate ₹25,000 crore in 2015-16 to the corpus of Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) set up in NABARD; ₹15,000 crore for Long Term Rural Credit Fund; ₹45,000 crore for Short Term

Cooperative Rural Credit Refinance Fund; and ₹ 15,000 crore for Short Term RRB Refinance Fund.

31. Farm credit underpins the efforts of our hard-working farmers. I have, therefore, set up an ambitious target of ₹8.5 lakh crore of credit during the year 2015-16 which, I am sure, the banks will surpass.

32. Our government is committed to supporting employment through MGNREGA. We will ensure that no one who is poor is left without employment. We will focus on improving the quality and effectiveness of activities under MGNREGA. I have made an initial allocation of ₹34,699 crore for the programme.

33. While the farmer is no longer in the clutches of the local trader, his produce still does not command the best national price. To increase the incomes of farmers, it is imperative that we create a National agricultural market, which will have the incidental benefit of moderating price rises. I intend this year to work with the States, in NITI, for the creation of a Unified National Agriculture Market.

Funding the Unfunded

34. Madam Speaker, our government firmly believes that development has to generate inclusive growth. While large corporate and business entities have a role to play, this has to be complemented by informal sector enterprises which generate maximum employment. There are some 5.77 crore small business units, mostly individual proprietorship, which run small manufacturing, trading or service businesses. 62% of these are owned by SC/ST/OBC. These bottom-of-the-pyramid, hard-working entrepreneurs find it difficult, if not impossible, to access formal systems of credit. I, therefore, propose to create a Micro Units Development Refinance Agency (MUDRA) Bank, with a corpus of ₹20,000 crore, and credit guarantee corpus of ₹3,000 crore. MUDRA Bank will refinance Micro-Finance Institutions through a Pradhan Mantri Mudra Yojana. In lending, priority will be given to SC/ST enterprises. These measures will greatly increase the confidence of young, educated or skilled workers who would now be able to aspire to become first generation entrepreneurs; existing small businesses, too, will be able to expand their activities. Just as we are banking the un-banked, we are also funding the un-funded.

35. A significant part of the working capital requirement of a MSME arises due to long receivables realization cycles. We are in the process of establishing

an electronic Trade Receivables Discounting System (TReDS) financing of trade receivables of MSMEs, from corporate and other buyers, through multiple financiers. This should improve the liquidity in the MSME sector significantly.

36. Bankruptcy law reform, that brings about legal certainty and speed, has been identified as a key priority for improving the ease of doing business. SICA (Sick Industrial Companies Act) and BIFR (Bureau for Industrial and Financial Reconstruction) have failed in achieving these objectives. We will bring a comprehensive Bankruptcy Code in fiscal 2015-16, that will meet global standards and provide necessary judicial capacity.

37. The Government is committed to increasing access of the people to the formal financial system. In this context, Government proposes to utilize the vast Postal network with nearly 1,54,000 points of presence spread across the villages of the country. I hope that the Postal Department will make its proposed Payments Bank venture successful so that it contributes further to the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana.

38. To bring parity in regulation of Non-Banking Financial Companies (NBFCs) with other financial institutions in matters relating to recovery, it is proposed that NBFCs registered with RBI and having asset size of ₹500 crore and above will be considered for notifications as 'Financial Institution' in terms of the SARFAESI Act, 2002.

From Jan Dhan to Jan Suraksha

39. A large proportion of India's population is without insurance of any kind - health, accidental or life. Worryingly, as our young population ages, it is also going to be pension-less. Encouraged by the success of the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, I propose to work towards creating a universal social security system for all Indians, specially the poor and the under-privileged.

40. The soon-to-be-launched Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna will cover accidental death risk of ₹2 lakh for a premium of just ₹12 per year. Similarly, we will also launch the Atal Pension Yojana, which will provide a defined pension, depending on the contribution, and its period. To encourage people to join this scheme, the Government will contribute 50% of the beneficiaries' premium limited to ₹1,000 each year, for five years, in the new accounts opened before 31st December, 2015.

41. The third Social Security Scheme that I wish to announce is the Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana which covers both natural and accidental death risk of ₹2 lakhs. The premium will be ₹330 per year, or less than one rupee per day, for the age group 18-50.

42. There are unclaimed deposits of about ₹3,000 crore in the PPF, and approximately ₹6,000 crore in the EPF corpus. I have proposed the creation of a Senior Citizen Welfare Fund, in the Finance Bill, for appropriation of these amounts to a corpus which will be used to subsidize the premiums of vulnerable groups such as old age pensioners, BPL card-holders, small and marginal farmers and others. A detailed scheme would be issued in March.

43. Madam Speaker, special regard needs to be paid to the population of senior citizens in the country which is now approximately 10.5 crore, out of which over one crore are above the age of 80 years. 70% live in rural areas and a large number are in the BPL category. A sizeable percentage of them also suffer from age related disabilities. Ours is a society that venerates its elders. I, therefore, propose that a new scheme for providing Physical Aids and Assisted Living Devices for senior citizens, living below the poverty line.

44. In sum, these social security schemes reflect our commitment to utilize the Jan Dhan platform, to ensure that no Indian citizen will have to worry about illness, accidents, or penury in old age. Being sensitive to the needs of the poor, under-privileged and the disadvantaged, my Government also remains committed to the ongoing welfare schemes for the SCs, STs and Women. Despite serious constraints on Union finances, allocations made this year are as follows:

SC	₹ 30,851 crore
ST	₹ 19,980 crore
Women	₹ 79,258 crore

45. An integrated education and livelihood scheme called 'Nai Manzil' will be launched this year to enable Minority Youth who do not have a formal school-leaving certificate to obtain one and find better employment. Further, to show-case civilization and culture of the Parsis, the Government will support, in 2015-16, an exhibition, 'The Everlasting Flame'. The allocation for the Ministry of Minority Affairs is being protected. The BE for the year 2015-16 is ₹3,738 crore.

Infrastructure

46. Madam, it is no secret that the major slippage in the last decade has been on the infrastructure front. Our infrastructure does not match our growth ambitions. There is a pressing need to increase public investment. I have, therefore, increased outlays on both the roads and the gross budgetary support to the railways, by ₹14,031 crore, and ₹10,050 crore respectively. The CAPEX of the public sector units is expected to be ₹ 3,17,889 crore, an increase of approximately ₹80,844 crore over RE 2014-15. In fact, all told, investment in infrastructure will go up by ₹70,000 crore in the year 2015-16, over the year 2014-15 from the Centre's Funds and resources of CPSEs.

47. Secondly, I intend to establish a National Investment and Infrastructure Fund (NIIF), and find monies to ensure an annual flow of ₹ 20,000 crore to it. This will enable the Trust to raise debt, and in turn, invest as equity, in infrastructure finance companies such as the IRFC and NHB. The infrastructure finance companies can then leverage this extra equity, many fold. Thirdly, I also intend to permit tax free infrastructure bonds for the projects in the rail, road and irrigation sectors. Fourth, the PPP mode of infrastructure development has to be revisited, and revitalised. The major issue involved is rebalancing of risk. In infrastructure projects, the sovereign will have to bear a major part of the risk without, of course, absorbing it entirely.

48. Fifth, I also intend to establish, in NITI, the Atal Innovation Mission (AIM). AIM will be an Innovation Promotion Platform involving academics, entrepreneurs, and researchers and draw upon national and international experiences to foster a culture of innovation, R&D and scientific research in India. The platform will also promote a network of world-class innovation hubs and Grand Challenges for India. Initially, a sum of ₹ 150 crore will be earmarked for this purpose.

49. India has a well regarded and world-class IT industry with revenues of about US\$ 150 billion, over US\$ 100 billion of exports, employing nearly 40 lakh people directly. We are now seeing a growing interest in start-ups. Experimenting in cutting edge technologies, creating value out of ideas and initiatives and converting them into scalable enterprises and businesses is at the core of our strategy for engaging our youth and for inclusive and sustainable growth of the country. Concerns such as a more liberal system of raising global capital, incubation facilities in our Centres of Excellence, funding for seed capital and

growth, and ease of Doing Business etc. need to be addressed to create lakh of jobs and hundreds of billion dollars in value.

50. With this objective, Government is establishing a mechanism to be known as SETU (Self-Employment and Talent Utilisation). SETU will be a Techno-Financial, Incubation and Facilitation Programme to support all aspects of start-up businesses, and other self-employment activities, particularly in technology-driven areas. I am setting aside ₹ 1,000 crore initially in NITI Aayog for this purpose.

51. As the success of so-called minor ports has shown, ports can be an attractive investment possibility for the private sector. Ports in the public sector need to both attract such investment as well as leverage the huge land resources lying unused with them. To enable us to do so, ports in public sector will be encouraged, to corporatize, and become companies under the Companies Act.

52. Madam Speaker, investors spend a large amount of time and resources on getting the multiple permissions required. We aim towards ease of doing in India. I have myself launched the e-Biz Portal which integrates 14 regulatory permissions at one source. Good States are embracing and joining this platform. However, if we really want to create jobs, we have to make India an investment destination which permits the start of a business in accordance with publically stated guidelines and criteria.

53. I intend to appoint an Expert Committee for this purpose to examine the possibility and prepare a draft legislation where the need for multiple prior permissions can be replaced with a pre-existing regulatory mechanism.

54. The Government also proposes to set up 5 new Ultra Mega Power Projects, each of 4000 MWs in the plug-and-play mode. All clearances and linkages will be in place before the project is awarded by a transparent auction system. This should unlock investments to the extent of ₹ 1 lakh crore. The Government would also consider similar plug-and-play projects in other infrastructure projects such as roads, ports, rail lines, airports etc. I am happy to announce that the second unit of Kudankulam Nuclear Power Station will be commissioned in 2015-16.

55. Madam Speaker, I hope to garner some additional resources during the year from tax buoyancy. If I am successful, then over and above the budgetary allocation, I will endeavour to enhance allocations to MGNREGA by ₹ 5,000 crore; Integrated

Child Development Scheme (ICDS) by ₹ 1,500 crore; Integrated Child Protection Scheme (ICPS) by ₹ 500 crore; and the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana by ₹ 3,000 crore; and the initial inflow of ₹ 5,000 crore into the NIIF.

Financial Markets

56. One vital factor in promoting investment in India, including in the infrastructure sector, is the deepening of the Indian Bond market, which we have to bring at the same level as our world class equity market. I intend to begin this process this year by setting up a Public Debt Management Agency (PDMA) which will bring both India's external borrowings and domestic debt under one roof.

57. I also propose to merge the Forwards Markets Commission with SEBI to strengthen regulation of commodity forward markets and reduce wild speculation. Enabling legislation, amending the Government Securities Act and the RBI Act is proposed in the Finance Bill, 2015.

58. Capital Account Controls is a policy, rather than a regulatory, matter. I, therefore, propose to amend, through the Finance Bill, Section-6 of FEMA to clearly provide that control on capital flows as equity will be exercised by the Government, in consultation with the RBI.

59. A properly functioning capital market also requires proper consumer protection. I, therefore, also propose to create a Task Force to establish a sector-neutral Financial Redressal Agency that will address grievances against all financial service providers. I am also glad to inform the House that work assigned to the Task Forces on the Financial Data Management Centre, the Financial Sector Appellate Tribunal, the Resolution Corporation, and the Public Debt Management Agency are progressing satisfactorily. We have also received a large number of suggestions regarding the Indian Financial Code (IFC), which are currently being reviewed by the Justice Srikrishna Committee. I hope, sooner rather than later, to introduce the IFC in Parliament for consideration.

60. Madam, Speaker, this is just the beginning. I have a vision of putting in place a direct tax regime which is internationally competitive on rates, is without exemptions, incentivises savings, and does not realize tax from intermediaries. Such a direct tax regime would match the modernized indirect taxes regime we are putting in place by way of GST, and will bring both greater transparency and greater investments.

61. Madam Speaker the situation with regard to the dormant Employees Provident Fund (EPF) accounts and the claim ratios of ESIs is too well known to be repeated here. It has been remarked that both EPF and ESI have hostages, rather than clients. Further, the low paid worker suffers deductions greater than the better paid workers, in percentage terms.

62. With respect to the Employees Provident Fund (EPF), the employee needs to be provided two options. Firstly, the employee may opt for EPF or the New Pension Scheme (NPS). Secondly, for employees below a certain threshold of monthly income, contribution to EPF should be optional, without affecting or reducing the employer's contribution. With respect to ESI, the employee should have the option of choosing either ESI or a Health Insurance product, recognized by the Insurance Regulatory Development Authority (IRDA). We intend to bring amending legislation in this regard, after stakeholder consultation.

Monetising Gold

63. India is one of the largest consumers of gold in the world and imports as much as 800-1000 tonnes of gold each year. Though stocks of gold in India are estimated to be over 20,000 tonnes, mostly this gold is neither traded, nor monetized. I propose to:

- (i) Introduce a Gold Monetisation Scheme, which will replace both the present Gold Deposit and Gold metal Loan Schemes. The new scheme will allow the depositors of gold to earn interest in their metal accounts and the jewelers to obtain loans in their metal account. Banks/other dealers would also be able to monetize this gold.
- (ii) Also develop an alternate financial asset, a Sovereign Gold Bond, as an alternative to purchasing metal gold. The Bonds will carry a fixed rate of interest, and also be redeemable in cash in terms of the face value of the gold, at the time of redemption by the holder of the Bond.
- (iii) Commence work on developing an Indian Gold Coin, which will carry the Ashok Chakra on its face. Such an Indian Gold Coin would help reduce the demand for coins minted outside India and also help to recycle the gold available in the country.

64. One way to curb the flow of black money is to discourage transactions in cash. Now that a majority of Indians has or can have, a RUPAY debit card. I, therefore, proposes to introduce soon several measures that will incentivize credit or debit card transactions, and disincentivise cash transactions.

Investment

65. Alternate Investment Funds Regulations have been notified by SEBI. Such alternate investment funds provide another vehicle for facilitating domestic investments. Keeping in view the need to increase investments from all sources, I propose to also allow foreign investments in Alternate Investment Funds.

66. To further simplify the procedures for Indian Companies to attract foreign investments, I propose to do away with the distinction between different types of foreign investments, especially between foreign portfolio investments and foreign direct investments, and replace them with composite caps. The sectors which are already on a 100% automatic route would not be affected.

67. The 'Act East' policy of the Government of India endeavours to cultivate extensive economic and strategic relations in South-East Asia. In order to catalyze investments from the Indian private sector in this region, a Project Development Company will, through separate Special Purpose Vehicles (SPVs), set up manufacturing hubs in CMLV countries, namely, Cambodia, Myanmar, Laos and Vietnam.

Safe India

68. My Government is committed to safety and security of women. In order to support programmes for women security, advocacy and awareness, I have decided to provide another ₹ 1,000 crore to the Nirbhaya Fund.

Tourism

69. While India has 25 (twenty five) Cultural World Heritage Sites. These facilities are still deficient and require restoration, including landscape restoration; signage and interpretation centres; parking; access for the differently abled; visitors' amenities, including securities and toilets; illumination and plans for benefiting communities around them. I propose to provide resources to start work along these lines for the following Heritage Sites:

- (i) Churches & Convents of Old Goa
- (ii) Hampi, Karnataka

- (iii) Elephanta Caves, Mumbai
- (iv) Kumbalgarh and other Hill Forts of Rajasthan
- (v) Rani ki Vav, Patan, Gujarat
- (vi) Leh Palace, Ladakh, J&K
- (vii) Varanasi Temple town, UP
- (viii) Jalianwala bagh, Amritsar, Punjab
- (ix) Qutub Shahi Tombs, Hyderabad, Telengana

70. After the success of VISAS on arrival issued to travelers of 43 countries, I propose to increase the countries covered to 150, in stages.

Green India

71. Madam, as environmental degradation hurts the poor more than others, we are committed to make our development process as green as possible. Our de facto 'Carbon Tax' on most petroleum products compares favourably with international norms. With regard to coal, there is a need to find a balance between taxing pollution, and the price of power. However, beginning this year, I intend to start on that journey too. My Government is also launching a Scheme for Faster Adoption and manufacturing of Electric Vehicles (FAME). I am proposing an initial outlay of ₹75 crore for this Scheme in 2015-16. The Ministry of New Renewable Energy has revised its target of renewable energy capacity to 1,75,000 MW till 2022, comprising 100,000 MW Solar, 60,000 MW Wind, 10,000 MW Biomass and 5000 MW Small Hydro.

72. Madam, Speaker, we are putting the scam, scandal and corruption Raj behind us. Malfeasance in public procurement can perhaps be contained by having a procurement law and an institutional structure consistent with the UNCITRAL model. I believe, Parliament needs to take a view soon on whether we need a procurement law, and if so, what shape it should take.

73. On the other hand, disputes arising in public contracts take long to resolve, and the process is very costly too. My Government proposes to introduce a Public Contracts (Resolution of Disputes) Bill to streamline the institutional arrangements for resolution of such disputes.

74. There is also a need, I feel, to tackle the lack of common approach and philosophy in the regulatory

arrangements prevailing even within the different sectors of infrastructure. Our Government, therefore, also proposes to introduce a regulatory reform law that will bring about a cogency of approach across various sectors of infrastructure.

Skill India

75. India is one of the youngest nations in the world with more than 54% of the total population below 25 years of age. Our young people have to be both educated and employable for the jobs of the 21st Century. The Prime Minister has explained how Skill India needs to be closely coordinated with Make in India. Yet today less than 5% of our potential workforce gets formal skill training to be employable and stay employable.

76. We will soon be launching a National Skills Mission through the Skill Development and Entrepreneurship Ministry. The Mission will consolidate skill initiatives spread across several Ministries and allow us to standardize procedures and outcomes across our 31 Sector Skill Councils.

77. With rural population still forming close to 70% of India's population, enhancing the employability of rural youth is the key to unlocking India's demographic dividend. With this in mind, we had launched the Deen Dayal Upadhyay Gramin Kaushal Yojana. ₹ 1,500 crore has been set apart for this scheme. Disbursement will be through a digital voucher directly into qualified student's bank account.

78. This is the year when we will be entering the 100th birth anniversary of Shri Deen Dayalji Upadhyay. The intention of the Government is to celebrate the anniversary of this great nationalist, in a befitting manner. A 100th Birthday Celebration Committee will be announced soon, and adequate resources provided for the celebration.

79. With a view to enable all poor and middle class students to pursue higher education of their choice without any constraint of funds, I propose to set up a fully IT based Student Financial Aid Authority to administer and monitor Scholarship as well Educational Loan Schemes, through the Pradhan Mantri Vidya Lakshmi Karyakram. We will ensure that no student misses out on higher education for lack of funds.

80. Hon'ble Members will remember that in the Budget Speech of July, I had indicated my intention to provide one major Central Institute in each State. In the fiscal year 2015-16, I propose to set up All India Institutes of Medical Sciences in J&K, Punjab,

Tamil Nadu, Himachal Pradesh and Assam. Keeping in view the need to augment Medical Sciences in Bihar, I propose to set up another AIIMS like institution in these States. I propose to set up an IIT in Karnataka, and upgrade Indian School of Mines, Dhanbad into a full-fledged IIT. I also propose to set up a Post Graduate Institute of Horticulture Research and Education in Amritsar. IIMs will be set up in J&K and Andhra Pradesh. In Kerala, I propose to upgrade the existing National Institute of Speech and Hearing to a University of Disability Studies and Rehabilitation. I also propose three new National Institutes of Pharmaceutical Education and Research: in Maharashtra, Rajasthan, and Chattisgarh; and an Institutes of Science and Education Research in Nagaland and Odisha. I also propose to set up a Centre for Film Production, Animation and Gaming in Arunachal Pradesh, for the North-Eastern States; and Apprenticeship Training Institute for Women in Haryana and Uttarakhand.

81. In order to improve the Governance of Public Sector banks, the Government intends to set up an autonomous bank Board Bureau. The Bureau will search and select heads of Public Sector banks and help them in developing differentiated strategies and capital raising plans through innovative financial methods and instruments. This would be an interim step towards establishing a holding and investment Company for Banks.

Digital India

82. Madam, Speaker, I would like to inform the House we are making good progress towards making Digital India. The National Optical Fibre Network Programme (NOFNP) of 7.5 lakh kms. networking 2.5 lakh villages is being further speeded up by allowing willing States to undertake its execution, on reimbursement of cost as determined by Department of Telecommunications. Andhra Pradesh is the first State to have opted for this manner of implementation.

83. As Members are aware, in making their recommendations, the Finance Commission has not distinguished between special category and other states. Moreover, both Bihar and West Bengal are going to be amongst the biggest beneficiaries of the recommendations of the Finance Commission. Yet, the Eastern States have to be given an opportunity to grow even faster. I, therefore, propose to give similar special assistance to Bihar and West Bengal as has been provided by the Government of India in the case

of Government of Andhra Pradesh. As regards Andhra Pradesh and Telengana, the Government is committed to comply with all the legal commitments made to these States at the time of reorganization.

84. In spite of the large increase in devolution to states, which implies reduced fiscal space for the Centre in the same proportion we are committed to the welfare of the poor and the neo-middle class. Keeping this in mind, adequate provision is being made for the schemes for the poor and the dis-advantaged. Illustratively, I have allocated ₹ 68,968 crore to the education sector including mid-day meals, ₹ 33,152 crore to the health sector and ₹ 79,526 crore for rural development activities including MGNREGA, ₹ 22,407 crore for housing and urban development, ₹ 10,351 crore for women and child development, ₹ 4,173 crore for Water Resources and Namami Gange. The significant sums that will be spent by the States on these programmes will ensure a quantum leap in expenditures in these areas. I urge states to utilize their enhanced resources effectively in these areas.

85. Madam, Speaker, I am delighted to report good progress for DMIC corridors: the Ahmedabad-Dhule Investment Region in Gujarat, and the Shendra-Bidkin Industrial Park near Aurangabad, in Maharashtra, are now in a position to start work on basic infrastructure. In the current year, I have earmarked an initial sum of ₹ 1,200 crore. However, as the pace of expenditure picks up, I will provide them additional funds.

86. Defence of every square inch of our mother land comes before anything else. So far, we have been over dependent on imports, with its attendant unwelcome spin-offs. Our Government has already permitted FDI in defence so that the Indian-controlled entities also become manufacturers of defence equipments, not only for us, but for export. We are thus pursuing the Make in India policy to achieve greater self-sufficiency in the area of defence equipment, including aircraft. Members of this august House would have noted that we have been both transparent and quick in making defence equipment related purchase decisions, thus keeping our defence forces ready for any eventuality. This year too, I have provided adequately for the needs of the armed forces. As against likely expenditure of this year of ₹ 2,22,370 crore the budget allocation for 2015-16 is ₹ 2,46,727 crore.

87. While India produces some of the finest financial minds, including in international finance, they have few avenues in India to fully exhibit and exploit their strength to the country's advantage. GIFT in Gujarat was envisaged as International Finance Centre that would actually become as good an International Finance Centre as Singapore or Dubai, which, incidentally, are largely manned by Indians. The proposal has languished for years. I am glad to announce that the first phase of GIFT will soon become a reality. Appropriate regulations will be issued in March.

88. For the quick resolution of commercial disputes, the Government proposes to set up exclusive commercial divisions in various courts in India based on the recommendations of the 253rd Report of the Law Commission. The Government proposes to introduce a Bill in the parliament after consulting stakeholders in this regard.

89. Madam Speaker, the Government will, during this session, also place before the Parliament the required Bills, to convert Ordinances issued by the Government into Acts of Parliament.

BUDGET ESTIMATES

90. I now turn to the Budget Estimates for Budget 2015-16.

91. Non-Plan expenditure estimates for the Financial Year are estimated at ₹13,12,200 crore. Plan expenditure is estimated to be ₹ 4,65,277 crore, which is very near to the R.E. of 2014-15. Total Expenditure has accordingly been estimated at ₹ 17,77,477 crore. The requirements for expenditure on Defence, Internal Security and other necessary expenditures are adequately provided.

92. Gross Tax receipts are estimated to be ₹ 14,49,490 crore. Devolution to the States is estimated to be ₹ 5,23,958 crore. Share of Central Government will be ₹ 9,19,842 crore. Non Tax Revenues for the next fiscal are estimated to be ₹2,21,733 crore.

93. With the above estimates, fiscal deficit will be 3.9 per cent of GDP and Revenue Deficit will be 2.8 per cent of GDP.

PART B

Madam Speaker,

94. I now turn to my tax proposals.

95. Taxation is an instrument of social and economic engineering. Tax collections help the Government to provide education, healthcare, housing and other basic facilities to the people to improve their quality of life and to address the problems of poverty, unemployment and slow development. To achieve these objectives, it has been our endeavour in the last nine months to foster a stable taxation policy and non-adversarial tax administration. A very important dimension to our tax administration is the fight against the scourge of black money. A number of measures have already been taken in this direction. I propose to do much more.

96. We need to revive growth and investment to ensure that more jobs are created for our youth and benefits of development reach millions of our poor. We need an enabling tax policy for this. I have already introduced the Bill to amend the Constitution of India for Goods and Services Tax (GST) in the last Session of this august House. GST is expected to play a transformative role in the way our economy functions. It will add buoyancy to our economy by developing a common Indian market and reducing the cascading effect on the cost of goods and services. We are moving in various fronts to implement GST from the next year.

97. We need to match this transformative piece of legislation in indirect taxation with transformative measures in direct taxation. The basic rate of Corporate Tax in India at 30% is higher than the rates prevalent in the other major Asian economies, making our domestic industry uncompetitive. Moreover, the effective collection of Corporate Tax is about 23%. We lose out on both counts, i.e. we are considered as having a high Corporate Tax regime but we do not get that tax due to excessive exemptions. A regime of exemptions has led to pressure groups, litigation and loss of revenue. It also gives room for avoidable discretion. I, therefore, propose to reduce the rate of Corporate Tax from 30% to 25% over the next 4 years. This will lead to higher level of investment, higher growth and more jobs. This process of reduction has to be necessarily accompanied by rationalisation and removal of various kinds of tax exemptions and incentives for corporate taxpayers, which incidentally account for a large number of tax disputes.

98. I wanted to start the phased reduction of corporate tax rate and phased elimination of exemptions right away; but I thought it would be appropriate to give advance notice that these changes will start from the next financial year. Our stated policy is to avoid sudden surprises and instability in tax policy. Exemptions to individual taxpayers will, however, continue since they facilitate savings which get transferred to investment and economic growth.

99. While finalising my tax proposals, I have adopted certain broad themes, which include:

- A. Measures to curb black money;
- B. Job creation through revival of growth and investment and promotion of domestic manufacturing and 'Make in India';
- C. Minimum government and maximum governance to improve the ease of doing business;
- D. Benefits to middle class taxpayers;
- E. Improving the quality of life and public health through Swachh Bharat initiatives; and
- F. Stand alone proposals to maximise benefits to the economy.

100. Madam Speaker, the first and foremost pillar of my tax proposals is to effectively deal with the problem of black money which eats into the vitals of our economy and society. The problems of poverty and inequity cannot be eliminated unless generation of black money and its concealment is dealt with effectively and forcefully.

101. In the last 9 months several measures have been initiated in this direction. A major breakthrough was achieved in October, 2014 when a delegation from the Revenue Department visited Switzerland and the Swiss authorities agreed to (a) provide information in respect of cases independently investigated by the Income-tax Department; (b) confirm genuineness of bank accounts and provide non-banking information; (c) provide such information in a time bound manner; and (d) commence talks with India for Automatic Exchange of Information between the two countries at the earliest. Investigation into cases of undisclosed foreign assets has been accorded the highest priority, resulting in detection of substantial amounts of unreported income. For strengthening collection of information from various sources domestically, a new structure

is being put in place which includes electronic filing of statements by reporting entities. This will ensure seamless integration of data and more effective enforcement.

102. Tracking down and bringing back the wealth which legitimately belongs to the country is our abiding commitment to the country. Recognising the limitations under the existing legislation, we have taken a considered decision to enact a comprehensive new law on black money to specifically deal with such money stashed away abroad. To this end, I propose to introduce a Bill in the current Session of the Parliament.

103. With your permission, Madam Speaker, I would like to highlight some of the key features of the proposed new law on black money.

- (1) Concealment of income and assets and evasion of tax in relation to foreign assets will be prosecutable with punishment of rigorous imprisonment upto 10 years. Further,
 - this offence will be made non-compoundable;
 - the offenders will not be permitted to approach the Settlement Commission; and
 - penalty for such concealment of income and assets at the rate of 300% of tax shall be levied.
- (2) Non filing of return or filing of return with inadequate disclosure of foreign assets will be liable for prosecution with punishment of rigorous imprisonment up to 7 years.
- (3) Income in relation to any undisclosed foreign asset or undisclosed income from any foreign asset will be taxable at the maximum marginal rate. Exemptions or deductions which may otherwise be applicable in such cases, shall not be allowed.
- (4) Beneficial owner or beneficiary of foreign assets will be mandatorily required to file return, even if there is no taxable income.
- (5) Abettors of the above offences, whether individuals, entities, banks or financial

institutions will be liable for prosecution and penalty.

- (6) Date of Opening of foreign account would be mandatorily required to be specified by the assessee in the return of income.
- (7) The offence of concealment of income or evasion of tax in relation to a foreign asset will be made a predicate offence under the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (PMLA). This provision would enable the enforcement agencies to attach and confiscate unaccounted assets held abroad and launch prosecution against persons indulging in laundering of black money.
- (8) The definition of 'proceeds of crime' under PMLA is being amended to enable attachment and confiscation of equivalent asset in India where the asset located abroad cannot be forfeited.
- (9) The Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA) is also being amended to the effect that if any foreign exchange, foreign security or any immovable property situated outside India is held in contravention of the provisions of this Act, then action may be taken for seizure and eventual confiscation of assets of equivalent value situated in India. These contraventions are also being made liable for levy of penalty and prosecution with punishment of imprisonment up to five years.

104. As regards curbing domestic black money, a new and more comprehensive Benami Transactions (Prohibition) Bill will be introduced in the current session of the Parliament. This law will enable confiscation of benami property and provide for prosecution, thus blocking a major avenue for generation and holding of black money in the form of benami property, especially in real estate.

105. A few other measures are also proposed in the Budget for curbing black money within the country. The Finance Bill includes a proposal to amend the Income-tax Act to prohibit acceptance or payment of an advance of ₹ 20,000 or more in cash for purchase of immovable property. Quoting of PAN is being made mandatory for any purchase or sale

exceeding the value of ₹1 lakh. The third party reporting entities would be required to furnish information about foreign currency sales and cross border transactions. Provision is also being made to tackle splitting of reportable transactions. To improve enforcement, CBDT and CBEC will leverage technology and have access to information in each other's database.

106. Madam Speaker, the second pillar of my taxation proposals this year is job creation through revival of growth and investment and promotion of domestic manufacturing and 'Make in India'. I propose to undertake a series of steps in this direction to attract capital, both domestic and foreign. Tax 'pass through' is proposed to be allowed to both Category-I and Category-II Alternative Investment Funds, so that tax is levied on the investors in these Funds and not on the Funds per se. This will step up the ability of these Funds to mobilise higher resources and make higher investments in small and medium enterprises, infrastructure and social projects and provide the much required private equity to new ventures and start-ups.

107. A step was taken in the last Budget to encourage Real Estate Investment Trusts (REITs) and Infrastructure Investments Trusts (InvITs) by providing partial pass through to them. These collective investment vehicles have an important role to revive construction activity. A large quantum of funds is locked up in various completed projects which need to be released to facilitate new infrastructure projects to take off. I therefore propose to rationalise the capital gains regime for the sponsors exiting at the time of listing of the units of REITs and InvITs, subject to payment of Securities Transaction Tax (STT). The rental income of REITs from their own assets will have pass through facility.

108. The present taxation structure has an inbuilt incentive for fund managers to operate from offshore locations. To encourage such offshore fund managers to relocate to India, I propose to modify the Permanent Establishment (PE) norms to the effect that mere presence of a fund manager in India would not constitute PE of the offshore funds resulting in adverse tax consequences.

109. Implementation of the General Anti Avoidance Rule (GAAR) has been a matter of public debate. The investment sentiment in the country has now turned positive and we need to accelerate this momentum. There are also certain contentious issues

relating to GAAR which need to be resolved. It has therefore been decided to defer the applicability of GAAR by two years. Further, it has also been decided that when implemented, GAAR would apply prospectively to investments made on or after 01.04.2017.

110. Today I see a lot of young entrepreneurs running business ventures or wanting to start new ones. They need latest technology. Therefore, to facilitate technology inflow to small businesses at low costs, I propose to reduce the rate of income tax on royalty and fees for technical services from 25% to 10%.

111. To generate greater employment opportunities, it is proposed to extend the benefit of deduction for employment of new regular workmen to all business entities. The eligibility threshold of minimum 100 regular workmen is being reduced to fifty.

112. The role of indirect taxes is also very important in the context of promotion of domestic manufacturing and Make in India. In indirect taxes, therefore, I propose to reduce the rates of basic customs duty on certain inputs, raw materials, intermediates and components (in all 22 items) so as to minimise the impact of duty inversion and reduce the manufacturing cost in several sectors. Some other changes address the problem of CENVAT credit accumulation due to the levy of SAD. I propose to fully exempt all goods, except populated printed circuit boards for use in manufacture of ITA bound items from SAD and reduce the SAD on imports of certain other inputs and raw materials subject to actual user condition. These changes are detailed in the Annexure to the Budget Speech.

113. My next proposal is regarding minimum government and maximum governance with focus on ease of doing business and simplification of Tax Procedures without compromising on tax revenues. The total wealth tax collection in the country was ₹1,008 crore in 2013-14. Should a tax which leads to high cost of collection and a low yield be continued or should it be replaced with a low cost and higher yield tax? The rich and wealthy must pay more tax than the less affluent ones. I have therefore decided to abolish the wealth tax and replace it with an additional surcharge of 2% on the super-rich with a taxable income of over ₹1 crore. This will lead to tax simplification and enable the Department to focus more on ensuring tax compliance and widening the tax base. As against a tax sacrifice of ₹1,008 crore,

through these measures the Department would be collecting about ₹ 9,000 crore from the 2% additional surcharge. Further, to track the wealth held by individuals and entities, the information regarding the assets which are currently required to be furnished in wealth-tax return will be captured in the income tax returns. This will ensure that the abolition of wealth tax does not lead to escape of any income from the tax net.

114. The provision relating to indirect transfers in the Income-tax Act which is a legacy from the previous government contains several ambiguities. This provision is being suitably cleaned up. Further, concerns regarding applicability of indirect transfer provisions to dividends paid by foreign companies to their shareholders will be addressed by the Central Board of Direct Taxes through a clarificatory circular. These changes would eliminate the scope for discretionary exercise of power and provide a hassle free structure to the taxpayers. I reiterate what I had said in the last Budget that ordinarily retrospective tax provisions adversely impact the stability and predictability of the taxation regime and resort to such provisions shall be avoided.

115. Further, to reduce the associated hassles to smaller taxpayers and the compliance costs in domestic transfer pricing, I propose to increase the threshold limit from ₹ 5 crore to ₹ 20 crore.

116. In order to rationalise the MAT provisions for FIIs, profits corresponding to their income from capital gains on transactions in securities which are liable to tax at a lower rate, shall not be subject to MAT.

117. The Tax Administration Reform Commission (TARC) has given a number of recommendations to improve the administration in the Tax Departments. These recommendations are in advanced stage of examination and will be appropriately implemented during the course of this year.

118. As part of the movement towards GST, I propose to subsume the Education Cess and the Secondary and Higher Education Cess in Central Excise duty. In effect, the general rate of Central Excise Duty of 12.36% including the cesses is being rounded off to 12.5%. I also propose to revise the specific rates of Central Excise duty in certain other commodities, as detailed in the Annexure. However, in the case of petrol and diesel such specific rates are being revised only to the extent of subsuming the quantum of education cess presently levied on them,

keeping the total incidence of excise duties unchanged. The ad-valorem rates of excise duty lower than 12% and those higher than 12% with a few exceptions are not being increased. Some changes are also being made to excise levy on cigarettes and the compounded levy scheme applicable to pan masala, gutkha and certain other tobacco products.

119. To give a boost to domestic leather footwear industry, the excise duty on footwear with leather uppers and having retail price of more than ₹1000 per pair is being reduced to 6%.

120. To further facilitate the ease of doing business, online central excise and service tax registration will be done in two working days. The assessee under these taxes will be allowed to issue digitally signed invoices and maintain electronic records. These measures will cut down lot of paper work and red tape. Time limit for taking CENVAT credit on inputs and input services is being increased from six months to one year as a measure of business facilitation.

121. Introduction of GST is eagerly awaited by Trade and Industry. To facilitate a smooth transition to levy of tax on services by both the Centre and the States, it is proposed to increase the present rate of service tax plus education cesses from 12.36% to a consolidated rate of 14%.

122. Madam Speaker, cleanliness of households and clean environment are very important social causes. The fourth pillar of my taxation proposals this year therefore relates to initiatives for the Swachh Bharat Abhiyan. In my direct tax proposals, I have proposed 100% deduction for contributions, other than by way of CSR contributions, to the Swachh Bharat Kosh. A similar tax treatment is also proposed for the Clean Ganga Fund.

123. In indirect taxes, I propose to increase the Clean Energy Cess from ₹100 to ₹200 per metric tonne of coal, etc. to finance clean environment initiatives. Excise duty on sacks and bags of polymers of ethylene other than for industrial use is being increased from 12% to 15%. It is also proposed to have an enabling provision to levy Swachh Bharat Cess at a rate of 2% or less on all or certain services if need arises. This Cess will be effective from a date to be notified. Resources generated from this cess will be utilised for financing and promoting initiatives towards Swachh Bharat.

124. It is also proposed to exempt services by common affluent treatment plants from service tax.

The concessions from customs and excise duties currently available on specified parts for manufacture of electrically operated vehicles and hybrid vehicles are being extended by one more year i.e. up to 31.3.2016.

125. Madam Speaker, the fifth pillar of my taxation proposals this year is extension of benefits to middle class tax payers. The proposals in this regard are as follows :

- > Increase in the limit of deduction in respect of health insurance premium from ₹15,000 to ₹25,000.
 - o For senior citizens the limit will stand increased to ₹30,000 from the existing ₹20,000.
 - o For very senior citizens of the age of 80 years or more, who are not covered by health insurance, deduction of ₹ 30,000 towards expenditure incurred on their treatment will be allowed.
- > The deduction limit of ₹ 60,000 towards expenditure on account of specified diseases of serious nature is proposed to be enhanced to ₹80,000 in case of very senior citizens.
- > Additional deduction of ₹ 25,000 will be allowed for differently abled persons under Section 80DD and Section 80U of the Income-tax Act.
- > The limit on deduction on account of contribution to a Pension Fund and the New Pension Scheme is proposed to be increased from ₹1 lakh to ₹1.5 lakh.
- > To provide social safety net and the facility of pension to individuals, an additional deduction of ₹ 50,000 is proposed to be provided for contribution to the New Pension Scheme under Section 80CCD. This will enable India to become a pensioned society instead of a pensionless society.
- > Investments in Sukanya Samriddhi Scheme is already eligible for deduction under Section 80C. All payments to the beneficiaries including interest payment on deposit will also be fully exempt.

- > Transport allowance exemption is being increased from ₹800 to ₹1,600 per month.
- > For the benefit of senior citizens, service tax exemption will be provided on Varishta Bima Yojana.

126. Madam Speaker, I am giving these concessions to individual taxpayers despite inadequate fiscal space. After taking into account the tax concession given to middle class tax payers in my last Budget and this Budget, today an individual tax payer will get tax benefit of ₹ 4,44,200 as detailed in the annexure. As and when my fiscal capacity improves, individual taxpayers will have a lot to look forward to.

127. Madam Speaker, there are several stand-alone proposals relating to taxation. These include conversion of existing excise duty on petrol and diesel to the extent of ₹ 4 per litre into Road Cess to fund investment in roads and other infrastructure. An additional sum of ₹ 40,000 crore will be made available through this measure for these sectors. In service tax, exemption is being extended to certain pre cold storage services in relation to fruits and vegetables so as to incentivise value addition in this crucial sector. The Negative List under service tax is being slightly pruned and certain other exemptions are being withdrawn to widen the tax base.

128. Yoga is India's well acknowledged gift to the world. It is proposed to include yoga within the ambit of charitable purpose under Section 2(15) of the Income-tax Act. Further, to mitigate the problem being faced by many genuine charitable institutions, it is proposed to modify the ceiling on receipts from activities in the nature of trade, commerce or business to 20% of the total receipts from the existing ceiling of ₹25 lakh. A national database of non profit organisations is also being developed.

129. Enactment of a Direct Taxes Code (DTC) has been under discussion for quite some time. Most of the provisions of the DTC have already been included in the Income-tax Act. Among the very few aspects of DTC which were left out, we have addressed some of the issues in the present Budget. Further, the jurisprudence under the Income-tax Act is well evolved. Considering all these aspects, there is no great merit in going ahead with the Direct Tax Code as it exists today.

130. Madam Speaker, the details of direct and

indirect tax proposals are given in the Annexure to the Budget speech and the other budget documents laid on the Table of the House. My direct tax proposals would result in revenue loss of ₹8,315 crore, whereas the proposals in indirect taxes are expected to yield ₹23,383 crore. Thus, the net impact of all tax proposals would be revenue gain of ₹15,068 crore.

CONCLUSION

131. To conclude, Madam Speaker, it is no secret that expectations of this Budget have been high. People who urge us to undertake Big Bang Reforms, also say that the Indian economy is a giant super tanker, or an elephant. An elephant, Madam Speaker, moves slowly but surely. Even our worst critics would admit that we have moved rapidly. In this speech, I think I have clearly outlined not only what we are going to do immediately, but also a roadmap for the future.

132. I think I can genuinely stake, for our Government, a claim of intellectual honesty. We have been consistent in what we have said, and what we are doing. We are committed, Madam Speaker, to achieving what we have been voted to power for: Change, growth, jobs and genuine, effective upliftment of the poor and the under-privileged. Our commitment to the 'Daridra Narayan' is steadfast, as is commitment to the Constitutional principles of Equality and Justice for All, without concern for caste, creed or religion. This will be in the spirit of the Upanishad-inspired mantra:

Om Sarve Bhavantu Sukhinah

Sarve Santu Nir-Aamayaaah

Sarve Bhadraanni Pashyantu

Maa Kashcid-Duhkha-Bhaag-Bhavet

Om Shaantih Shaantih Shaantih

(OM! May All Be Happy

May All Be Free From Illness

May All See What is Beneficial

May No One Suffer)

133. With these words, Madam Speaker, I commend the Budget to the House.

ANNEXURE

- **Allocation of Natural Resources:** Auction of coal, reform in the mining sector to see that resources are used for development of the country and its people;

- **Financial Inclusion:** through the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana-making every Indian a part of the financial system;
- **Health and hygiene of the common man:** Launched a successful campaign of Swachh Bharat to ensure cleanliness, leading to better productivity and well being of the poor;
- **Girl Child & their Education:** Started a drive for constructing toilets in the remaining elementary schools and also Launched the Beti Bachao-Beti Padhao campaign;
- **Creation of Employment for the Youth:** Launched the 'Make in India' campaign and combined it with a detailed process and policy re-engineering to make India a Global Manufacturing Hub for creation of job opportunities for millions of youth;
- **Hassle Free Business Environment:** Created a non-adversarial tax regime, ending tax terrorism; Secured the political agreement on the goods and services tax (GST), that will allow legislative passage of the constitutional amendment bill;
- **Delivery of benefits to the poor made efficient:** Started direct transfer of cooking gas subsidy on a national scale by use of technology;
- **Attracting Investment to create Jobs:** Increased FDI caps in defence, Insurance and Railway Infrastructure; rationalised the conditions for FDI in construction and medical devices sectors;
- **Expanding the job market and ensuring welfare of the labour:** Facilitated States which work to improve its Labour Laws and brought systemic changes in the area through the umbrella programme of 'Shrameva Jayate';
- **Better agri-productivity; more income to farmers:** Launched the programme for Soil Health cards for better productivity in agriculture;
- **Energising the country:** Brought rapid growth in power sector inspite of uncertainty on the coal front and launched ambitious programmes for new and renewable energy;
- **Technology-from grass root to the Space:** Launched the Digital India programme to make India a knowledge & innovation based society with Broadband connectivity being taken to all villages, Success of Mars Orbiter Mission;
- **Skill India programme:** Created a separate Ministry for skill development which is about to launch a massive programme;
- **Efficiency & better work culture in Government:** Brought a culture of responsibility without fear, and with efficiency and transparency; created an environment of trusting the citizens-encouraging self-certification in a number of areas;
- **Red tape to Red carpet:** Ending the red tape, created the 'Ease of Doing Business' in India by reforming and rationalising a large number of procedures, rules and regulations;
- **North-eastern part of the country brought in the mainstream:** North East given special priority in the development process by two visits of PM and launch of important infrastructure projects;
- **Pride in the Nation and its culture:** Brought out India's cultural and spiritual strength through UNO's recognition for Yoga, Namami Gange, Ghat and heritage city development programmes.

ANNEXURE TO PART-B OF THE BUDGET SPEECH

The Finance Bill, 2015 proposes to make amendments in the Income-tax Act, 1961, Wealth-tax Act, 1957, Excise Tariff Act, Customs Act, Finance Act, 1994 and Finance (No.2) Act, 2004. A gist of the main amendments is given below:-

Direct Taxes

2. Rates of tax

- 2.1 It is proposed that there will be no change in the rate of personal income-tax and the rate of tax for companies in respect of income earned in the financial year 2015-16, assessable in the assessment year 2016-17.

- 2.2 It is further proposed to levy a surcharge @ 12% on individuals, HUFs, AOPs, BOIs, artificial juridical persons, firms, cooperative societies and local authorities having income exceeding ₹ 1 crore. Surcharge in the case of domestic companies having income exceeding ₹ 1 crore and upto ₹ 10 crore is proposed to be levied @ 7% and surcharge @ 12% is proposed to be levied on domestic companies having income exceeding ₹ 10 crore.
- 2.3 It is further proposed that in the case of foreign companies the surcharge will continue to be levied @2% if the income exceeds ₹ 1 crore and is upto ₹ 10 crore, and @5% if the income exceeds ₹ 10 crore.
- 2.4 It is also proposed to levy a surcharge @12% as against current rate of 10% on additional income-tax payable by companies on distribution of dividends and buyback of shares, or by mutual funds and securitisation trusts on distribution of income.
- 2.5 The education cess on income-tax @ 2% for fulfilment of the commitment of the Government to provide and finance universalised quality based education and 1% of additional surcharge called 'Secondary and Higher Education Cess' on tax and surcharge is proposed to be continued for the financial year 2015-16 for all taxpayers.

3. **A. Measures to curb black money**

- 3.1 With a view to curbing the generation of black money in real estate, it is proposed to amend the provisions of section 269SS and 269T of the Income-tax Act so as to prohibit acceptance or re-payment of advance in cash of ₹ 20,000 or more for any transaction in immovable property. It is also proposed to provide a penalty of an equal amount in case of contravention of such provisions.
- 3.2 Offence of making false declaration/ documents in the transaction of any business relating to Customs (section 132 of the Customs Act) to be predicate offence under PMLA to curb trade based money laundering.

4. **B. Job creation through revival of growth and investment and promotion of domestic 'manufacturing' and 'Make in India'.**

- 4.1 Taking into account the representations received from various stakeholders and international developments in this regard, it is proposed to defer applicability of General Anti Avoidance Rule (GAAR) by 2 years. Accordingly, it is proposed to be applicable for income of the financial year 2017-18 (A.Y. 2018-19) and subsequent years. It is also proposed that the investments made upto 31.03.2017 shall not be subjected to GAAR.
- 4.2 With a view to streamline the taxation regime of Alternative Investment Funds (AIFs), it is proposed to provide pass through status to all the sub-categories of category-I and also to category-II AIFs governed by the regulations of Securities and Exchange Board of India (SEBI).
- 4.3 With a view to facilitate relocation of fund managers of offshore funds in India, it is proposed to modify the permanent establishment (PE) norms.
- 4.4 With a view to give effect to the provisions of section 94 of the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014, it is proposed to provide an additional investment allowance (@15%) and additional depreciation (@15%) to new manufacturing units set-up during the period 01.04.2015 to 31.03.2020 in notified areas of Andhra Pradesh and Telangana.
- 4.5 In respect of Real Estate Investment Trusts (REITs) and Infrastructure Investment Trusts (INVITs), it is proposed to provide that the sponsor will be given the same treatment on offloading of units at the time of listing as would have been available to him if he had offloaded his shareholding of special purpose vehicle (SPV) at the stage of direct listing. Further, the rental income arising from real estate assets directly held by the REIT is also proposed to be allowed to pass through and to be taxed in the hands of the unit holders of the REIT.
- 4.6 It is proposed to amend the provisions of section 194LD of the Income-tax Act so as to extend the period of applicability of reduced rate of tax at 5% in respect of income of foreign investors (FIIs and QFIs) from corporate bonds and government securities, from 31.5.2015 to 30.06.2017.
- 4.7 With a view to obviate the problems faced

by small companies and to facilitate the inflow of technology, it is proposed to amend the provisions of section 115A of the Income-tax Act so as to reduce the rate of tax on royalty and fees for technical services from 25% to 10%.

- 4.8 With a view to facilitating generation of employment, it is proposed to amend the provisions of section 80JJAA of the Income-tax Act so as to provide that tax benefit under the said section shall be available to a 'person' deriving profits from manufacture of goods in a factory and paying wages to new regular workmen. The eligibility threshold of minimum 100 workmen is proposed is to be reduced to fifty.

- 4.9 Additional depreciation @ 20% is allowed on new plant and machinery installed by a manufacturing unit or a unit engaged in generation and distribution of power. However, if the asset is installed after 30th September of the previous year only 10% of the additional depreciation is allowed. It is proposed to allow the remaining 10% of the additional depreciation in the subsequent previous year.

5. **C. Minimum government and maximum governance to improve the ease of doing business**

- 5.1 Section 9 of the Income-tax Act was amended by Finance Act, 2012 to clarify that if an asset, being a share of, or interest, in a company or an entity derives its value, directly or indirectly, substantially from an asset situated in India, the gain arising from transfer of such share or interest shall be taxable in India. After the clarificatory amendment, a large number of representations were received from various quarters seeking clarification on certain terms used in the amended provisions. An Expert Committee was also constituted to look into the concerns. Taking into account the recommendations made by the Expert Committee and the concerns raised by the various stakeholders, it is proposed to amend the provisions of the Income-tax Act so as to provide that:-

- the share or interest shall be deemed to derive its value substantially from the assets located in India, if on the

specified date, the value of such assets represents at least fifty per cent of the fair market value of all the assets owned by the company or entity. However, the indirect transfer provisions would not apply if the value of Indian assets does not exceed ₹ 10 crore. Further, the principle of proportionality will apply to the taxation of gains arising from indirect transfer of Indian assets.

- the Indian entity shall be obligated to furnish information relating to the offshore transactions having the effect of directly or indirectly modifying the ownership structure or control of the Indian company or entity. In case of non-compliance, a penalty is also proposed.
- the indirect transfer provisions shall not apply in a case where the transferor of share or interest in a foreign entity, along with his associated enterprises, neither holds the right of control or management nor holds voting power or share capital or interest exceeding five percent of the total voting power or total share capital in the foreign company or entity, directly or indirectly, holding the Indian assets.
- the capital gains shall be exempt in respect of transfer of share of a foreign company deriving its value, directly or indirectly, substantially from the shares of an Indian company, under a scheme of amalgamation or demerger.

- 5.2 It is proposed to amend the provisions of section 92BA of the Income-tax Act so as to increase the threshold limit for applicability of transfer pricing regulations to specified domestic transactions from ₹5 crore to ₹20 crore.

- 5.3 It is proposed to amend the provisions of section 2(15) of the Income-tax Act so as to include 'yoga' as a specific category of activity in the definition of 'charitable purpose' and also to provide relief for activities in the nature of business undertaken by genuine

- charitable organizations subject to the condition that aggregate receipts from such activity is less than 20% of the total receipts.
- 5.4 It is proposed to exempt the income of Core Settlement Guarantee Fund established by Clearing Corporations as per mandate of SEBI.
- 5.5 It is proposed to amend the provisions of section 255 of the Income-tax Act so as to increase the monetary limit from ₹ 5 lakh to ₹ 15 lakh, for a case to be heard by a Single Member Bench of the ITAT.
- 5.6 It is proposed to amend the provisions of the Income-tax Act so as to provide tax neutrality on transfer of units of a scheme of a Mutual Fund under the process of consolidation of schemes of Mutual Funds as per SEBI Regulations, 1996.
- 5.7 It is proposed to amend the provisions of the Income-tax Act so as to provide a mechanism to pre-empt the repetitive appeals by the revenue in the same assessee's case on the same question of law year after year.
- 5.8 It is proposed to empower the Board to prescribe rules for grant of relief in respect of taxes paid in foreign jurisdictions.
- 5.9 It is proposed to abolish the levy of Wealth-tax with effect from 2016-17 (Assessment Year) for reducing the compliance burden on the tax payers. The revenue loss on account of such abolition is proposed to be compensated by increase in the existing surcharge by 2% in case of domestic companies and all non corporate taxpayers.
- 5.10 With a view to rationalise the dispute resolution mechanism available to taxpayer in the form of Settlement Commission, it is proposed to provide that while making an application to the Settlement Commission for an assessment year which has been re-opened by the Assessing Officer, the assessee can make an application for other assessment years in which the proceedings could be re-opened provided the return of income for such assessment years has been furnished by the assessee.
- 6. D. Improving the quality of life and public health through Swachh Bharat Initiatives**
- 6.1 It is proposed to provide that the donations (other than the CSR contributions made in accordance with section 135 of the Companies Act, 2013) made to Swachh Bharat Kosh (by both resident and non-resident) and Clean Ganga Fund (by resident) shall be eligible for 100% deduction under section 80G of the Income-tax Act.
- 7. E. Benefits to middle class taxpayers**
- With a view to encourage savings and to promote health care among individual taxpayers, a number of measures are proposed to be taken by way of incentives under the Income-tax Act. The same are enumerated below:-
- 7.1 It is proposed to provide that investment in Sukanya Samriddhi Scheme will be eligible for deduction u/s 80C and any payment from the scheme shall not be liable to tax.
- 7.2 It is proposed to increase the limit of deduction u/s 80D of the Income-tax Act from ₹ 15,000 to ₹ 25,000 on health insurance premium (in case of senior citizen from ₹ 20,000 to ₹ 30,000). It is also proposed to allow deduction of expenditure of similar amount in case of a very senior citizen not eligible to take health insurance.
- 7.3 It is proposed to increase the limit of deduction in case of very senior citizens u/s 80DDB of the Income-tax Act on expenditure on account of specified diseases from ₹ 60,000 to ₹ 80,000.
- 7.4 It is proposed to increase the limit of deduction u/s 80DD of the Income-tax Act in respect of maintenance, including medical treatment of a dependant who is a person with disability, from ₹ 50,000 to ₹ 75,000. It is also proposed to increase the limit of deduction from ₹ 1 lakh to ₹ 1.25 lakh in case of severe disability.
- 7.5 It is proposed to increase the limit of deduction u/s 80U of the Income-tax Act in case of a person with disability, from ₹ 50,000 to ₹ 75,000. It is also proposed to increase the limit of deduction from ₹ 1 lakh to ₹ 1.25 lakh in case of severe disability.

- 7.6 It is proposed to increase the limit of deduction u/s 80CCC of the Income-tax Act on account of contribution to a pension fund of LIC or IRDA approved insurer from ₹1 lakh to ₹ 1.5 lakh.
- 7.7 It is proposed to increase the limit of deduction u/s 80CCD of the Income-tax Act on account of contribution by the employee to National Pension Scheme (NPS) from ₹ 1 lakh to ₹ 1.50 lakh. It is also proposed to provide a deduction of upto ₹ 50,000 over and above the limit of ₹ 1.50 lakh in respect of contributions made to NPS.
- 7.8 It is proposed to amend the provisions of section 197A of the Income-tax Act so as to provide the facility of filing self-declaration of non-deduction of tax by the recipients of taxable maturity proceeds of life insurance policy.
- 7.9 Under the existing provisions of the Income-tax Act, an individual buying an immovable property from a resident is required to deduct tax but is not required to obtain TAN for depositing the tax so deducted. With a view to extend the same facility to an individual or HUF purchasing an immovable property from a non-resident, it is proposed to relax the requirement of obtaining TAN by the individual or HUF who is required to deduct tax on acquisition of immovable property from a non-resident.
- 7.10 It is proposed to provide that donation made to National Fund for Control of Drug Abuse (NFCDA) shall be eligible for 100% deduction under section 80G of the Income-tax Act.
- 7.11 Details of tax deductions referred to in para 99.

· Deduction u/s 80C	₹1,50,000
· Deduction u/s 80CCD	₹50,000
· Deduction on account of interest on house property loan (Self occupied property)	₹2,00,000
· Deduction u/s 80D on health insurance premium	₹25,000
· Exemption of transport allowance	₹19,200
Total	₹4,44,200

8. F. Stand alone proposals to maximise benefits to the economy

- 8.1 It is proposed to provide for chargeability of interest paid by a permanent establishment (PE) or a branch of foreign bank to its Head Office (HO) and other overseas branches under the source rule of taxation and for treating the PE or branch as a taxable entity for computation of income and for purpose of levy of TDS.
- 8.2 With a view to providing a uniform method of computation of period of stay in Indian for the purposes of determination of 'resident' status in the case of a India seafarer, whether working on a Indian-ship or foreign-ship, it is proposed to provide an enabling power to CBDT to prescribe the same in the rules.
- 8.3 In search cases, it is proposed to allow seized cash to be adjusted towards the assessee's tax liability under his settlement application.
- 8.4 With a view to ensuring proper deduction of tax on payments made to non-residents, it is proposed to amend the provisions of section 195 of the Income-tax Act so as to provide for enabling power to the CBDT for capturing information about prescribed foreign remittances which are claimed to be not chargeable to tax.

INDIRECT TAXES

A. Job creation through revival of growth and investment and promotion of domestic manufacturing and 'Make in India'.

CUSTOMS

I. Reduction in duty on certain inputs to address the problem of duty inversion:

- 1) 'Metal parts' for use in the manufacture of electrical insulators.
- 2) Ethylene-Propylene-non-conjugated-Diene Rubber (EPDM), Water blocking tape and Mica glass tape for use in the manufacture of insulated wires and cables.
- 3) Magnetron upto 1 KW for use in the manufacture of microwave ovens.
- 4) C- Block for Compressor, Over Load

- Protector (OLP) & Positive thermal co-efficient and Crank Shaft for compressor, for use in the manufacture of Refrigerator compressors.
- 5) Zeolite, ceria zirconia compounds and cerium compounds for use in the manufacture of washcoats, which are further used in manufacture of catalytic converters.
 - 6) Anthraquinone for manufacture of hydrogen peroxide.
 - 7) Sulphuric acid for use in the manufacture of fertilizers.
 - 8) Parts and components of Digital Still Image Video Camera capable of recording video with minimum resolution of 800x600 pixels, at minimum 23 frames per second, for at least 30 minutes in a single sequence, using the maximum storage (including the expanded) capacity.

II. Reduction in Basic Customs Duty to reduce the cost of raw materials:

- 1) Ethylene dichloride (EDC), vinyl chloride monomer (VCM) and styrene monomer (SM) from 2.5% to 2%.
- 2) Isoprene and Liquefied butanes from 5% to 2.5%.
- 3) Butyl acrylate from 7.5% to 5%.
- 4) Ulexite ore from 2.5% to Nil.
- 5) Antimony metal, antimony waste and scrap from 5% to 2.5%.
- 6) Specified components for use in the manufacture of specified CNC lathe machines and machining centres from 7.5% to 2.5%.
- 7) Certain specified inputs for use in the manufacture of flexible medical video endoscopes from 5% to 2.5%.
- 8) HDPE for use in the manufacture of telecommunication grade optical fibre cables from 7.5% to Nil.
- 9) Black Light Unit Module for use in the manufacture of LCD/LED TV panels from 10% to Nil.
- 10) Organic LED (OLED) TV panels from 10% to Nil.

- 11) CVD and SAD are being fully exempted on specified raw materials [battery, titanium, palladium wire, eutectic wire, silicone resins and rubbers, solder paste, reed switch, diodes, transistors, capacitors, controllers, coils (steel), tubing (silicone)] for use in the manufacture of pacemakers.
- 12) Evacuated Tubes with three layers of solar selective coating for use in the manufacture of solar water heater and system to Nil.
- 13) Active Energy Controller (AEC) for use in the manufacture of Renewable Power System (RPS) Inverters to 5%, subject to certification by MNRE.
- 14) Parts, components and accessories (falling under any Chapter) for use in the manufacture of tablet computers and their sub-parts for use in manufacture of parts, components and accessories are being fully exempted from BCD, CVD and SAD.

III. Reduction in SAD to address the problem of CENVAT credit accumulation:

- 1) All goods except populated PCBs, falling under any Chapter of the Customs Tariff, for use in manufacture of ITA bound goods from 4% to Nil.
- 2) Naphtha, ethylene dichloride (EDC), vinyl chloride monomer (VCM) and styrene monomer (SM) for manufacture of excisable goods from 4% to 2%.
- 3) Metal scrap of iron & steel, copper, brass and aluminium from 4% to 2%.
- 4) Inputs for use in the manufacture of LED drivers and MCPCB for LED lights, fixtures and LED lamps from 4% to Nil.

IV. Increase in Basic Customs Duty:

- 1) Metallurgical coke from 2.5% to 5%.
- 2) Tariff rate on iron & steel and articles of iron or steel, falling under Chapters 72 and 73 of the Customs Tariff, from 10% to 15%. However, there is no change in the existing effective rates of basic customs duty on these goods.

- 3) Tariff rate on Commercial Vehicles from 10% to 40% and effective rate from 10% to 20%. However, customs duty on commercial vehicles in Completely Knocked Down (CKD) kits and electrically operated vehicles including those in CKD condition will continue to be at 10%.

V. Miscellaneous:

- 1) Export duty on upgraded ilmenite is being reduced from 5% to 2.5%.
- 2) Excise duty structure for mobiles handsets including cellular phones is being changed from 1% without CENVAT credit or 6% with CENVAT credit to 1% without CENVAT credit or 12.5% with CENVAT credit.
- 3) Excise duty structure of 2% without CENVAT credit or 12.5% with CENVAT credit is being prescribed for tablet computers.
- 4) Basic Customs Duty on Digital Still Image Video Camera capable of recording video with minimum resolution of 800x600 pixels, at minimum 23 frames per second, for at least 30 minutes in a single sequence, using the maximum storage (including the expanded) capacity is being reduced to Nil. Basic Customs Duty on parts and components of these cameras is also being reduced from 5% to Nil.
- 5) Concessional customs duty structure of Nil Basic Customs Duty, 6% CVD and Nil SAD on specified parts of electrically operated vehicles and hybrid vehicles, presently available upto 31.03.2015, is being extended upto 31.03.2016.

EXCISE

I. Excise duty structure on certain goods is being restructured as follows:

- 1) Wafers for use in the manufacture of integrated circuit (IC) modules for smart cards from 12% to 6%.
- 2) Inputs for use in the manufacture of LED drivers and MCPCB for LED lights, fixtures and LED lamps from 12% to 6%.

- 3) Mobiles handsets, including cellular phones from 1% without CENVAT credit or 6% with CENVAT credit to 1% without CENVAT credit or 12.5% with CENVAT credit. NCCD of 1% on mobile handsets including cellular phones remains unchanged.

- 4) Tablet computers from 12% to 2% without CENVAT credit or 12.5% with CENVAT credit.

- 5) Specified raw materials [battery, titanium, palladium wire, eutectic wire, silicone resins and rubbers, solder paste, reed switch, diodes, transistors, capacitors, controllers, coils (steel), tubing (silicone)] for use in the manufacture of pacemakers to Nil.

- 6) Pig iron SG grade and Ferro-silicon-magnesium for use in the manufacture of cast components of wind operated electricity generators to Nil, subject to certification by MNRE.

- 7) Solar water heater and system from 12% to Nil without CENVAT credit or 12.5% with CENVAT credit.

- 8) Round copper wire and tin alloys for use in the manufacture of Solar PV ribbon for manufacture of solar PV cells to Nil subject to certification by Department of Electronics and Information Technology (DeitY).

II. Miscellaneous:

- 1) Excise duty on leather footwear (footwear with uppers made of leather of heading 4107 or 4112 to 4114) of Retail Sale Price of more than ₹ 1000 per pair from 12% to 6%.
- 2) Excise duty levied on the value of duty paid on rails for manufacture of railway or tramway track construction material is being exempted retrospectively for the period from 17.03.2012 to 02.02.2014, if no CENVAT credit of duty paid on such rails is availed.

B. Minimum government and maximum governance to improve the ease of design business

I. Reduction in number of levies:**EXCISE**

- 1) Education Cess and Secondary & Higher Education Cess leviable on excisable goods are being subsumed in Basic Excise duty. Consequently, Education Cess and Secondary & Higher Education Cess leviable on excisable goods are being fully exempted. The standard ad valorem rate of Basic Excise Duty is being increased from 12% to 12.5% and specific rates of Basic Excise Duty on petrol, diesel, cement, cigarettes & other tobacco products (other than biris) are being suitably changed. However, the total incidence of various duties of excise on petrol and diesel remains unchanged. Other Basic Excise Duty rates (ad valorem as well as specific) with a few exceptions are not being changed. Customs Education Cesses will continue to be levied on imported goods.

II. Ensure certainty and uniformity in valuation of the goods for the purposes of levy of excise duty:

- 1) All goods falling under Chapter sub-heading 2101 20, including iced tea, are being notified under section 4A of the Central Excise Act for the purpose of assessment of Central Excise duty with reference to the Retail Sale Price with an abatement of 30%. Such goods are also being included in the Third Schedule to the Central Excise Act, 1944.
- 2) Goods, such as lemonade and other beverages, are being notified under section 4A of the Central Excise Act for the purpose of assessment of Central Excise duty with reference to the Retail Sale Price with an abatement of 35%. Such goods are also being included in the Third Schedule to the Central Excise Act, 1944.

III. Compliance Facilitation:

- 1) Online Central Excise/Service Tax Registration within two working days.
- 2) Time limit for taking CENVAT Credit on inputs and input services is being increased from six months to one year.

- 3) Facility of direct dispatch of goods by registered, dealer from seller to customer's premises is being provided. Similar facility is also being allowed in respect of job-workers. Registered importer can also send goods directly to customer from the port of importation.
- 4) Penalty provisions in Customs, Central Excise & Service Tax are being rationalized to encourage compliance and early dispute resolution.
- 5) Central Excise/Service Tax assesseees are being allowed to issue digitally signed invoices and maintain other records electronically.

IV. Miscellaneous:

- 1) The entry "waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured" in the Seventh Schedule to the Finance Act, 2005 related to levy of additional duty of excise @ 5% is being omitted. Till the enactment of the Finance Bill, 2015, the said additional duty of excise of 5% leviable on such goods is being exempted. Simultaneously, the Basic Excise Duty on these goods is being increased from 12% to 18%.
- 2) Excise duty on chassis for ambulances is being reduced from 24% to 12.5%.

C. Improving the quality of life and public health through Swachh Bharat Initiatives.**CUSTOMS & EXCISE**

- 1) The Scheduled rate of Clean Energy Cess levied on coal, lignite and peat is being increased from ₹100 per tonne to ₹300 per tonne. The effective rate of Clean Energy Cess is being increased from ₹100 per tonne to ₹200 per tonne.
- 2) Concessional customs and excise duty rates on specified parts of Electrically Operated Vehicles and Hybrid Vehicles, presently available upto 31.03.2015, is being extended upto 31.03.2016.
- 3) Excise duty on sacks and bags of polymers of ethylene other than for industrial use is being increased from 12% to 15%.

SERVICE TAX

- 1) An enabling provision is being made to empower the Central Government to impose a Swachh Bharat Cess on all or certain taxable services at a rate of 2% on the value of such taxable services. The proceeds from this Cess would be utilized for Swachh Bharat initiatives. This Cess will be effective from a date to be notified.
- 2) Service provided by a Common Effluent Treatment Plant operator for treatment of effluent is being exempted.

D. Stand alone proposals to maximise benefits to the economy**D.I Broadening the Tax Base:****EXCISE**

- 1) Excise duty of 2% without CENVAT credit or 6% with CENVAT credit is being levied on condensed milk put up in unit containers. It is also being notified under section 4A of the Central Excise Act for the purpose of valuation with reference to the Retail Sale Price with an abatement of 30%.
- 2) Excise duty of 2% without CENVAT credit or 6% with CENVAT credit is being levied on peanut butter.

SERVICE TAX**I. Change in Service Tax rates:**

- 1) The **service tax rate** is being increased from 12% plus Education Cesses to 14%. The 'Education Cess' and 'Secondary and Higher Education Cess' shall be subsumed in the new service tax rate. The revised rate shall come into effect from a date to be notified.

II. Review of the Negative List

- 1) Service tax to be levied on the service provided by way of access to amusement facility such as rides, bowling alleys, amusement arcades, water parks, theme parks, etc.
- 2) Service tax to be levied on service by way of admission to entertainment event of concerts, non-recognized sporting events, pageants, music concerts and

award functions, if the amount charged for admission is more than Rs 500. Service by way of admission to exhibition of the cinematographic film, circus, dance, or theatrical performances including drama, ballets or recognized sporting events shall continue to be exempt.

- 3) Service tax to be levied on service by way of carrying out any processes as job work for production or manufacture of alcoholic liquor for human consumption.
- 4) An enabling provision is being made to exclude all services provided by the Government or local authority to a business entity from the Negative List. Once this amendment is given effect to, all service provided by the Government to business entities, unless specifically exempt, shall become taxable.

III. Review of General Exemptions

- 1) Exemption presently available on specified services of construction, repair of civil structures, etc. when provided to Government shall be restricted only to,-
 - a) a historical monument, archaeological site
 - b) canal, dam or other irrigation work;
 - c) pipeline, conduit or plant for (i) water supply (ii) water treatment, or (iii) sewerage treatment or disposal.
- 2) Exemption to construction, erection, commissioning or installation of original works pertaining to an airport or port is being withdrawn.
- 3) Exemption to services provided by a performing artist in folk or classical art form of (i) music, or (ii) dance, or (iii) theater, will be limited only to such cases where amount charged is upto Rs 1,00,000 per performance (except brand ambassador).
- 4) Exemption to transportation of 'food stuff' by rail, or vessels or road will be limited to transportation of food grains including rice and pulses, flours, milk and salt only. Transportation of agricultural produce is separately exempt which

- would continue.
- 5) Exemptions are being withdrawn on the following services:
 - (a) services provided by a mutual fund agent to a mutual fund or assets management company;
 - (b) distributor to a mutual fund or AMC; and
 - (c) selling or marketing agent of lottery ticket to a distributor of lottery.
 - 6) Exemption is being withdrawn on the following services,-
 - (a) Departmentally run public telephone
 - (b) Guaranteed public telephone operating only local calls
 - (c) Service by way of making telephone calls from free telephone at airport and hospital where no bill is issued
 - 7) Existing exemption notification for service provided by a commission agent located outside India to an exporter located in India is being rescinded, as this notification has become redundant in view of the amendments made in law in the previous budget, whereby services provided by such agents have been excluded from the tax net.

D.II Relief Measures:

CUSTOMS

- 1) Exempt artificial heart (left ventricular assist device) from Basic Customs Duty of 5% and CVD.

EXCISE

- 1) Full exemption from excise duty is being extended to captively consumed intermediate compound coming into existence during the manufacture of Agarbattis. Agarbattis attract Nil excise duty.

SERVICE TAX

- 1) Services of pre-conditioning, pre-cooling, ripening, waxing, retail packing, labeling

- of fruits and vegetables are being exempted.
- 2) Life insurance service provided by way of Varishtha Pension Bima Yojna is being exempted.
- 3) Service provided by way of exhibition of movie by the exhibitor/theatre owner to the distributor or association of persons consisting of exhibitor as one of its member is being exempted.
- 4) All ambulance services provided to patients are being exempted.
- 5) Service provided by way of admission to a museum, zoo, national park, wild life sanctuary and a tiger reserve is being exempted.
- 6) Transport of goods for export by road from the factory to a land customs station (LCS) is being exempted.

D.III Allocation of additional resources for infrastructure:

EXCISE & CUSTOMS

- 1) The Scheduled rates of Additional Duty of Customs / Excise levied on Petrol and High Speed Diesel Oil [commonly known as Road Cess] are being increased from ₹ 2 per litre to ₹8 per litre. The effective rates of Additional Duty of Customs / Excise levied on Petrol and High Speed Diesel Oil [commonly known as Road Cess] are being increased from ₹2 per litre to ₹6 per litre. Simultaneously, Basic Excise Duty Rates on Petrol and High Speed Diesel Oil (both branded and unbranded) are being reduced by ₹4 per litre. Basic Excise duty rates on petrol and diesel are also being increased suitably so as to subsume Education Cess and Secondary and Higher Education Cess presently levied on them. Thus, the net decrease in Basic Excise Duty on branded petrol is ₹3.46 per litre, on unbranded petrol is ₹3.49 per litre, on branded diesel is ₹3.63 per litre and on unbranded diesel is ₹3.70 per litre. **However, total incidence of excise duties on petrol and diesel remains unchanged.**

D.IV Promote public health:

EXCISE

- 1) Excise duty on cigarettes is being increased by 25% for cigarettes of length not exceeding 65 mm and by 15% for cigarettes of other lengths. Similar increases are proposed on cigars, cheroots and cigarillos.
- 2) Maximum speed of packing machine is being specified as a factor relevant to production for determining excise duty payable under the Compounded Levy Scheme presently applicable to pan masala, gutkha and chewing tobacco. Accordingly, deemed production and duty payable per machine per month are being notified with reference to the speed range in which the maximum speed of a packing machine falls.

D.V Other measures relating to Service Tax**1. Changes in the Finance Act, 1994**

1. A definition of the term “government” is being incorporated in the Act to resolve interpretational issues as regards the scope of this term in the context of the Negative List and service tax exemptions.
2. To amend the definition of term “service” to specifically state the intention of legislature to levy service tax on:
 - i. chit fund foremen by way of conducting a chit; and
 - ii. distributor or selling agent of lottery, as appointed or authorized by the organizing state for promoting, marketing, distributing, selling, or assisting the state in any other way for organizing and conducting a lottery.
3. It is being specifically prescribed in the Act that value of a taxable service shall include any reimbursable cost or expenditure incurred and charged by the service provider to make legal position clear and avoid disputes.
4. Section 66F of the Act prescribes that unless otherwise specified, reference to a service shall not include reference to any input service used for providing such

service. An illustration is being incorporated in this section to exemplify the scope of this provision.

2. Rationalization of abatement

1. A uniform abatement is being prescribed for transport by rail, road and vessel to bring parity in these sectors. Service Tax shall be payable on 30% of the value of such service subject to a uniform condition of non-availment of Cenvat Credit on inputs, capital goods and input services. Presently, tax is payable on 30% of the value in case of rail transport, 25% in case of road transport and 40% in case of transport by vessels.
2. The abatement for executive (business/first class) air travel, wherein the service element is higher, is being reduced from 60% to 40%. Consequently, service tax would be payable on 60% of the value of fare for business class.
3. Abatement is being withdrawn on chit fund service.

3. Service Tax Rules

1. In respect of any service provided under aggregator model, the aggregator is being made liable to pay service tax if the service is provided using the brand name of aggregator in any manner.
2. Consequent to the upward revision in Service Tax rate, the composition rate on specified services, namely, life insurance service, services of air travel agent, money changing service provided by banks or authorized dealers, and service provided by lottery distributor and selling agent, is proposed to be revised proportionately.

4. Reverse charge mechanism

1. Manpower supply and security services when provided by individual, HUF, partnership firm to a body corporate are being brought to full reverse charge as a simplification

measure. Presently, these are taxed under partial reverse charge mechanism.

2. Services provided by mutual fund agents, mutual fund distributors and lottery agents are being brought to under reverse charge consequent to withdrawal of exemption on such services.

amended to allow credit of service tax paid under partial reverse charge by the service receiver without linking it to the payments of value of service to service provider as a trade facilitation measure.

Dr. RAJAT BHARGAVA, Jt. Secy. (Budget)

5. The Cenvat Credit Rules, 2004

Cenvat Credit Rules are being